

# चुनाव से पहले ही राहुल हार गए



लोकसभा चुनाव के नतीजे 16 मई को आने वाले हैं, लेकिन देश का राजनीतिक माहौल दीवार पर लिखी इबारत की तरह यह संकेत दे रहा है कि यूपीए सरकार की हार निश्चित है. कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव के बीच मैदान छोड़कर भाग रहे हैं. हार की वजह यूपीए सरकार के दौरेन भ्रष्टाचार, महंगाई और घोटाले हैं. विकास के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की बातों पर लोगों को अब भरोसा नहीं रहा. राहुल गांधी खुद को एक नेता के रूप में साबित करने में विफल रहे हैं. राहुल गांधी की सबसे बड़ी चूक यह है कि वह युवाओं का भरोसा नहीं जीत सके. राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती न देना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल है. नरेंद्र मोदी को वॉक-ओवर देकर कांग्रेस ने भाजपा विरोधियों को निराश किया, साथ ही इस वजह से मुसलमानों का वोट बंट गया. राहुल गांधी ने मोदी का सामना न करके खुद को एक हारा हुआ योद्धा साबित किया है.



मनीष कुमार

**कां** ग्रेस पार्टी का कैंपेन एक शर्मनाक स्थिति में है. राहुल गांधी लोगों की नज़र में चुनाव से पहले ही हार चुके हैं. उनके भाषणों से लोगों में कोई विश्वास नहीं जगता है. वह एक ही तरह की बात हर रैली में कहते हैं, इसलिए जब उनका भाषण टीवी पर दिखाया जाता है, तो लोग चैनल बदल लेते हैं. अगर नरेंद्र मोदी की रैली साथ में होती है, तो टीवी चैनल वाले ही राहुल की आवाज़ बंद कर देते हैं. राहुल की साख एक नेता की नहीं बन सकी. राहुल गांधी किसानों का दिल नहीं जीत सके. देश के मज़दूर और दलित भी उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं. मुसलमानों में भी वह अपना स्थान नहीं बना पाए हैं और देश के युवाओं के बीच वह एक मजाक बनकर रह गए हैं. यही वजह है कि राहुल गांधी की रैली में अब लोग नहीं आते हैं. कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब वह बोलने के लिए उठे, तो लोग रैलियां छोड़कर जाने लगे. राहुल गांधी न तो आम जनता को जीत सके और न कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का हौसला बढ़ा सके. कांग्रेस के कई नेता तो चुनाव से पहले ही कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की भविष्यवाणी करने लगे हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता रसातल में कैसे चली गई. चुनाव से पहले ही पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता हताश और निराश हो चुके हैं. ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है या यूँ कहें कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को वॉक-ओवर दे दिया है.

सवाल यह है कि कांग्रेस

पार्टी से आखिर चूक कहां हुई, वह इस हालत में पहुंची कैसे?

पिछले 10-12 सालों से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को एक यूथ आइकन यानी एक युवा नेता के रूप में पेश करने की कोशिश में लगी रही. हर दो साल पर राहुल गांधी के सक्रिय राजनीति में आने की मांग उठती रही. राहुल गांधी का प्रचार होता रहा. राहुल गांधी के सक्रिय राजनीति में आने का मामला ऐसा हुआ, जैसे पहले आप-पहले आप के चक्कर में ट्रेन छूट जाती है. राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आंखें तब खुलीं, जब ट्रेन छूट चुकी थी. आखिरकार, पिछले साल जयपुर के कार्यक्रम में उन्हें कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष घोषित किया गया, लेकिन यहां भी उन्होंने यह कह दिया कि सत्ता जहर है. अब पता नहीं कि राहुल के उस भाषण को किसने लिखा था. राजनीतिक दल के लिए अगर सत्ता जहर है, तो उन्हें समाजसेवी संस्था बना देना चाहिए. अगर सत्ता जहर है, तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए. कहने का मतलब यह कि राहुल गांधी का अपना इमेज मेकओवर और कैंपेन संशय से ग्रसित रहा. इस संशय का दूसरा उदाहरण राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न बनाना है. कांग्रेस पार्टी यह समझ नहीं सकी कि देश की जनता मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री से ऊब चुकी है. उसे एक सक्रिय और निर्णायक प्रधानमंत्री चाहिए. पिछले दस

सालों में राहुल गांधी यह साबित नहीं कर सके हैं कि वह एक निर्णायक व्यक्तित्व हैं. यही वजह है कि लोगों की नज़रों में वह प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी में नरेंद्र मोदी से काफी पीछे छूट गए. इतने पीछे कि कोई प्रचार अभियान उसकी पूर्ति नहीं कर सकता.

वैसे कांग्रेस पार्टी का प्रचार अभियान भी अजीब है. किसी भी पोस्टर और वीडियो में कांग्रेस पार्टी ने लोगों से यह अपील तक नहीं की है कि कांग्रेस को वोट दें या हाथ के निशान पर बटन दबाएं. कांग्रेस का प्रचार अभियान पूरी तरह से गैर-राजनीतिक है. सवाल यह है कि कांग्रेस के वे अक्लमंद लोग कौन हैं, जिन्होंने ऐसे प्रचार की रूपरेखा तैयार की है. पहले जब सोनिया गांधी के हाथ में कमान थी, तो हर योजना पर चर्चा होती थी. भाषण में क्या होगा, नारे क्या होने चाहिए, वीडियो कैसा बनाना है, रैलियों का आयोजन कैसे होगा, उम्मीदवारों को कैसे चुना जाएगा, समाजसेवी संगठनों को कैसे इस्तेमाल करना है, मीडिया को कैसे मैनेज करना है, इन सब बातों पर चर्चा होती थी और फिर रणनीति बनती थी. सोनिया गांधी के आसपास राजनीतिक लोग थे, जो टीवी पर नज़र नहीं आते थे. वे जमीनी स्तर पर फैसले को लागू करने में माहिर थे. इसलिए हर रणनीति कामयाब होती थी. राहुल गांधी के

(शेष पृष्ठ 2 पर)

**यूपीए सरकार के मंत्री पिछले दो-तीन सालों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सबजबाग दिखाते रहे. यह भरोसा दिलाते रहे कि सरकार की नीतियों की वजह से कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी. जब मौका आया, तो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए. क्या कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा गुट तैयार हो चुका है, जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता है?**



**घर का डॉक्टर**

प्रकृति के अनमोल तत्वों द्वारा तैयार किया गया आयुर्वेदिक तेल राहत रुह औषधियुक्त जड़ी-बूटियों का सशक्त मिश्रण है।

- सर दर्द
- जले कटे एवं चर्म रोग
- बदन दर्द
- चक्कर आना (समलवाई)
- जोड़ों के दर्द
- दिमाग की कमजोरी
- सर्दी जुकाम
- अनिद्रा में लाभकारी

वर्ष 1881 से निरन्तर सेवा में

तिल के तेल से निर्मित

अब पाउच पैकिंग में भी

अन्य उत्कृष्ट उत्पाद

**आयुर्वेद रुक्मिणी**

सुपर डबल तेल

**सुखान**

बुद्धता और गुणवत्ता कलांगी

**Herbal Shampoo**

Anti Hair Fall

**Rahat Rook**

100% PURE COCONUT OIL

**हरबंशराम भगवानदास आयुर्वेदिक संस्थान प्रा.लि.**

website: www.harbanashram.com Customer Care No.- 08447 427 621

जनरल मर्चेन्ट एवं केमिस्ट शॉप में भी उपलब्ध

कितने असरदार रह गए हैं इमाम बुखारी?

**03**

1952 से अब तक...

**04**

कांग्रेस और भाजपा में कांटे की जंग

**07**

साई की महिमा

**12**

# चुनाव से पहले ही राहुल गांधी हार गए

## पृष्ठ एक का शेष

पार्टी के केंद्र में आते ही कांग्रेस के कई अनुभवी नेता निर्णायक भूमिका से दूर चले गए. राहुल गांधी अपने कुछ खास लोगों से घिरे हुए हैं. ये वही लोग हैं, जिनकी वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का विनाश हो गया. राहुल के खास सलाहकारों में कनिष्क सिंह, मोहन सिंह, मोहन प्रकाश, मधुसूदन मिस्त्री, के जे राव एवं संजय झा जैसे लोग हैं. इनमें से किसी ने ज़मीनी स्तर की राजनीति नहीं की. ये विचारक हैं, टीवी पर बहस करते हैं और ज़मीनी स्तर पर पार्टी कार्यक्रम नहीं करा सकते. इन लोगों की न तो राजनीतिक सोच है और न इनके पास राजनीतिक अनुभव है.

ऐसे ही सलाहकारों ने चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार और प्रोपेगंडा के तूफानी हमले की योजना बनाई. राहुल गांधी को योजना बताई गई, राहुल गांधी ने हां कर दी. पता चला कि यह तूफानी हमला कांग्रेस संगठन के लोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए विदेशी एजेंसियों को चुना गया. प्रचार का काम अमेरिकी कंपनी बरसन-मार्शल और जापानी कंपनी देन्तसू को दिया गया. इस काम के लिए कांग्रेस पार्टी ने 700 करोड़ रुपये दिए, ताकि होर्डिंस, पोस्टर, रेडियो, अखबारों और टीवी चैनलों के जरिये प्रचार हो सके. इनका काम मनमोहन सरकार की उपलब्धियों का प्रचार और राहुल गांधी का इमेज-मेकओवर करना था, ताकि लोग कांग्रेस को भाजपा से बेहतर मानें और वोट दें. चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले ही देश भर में प्रचार-प्रसार का काम शुरू हो गया. एक कांग्रेस नेता ने बताया कि इन एजेंसियों की पहली योजना मनमोहन सरकार के खिलाफ नकारात्मक प्रचार को निष्पत्ती बनाना था और उसके बाद राहुल का सकारात्मक प्रचार करके उनकी छवि निखारना था. पहली योजना के तहत इन एजेंसियों ने मनरेगा, फूड सिक्वोरिटी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, यूआईडी एवं आरटीआई जैसे कई मुद्दों का प्रचार किया, लेकिन उस प्रचार को देखकर लोगों का रिएक्शन उल्टा हो गया. मनरेगा भ्रष्टाचार की वजह से सबसे बदनाम योजना बनकर रह गई है, किसी को कैश मिला नहीं, यूआईडी को लेकर भी संशय बना हुआ है. विपक्ष ने सिर्फ इतना कहकर कि कांग्रेस पार्टी उन कामों का भी श्रेय लेना चाह रही है, जो अभी हुए ही नहीं हैं, प्रचार की हवा निकाल दी. इन्हीं कंपनियों के जरिये अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ के अनंन गोस्वामी के साथ इंटरव्यू रखा गया. उस एक इंटरव्यू ने राहुल गांधी को जो नुकसान पहुंचाया, उसकी भरपाई 700 करोड़ रुपये लेने वाली ये एजेंसियां अभी तक नहीं कर सकी हैं. इसके बाद इन कंपनियों द्वारा राहुल के इमेज मेकओवर की सारी योजना विफल हो गई. मोदी के सामने राहुल एक नौसिखिया ही बने रहे. कांग्रेस पार्टी ने राहुल की मार्केटिंग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल हो गई. राहुल गांधी का यह कहना कि भाजपा मार्केटिंग करने में एक्सपर्ट है, इस बात की पुष्टि करता है कि जो 700 करोड़ रुपये उन्होंने दो विदेशी कंपनियों को दिए, वे बेकार साबित हुए. राहुल गांधी को यह बात समझ में नहीं आई कि अगर पार्टी के ही अनुभवी नेताओं को 700 करोड़ रुपये देकर प्रचार की ज़िम्मेदारी सौंपी गई होती, तो आज उनकी भी मोदी के टक्कर की मार्केटिंग हो गई होती. आज वह मोदी को चुनौती देते नज़र आते. लेकिन, सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि राहुल गांधी की सारी मार्केटिंग और प्रचार योजना विफल हो गई.

यूपीए के 10 सालों को आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास के एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाएगा. मनमोहन सरकार ने खुद को एक झूठी, भ्रष्ट, जनविरोधी और आज़ाद भारत की सबसे बदनाम सरकार के रूप में स्थापित किया. उसने संसद और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने का कीर्तिमान स्थापित किया. देश की जनता यह मानती है कि यूपीए सरकार आज़ाद भारत की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ऐतिहासिक महंगाई और बेरोज़गारी देखी गई. किसानों ने सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं कीं. यूपीए सरकार के दौरान एक-एक करके कई सारे प्रजातांत्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता ही नष्ट कर दी गई. मीडिया में पिछले तीन सालों से यूपीए



फोटो-प्रभात पाण्डेय

सरकार सिर्फ घोटालों और अकर्मण्यता के लिए चर्चा में रही. मनमोहन सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए और उनकी सरकार फ़ैसला न लेने वाली सरकार के नाम से मशहूर हो गई. पहली बार कैबिनेट मंत्रियों को जेल जाना पड़ा. पहली बार किसी घोटाले में शक की सूई प्रधानमंत्री पर पड़ी. यह सब कम था, तो बाकी काम महंगाई और बेरोज़गारी ने कर दिया. लोग नाराज़ थे. दो साल पहले से ही कांग्रेस पार्टी को यह अंदाज़ा था कि 2014 आसान नहीं होने वाला है. अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के आंदोलन में जिस तरह से लोगों ने हिस्सेदारी की, वह कांग्रेस के खिलाफ जनविरोध का प्रमाण था. कांग्रेस पार्टी के नेता सब देख रहे थे, सरकार देख रही थी, सबके सामने एक सबसे बड़ी

चुनौती थी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की चुनौती. कांग्रेस गांधी परिवार की पार्टी है. यह सबको पता था कि 2014 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा. इसके लिए यूपीए सरकार और कांग्रेस के मंत्रियों ने क्या कोई तैयारी कर रखी थी?

दो साल पहले सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत के दौरान कई जानकारियां मिलीं. पता चला कि कांग्रेस पार्टी का 2014 का चुनाव जीतने का फॉर्मूला क्या है. उन्होंने बताया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य आधार कार्ड बनवाना है. इसके बाद डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम लागू की जाएगी. कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह मानना था कि अगर लोगों के बैंक एकाउंट में सीधे पैसा जाने लगेगा, तो सारी नाराज़गी खत्म हो जाएगी. सरकार चुनाव जीतने के लिए फूड सिक्वोरिटी बिल लेकर आएगी, जिसके तहत देश की बहुमत आबादी को मुफ्त में खाने का सामान मुहैया कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि आधार कार्ड बनने और इन योजनाओं को लागू करने के बाद देश के सभी जनकल्याण कार्यक्रमों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से जोड़ा जाएगा. सारी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और उसके बदले वह पैसा सीधे लोगों के बैंक एकाउंट में डाल दिया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि मीडिया चीखता-चिल्लाता रह जाएगा, एक्सपर्ट बोलते रह जाएंगे कि यह देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाएगी. हालांकि, ये योजनाएं तो फूलप्रफ थीं, इसमें कोई शक नहीं कि अगर सरकार इन योजनाओं पर अमल करती और इन्हें लागू कर देती, तो कांग्रेस की हालत आज कुछ और होती. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ. जो मंत्री इन योजनाओं को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार थे, वे आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. उन्होंने चुनाव न लड़ने का फ़ैसला किया है. इसलिए यह सवाल पूछना लाज़िमी है कि क्या यूपीए सरकार के इन मंत्रियों ने किसी साज़िश के तहत इन योजनाओं को लागू नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपीए सरकार के मंत्री पिछले दो-तीन सालों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सब्जबाग दिखाते रहे, यह भरोसा दिलाते रहे कि कांग्रेस इन नीतियों की वजह से आसानी से चुनाव जीत जाएगी? और जब मौक़ा आया, तो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए. कहीं ऐसा तो नहीं कि मनमोहन सिंह ने इस योजनाओं को अधर में लटका दिया, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया कि प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी आखिरी पारी है. इसके अलावा, क्या कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा गुट तैयार हो चुका है, जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता है?

सरकार की नाकामी और उसके खिलाफ लोगों की नाराज़गी थी. ऐसे में राहुल गांधी के लिए जो रणनीति चाहिए थी, वह विदेशी कंपनियों नहीं बना सकीं. वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से यह गलती हुई कि वह पिछले पांच सालों से संगठन मजबूत करना है, संगठन मजबूत करना है, की रट ही लगाते रह गए. नतीजा यह निकला कि वह न तो संगठन मजबूत कर सके और न ही चुनाव जीत सके. राहुल गांधी एवं उनकी टीम की देखरेख में जिन-जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. बिहार और उत्तर प्रदेश की हार ने राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन हाल में हुए विधानसभा चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में मिली जबरदस्त हार ने यह साबित कर दिया कि राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता नहीं है. यही वजह है कि देश का युवा वर्ग यह मानता है कि राहुल गांधी एक असफल व्यक्ति हैं, जो अपने परिवार के साथे में राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचे हैं. राहुल गांधी 43 साल के हो चुके हैं. युवा भी नहीं रहे, लेकिन राहुल गांधी के पास अपनी योग्यता और दर्शन को साबित करने के लिए कोई सुबूत नहीं है. लोगों को बताने के लिए राहुल के पास उनकी सफलता की कोई कहानी नहीं है. इतने सालों तक लोकसभा में रहने के बावजूद उनका एक भी भाषण ऐसा नहीं है, जिसे लोग याद कर सकें. हां, कभी-कभी जब उनकी जुबान फिसलती है, तो वह वीडियो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर काफी पॉपुलर हो जाता है. वैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं और राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी की वैवाहिक स्थिति पर राजनीति करके यह संकेत दे दिया है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार चुकी है. ■

manishbph244@gmail.com

## चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 06 अंक 07

दिल्ली, 21 अप्रैल-27 अप्रैल 2014

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक

संतोष भारतीय

संपादक समन्वय

डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक

सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,

हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001

फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)

अजय कुमार

जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001

फोन: 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के - 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के -2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली 110001

कंप कार्यालय एक-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-6451999

6450888

विज्ञापन व प्रसार 022-42296060

+91-8451050786

+91-9266627379

फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

## दिल्ली का बाबू

### घर की उम्मीद



मुंबई में आवास एक स्थायी समस्या है, यहां तक कि सरकारी अधिकारियों के लिए भी. राज्य सरकार के संशोधित नियमों के तहत वैसे बाबू, जिनका महाराष्ट्र में सरकारी कोटे के तहत अपना घर है, वे दूसरा घर नहीं ले सकते हैं. इस नए नियम के तहत मुंबई की मैत्री को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के लगभग 84 सदस्य अयोग्य ठहराए जाएंगे. इन अधिकारियों के लिए यह भले ही बुरी खबर हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्राथमिकता के आधार पर दूसरे अधिकारियों के लिए घर आवंटन का अवसर मिल जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, इन फ्लैटों के दावेदारों में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमिताभ राजन, पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर धनंजय कमलाकर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजवर्धन सिन्हा और मुख्यमंत्री के सचिव विकास खड़गे भी अन्य लोगों में शामिल हैं. इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राज्य हाउसिंग बोर्ड के पास आवासों के आवंटन का विशेषाधिकार है. इससे यह उम्मीद बंधी है कि वे बाबू सौभाग्य से घर प्राप्त कर सकते हैं. ऐसा सौभाग्य आम मुंबई वालों के पास भला कहा है, जो महज सिर पर छत होने से ही अधिक खुश हो जाते हैं. ■



दिलीप चेरियन

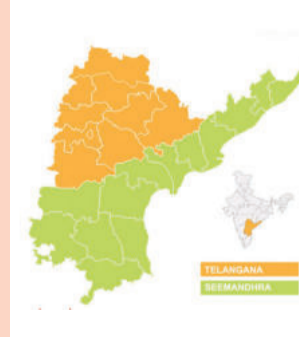
### कार्रवाई की धीमी रफ्तार

नौ करशाही का पहिया धीरे चलता है और यूपीए सरकार के दौरान यह और भी धीमा हो गया है. फिर भी मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी दंपती अरविंद एवं टीनू जोशी का आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आने के चार साल बाद उनके खिलाफ अभियोग चलाने का रास्ता साफ हो गया. वर्ष 2010 में आयकर विभाग के छापे के बाद इन दोनों के घर से 3 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैला दी थी. इस बरामदगी के बाद जोशी दंपती को निलंबित कर दिया गया था. हालांकि, अभी भी यह मामला अन्य मामलों की तरह कोर्ट में लंबे समय तक लटक सकता है, लेकिन एक बात सामने आई कि केंद्र सरकार ने उनकी बर्खास्तगी को मंजूरी दे दी और उनके खिलाफ आपराधिक मामला शुरू करने की इजाजत भी. केंद्रीय सेवा के अधिकारियों के खिलाफ केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई मामला नहीं चलाया जा सकता है. खास तौर पर कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ. अब जबकि यह स्पष्ट हो गया है, तो भ्रष्टाचार के मामले में अभियोग शुरू हो सकता है. ■



### बंटवारे की समस्या

आंध्र प्रदेश के बंटवारे की जटिल प्रक्रिया जारी है और केंद्र ने सीमांश और तेलंगाना के बीच कई विवादों को सुलझाने के लिए पूर्व शहरी विकास सचिव के शिवराम कृष्णा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, लेकिन यह समाधान निकालने के लिए बनाई गई अन्य समितियों में से एक ही है. केंद्र ने प्रदेश में आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस अधिकारियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए 1965 बैच एवं आंध्र प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सी आर कमलनाथन को नियुक्त किया है. इस पैनाल में राज्य के मुख्य सचिव पी के मोहंती, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट शामिल होंगे. साथ ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव कार्यवाहक सदस्य सचिव के तौर पर शामिल होंगे. बाबुओं के बारे में जानकारी रखने वालों का कहना है कि यह मसला इतना आसान नहीं है. इसके अलावा, दोनों राज्यों में अधिकारियों की कमी की समस्या हल करना मुश्किल है. एक अखिल भारतीय सेवा अधिकारी कैडर की पसंद चाहते हैं, जबकि यह विकल्प आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्वीकृत नहीं है. अधिनियम में यह भी कहा गया है कि तेलंगाना को 42 फ़ीसद, तो आंध्र प्रदेश को 58 फ़ीसद आईएएस अधिकारी मिलेंगे. फिलहाल, आईएएस अधिकारियों की कुल संख्या 376 है. यहां अपनी पसंद के कैडर के लिए बाबुओं में अंतर्विरोध भी चल रहा है. देखिए, आगे-आगे क्या होता है. ■



dilipcherian@gmail.com

## साउथ ब्लॉक

### सुरेश और चंद्रा निदेशक बने

1987 बैच के भारतीय रक्षा अभियंत्रण सेवा अधिकारी सुरेश सिंह को भ्रम एवं रोज़गार मंत्रालय में लंबे समय से खाली पड़े निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है. वह 1987 बैच के केंद्रीय पावर इंजीनियरिंग सेवा अधिकारी गौतम राय का स्थान लेंगे, जिन्हें द गोल्डमैन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय बरवले यूएसए के एक करियर प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था. इसी तरह 1995 बैच की आईआरएस-सी एंड सीई सीई अधिकारी ए जॉसेफ चंद्रा को वाणिज्य विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है. वह 1992 बैच के आईआरएस-सी एंड सीई अधिकारी वी के श्रीवास्तव का स्थान लेंगी, जो जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के काउंसलर नियुक्त किए गए हैं.

### भास्कर एफसीआई से जुड़े

1988 बैच के आईआरएसईई अधिकारी भास्कर हज़ारिका भारतीय खाद्य निगम के कोलकाता स्थित आंचलिक कार्यालय में महाप्रबंधक का कार्यभार संभालेंगे. यह पद पिछले कुछ समय से रिक्त था.

### पंकज सीआईसी में शामिल

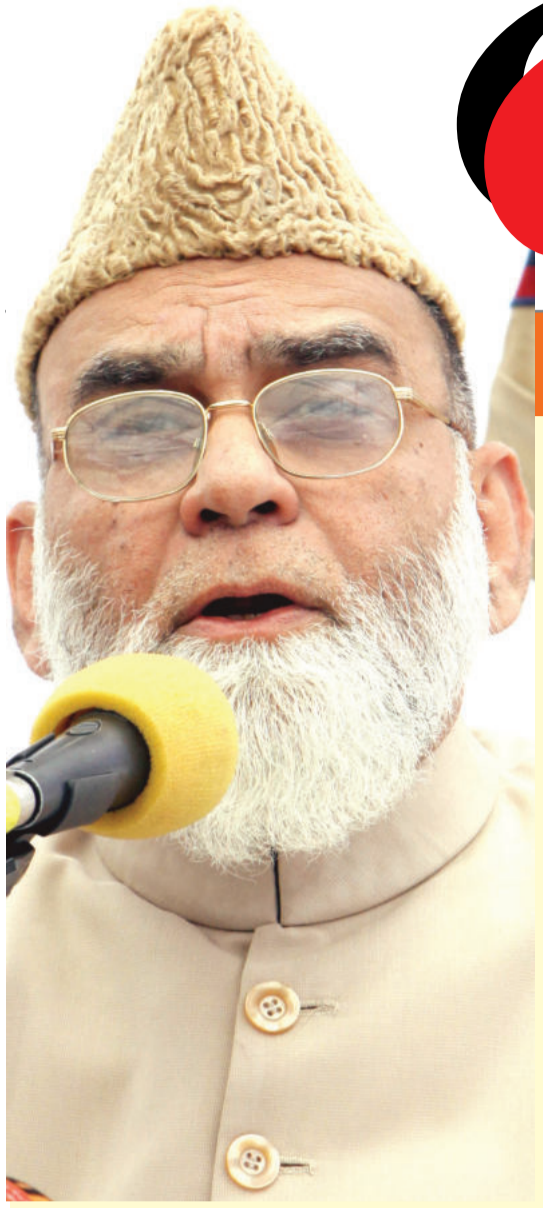
पंकज के पी श्रेयास्कार को केंद्रीय सूचना आयोग में संयुक्त सचिव (कानून) नियुक्त किया गया है, जो अभी तक केंद्रीय सूचना आयोग में निदेशक एवं संयुक्त रजिस्ट्रार थे. वह इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स अधिकारी शांति का स्थान लेंगे.

### समारिया संयुक्त सचिव बनेंगे

1993 बैच के आईएएस एवं असम सरकार के अंतर्गत खान एवं खनिज विभाग में आयुक्त एवं सचिव कैलाश चंद्र सामरिया जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं. वह 1984 बैच एवं एनईएमयूटी कैडर की आईएएस अधिकारी शकुंतला का स्थान लेंगे, जो शीघ्र ही अपना कार्यकाल पूरा करेंगी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com



अभिषेक रंजन सिंह

चावड़ी बाज़ार स्थित जरी-जरदोज़ी के कारीगर मोहम्मद जुनैद बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में सबसे भ्रमित मुस्लिम मतदाता ही हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वह किसे वोट करे। बेशक, इमाम साहब की कौल का असर देखने को मिलेगा। उनके मुताबिक, मुसलमानों का आधा वोट कांग्रेस को मिलेगा, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से में भी कुछ वोट आएंगे।



लोकसभा चुनाव 2014

## कितने असरदार रह गए हैं इमाम बुखारी?

यह पहली बार नहीं है, जब चुनाव के समय जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी ने मुसलमानों से किसी खास पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की हो। कभी कांग्रेस, कभी भारतीय जनता पार्टी और कभी समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कहने वाले इमाम बुखारी इस बार कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं। क्या देश के मुसलमानों पर उनकी इस अपील का असर पड़ेगा, इसी मसले पर प्रस्तुत है चौथी दुनिया की यह खास रिपोर्ट...

कांग्रेस के हक में वोट करने की अपील की है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की थी, जबकि एक मंत्रवा उन्हीं भारतीय जनता पार्टी की हिमायत करते हुए मुसलमानों से उसके हक में वोट करने की अपील की थी। यही वजह है कि देश के मुसलमानों को उनके ऊपर कोई एतबार नहीं रह गया है। गांव-देहात के कम पढ़े लिखे लोग बेशक उनके झरने में आ जाएं, लेकिन पढ़ा लिखा मुसलमान किसी के कहने पर वोट नहीं करेगा। वहीं इस बारे में अमीन अहमद बताते हैं कि लोग चाहे जो कहें, लेकिन इमाम साहब की बातों पर आज भी मुसलमानों को भरोसा है। अगर उन्हीं भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है, तो उसे मुसलमान संजीदगी से ले रहे हैं। निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा।

इराद अहमद अंसारी नामक एक युवक ने बताया कि इमाम बुखारी का नज़रिया समझ में नहीं आता। इस चुनाव में वह कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं, जबकि पिछले



फोटो-प्रभात पाण्डेय



चुनाव में वह किसी और पार्टी की हिमायत कर रहे थे। खुदा जाने अगले चुनाव में वह किसका समर्थन करेंगे। वहीं मोहम्मद सरफ़राज़ ने बताया कि मुसलमानों के बीच इमाम साहब की लोकप्रियता घट रही है। बेहतर यही होगा कि इमाम बुखारी अपनी इमामत छोड़ किसी सियासी पार्टी में शामिल हो जाएं।

चावड़ी बाज़ार स्थित जरी-जरदोज़ी के कारीगर

मोहम्मद जुनैद बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में सबसे भ्रमित मुस्लिम मतदाता ही हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वह किसे वोट करे। बेशक, इमाम साहब की कौल का असर देखने को मिलेगा। उनके मुताबिक, मुसलमानों का आधा वोट कांग्रेस को मिलेगा, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से में भी कुछ वोट आएंगे।

जामा मस्जिद इलाके में कुतुब खाना अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू के संचालक मोहम्मद निज़ामुद्दीन बताते हैं कि इमाम बुखारी का कहना बिल्कुल सही है कि मुसलमानों को कांग्रेस के पक्ष वोट करना चाहिए, ताकि फ़िरकापस्त ताक़तें हकूमत में न आ सकें।

बहरहाल, जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मुसलमानों से भले ही कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की हो, लेकिन सच्चाई यह है कि देश के मुसलमानों के बीच अपनी साख़ खो चुके हैं। मिसाल के तौर पर कांग्रेस को समर्थन करने की अपील पर उनके ही भाई याहया बुखारी ने विरोध जताया है। दरिबा कलां निवासी जमीला खातून ने चौथी

दुनिया को बताया कि इमाम बुखारी कौन होते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह कहने वाले कि किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं। उनके मुताबिक, इमाम बुखारी जैसे लोग सिर्फ़ अपने निजी फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं। उन्हें देश के मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली राबिया बताती हैं कि इमाम बुखारी जैसे लोगों को मुसलमानों के लिए शिक्षा और रोज़गार की बात करनी चाहिए न कि किसी पार्टी विशेष को वोट देने की अपील करनी चाहिए।

बहरहाल, 10 अप्रैल को दिल्ली-एनसीआर की सभी संसदीय सीटों पर मतदान हो गए, लेकिन जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी की अपील का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। शाही इमाम के दफ़तर से भले ही तमाम दावे किए जा रहे हों, लेकिन उन दावों की हकीकत 16 मई को सामने आ जाएगी, जब एक साथ पूरे देश के चुनाव नतीजे सामने आएंगे।

arsingh@chauthiduniya.com

**इमाम के दफ़तर में अखबारों की कतरन**

दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का सेहन (अहाता) सालों भर पर देशी-विदेशी सैनानियों और नमाजियों से भरा रहता है। यहीं पर शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी का दफ़तर भी है। उनसे मिलने के लिए सबसे पहले आपको यहीं से इजाज़त लेनी पड़ती है। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की शाही इमाम की अपील के बाद, इस बारे में मैं उनकी राय जानने उनके

दफ़तर पहुंचा। हमेशा की तरह वहां गहमागहमी का माहौल था, लेकिन इमाम साहब नहीं थे। काफी देर की मशवकत के बाद वहां कार्यरत एक कर्मचारी ने बताया कि इमाम साहब दिल्ली में नहीं हैं। वैसे तो उनके दफ़तर में उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी जवान के कई अखबार नियमित आते हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में दिए गए उनके बयान के बाद शाही इमाम के दफ़तर में अखबारों की कतरन सहेजने की कवायद चल रही थी। वहां मौजूद दो-तीन मुलाज़िम संजीदगी के साथ इमाम साहब और कांग्रेस से जुड़े उनके बयान और आलेखों का संवाह कर रहे थे। इन दौरान इमाम बुखारी से मिलने आए लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा, जब उन्हें पता चला कि वह शहर से बाहर हैं। इमाम बुखारी भले ही खुद को सक्रिय राजनीति से अलग बताते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके हालिया बयान के बाद जामा मस्जिद में मौजूद उनके दफ़तर में उस वक़्त तक गहमागहमी बनी रहेगी, जब कि लोकसभा के चुनाव संपन्न नहीं हो जाते और नई दिल्ली में नई सरकार बन नहीं जाती। ■

## क्या चुनावों के बाद टूट जाएगी आम आदमी पार्टी?

भारतीय राजनीति में सियासी पार्टियों के बनने और उसके बिखरने का इतिहास कोई नया नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी से लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी स्वयं को टूटने से नहीं बचा पाईं। हालांकि इस फ़ेहरिस्त में ज़ल्द ही आम आदमी पार्टी का नाम भी जुड़ सकता है, क्योंकि पार्टी में अंदरूनी कलह ज़ोरों पर है। लिहाज़ा लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी में बिखराव तय है। पार्टी के भीतर चल रहे घमासान का जायजा ले रहे हैं चौथी दुनिया संवाददाता **अभिषेक रंजन सिंह...**

आम आदमी पार्टी के ज़रिए राजनीति में बदलाव की उम्मीद कर रहे लोग इन दिनों बेहद निराश हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 16 मई को उनकी मायूसी और बढ़ने वाली है, क्योंकि इसी दिन लोकसभा के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। ज़ाहिर है ये नतीजे आम आदमी पार्टी के खिलाफ़ जाएंगे। संयोग से दिल्ली में जन्मी इस पार्टी की सबसे ज़्यादा दुर्गति यहीं होने वाली है। बाकी देश के अलग-अलग राज्यों में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की हालत क्या होने वाली है, इसका अंदाज़ा भी सहज लगाया जा सकता है।

दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले मैं दो महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे अश्विनी उपाध्याय ने प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया था। इसमें लक्ष्मीनगर से आम आदमी पार्टी

के विधायक विनोद कुमार बिन्नी, अन्ना हजारे के पूर्व ब्लांगर रहे राजू पारूलकर के अलावा, राकेश गुप्ता और अशोक अग्रवाल भी मौजूद थे। इस मौके पर अश्विनी उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों और सिद्धांतों से भटक चुकी है। उनके मुताबिक, आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। जो समर्पित कार्यकर्ता सच कहने की हिम्मत करता है, उसे बाहर का खुलासा करते हुए उपाध्याय ने कहा कि करोड़ों रुपयों का कोई हिसाब-किताब नहीं है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी की ओर से करीब 70 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पहले से तय थे। उनके मुताबिक, इन सीटों के लिए करीब 10 हजार से ज़्यादा लोगों से साक्षात्कार लिए गए थे, लेकिन पूर्व पत्रकार आशुतोष (चांदनी चौक), जर्नल सिंह

(पश्चिमी दिल्ली), राजमोहन गांधी (पूर्वी दिल्ली), योगेंद्र यादव (गुडगांव), खालिद परवेज़ (मुरादाबाद) और अंजलि दमानिया (नागपुर) समेत कई प्रत्याशियों के नाम पहले से ही तय थे। विनोद कुमार बिन्नी के अनुसार, आम आदमी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं थी, लेकिन केजरीवाल की मेहरबानी से यह पार्टी अब अपने आदर्शों से भटक चुकी है। दूसरी घटना बीते 6 अप्रैल की है, जब आम आदमी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर पर अरविंद केजरीवाल का पुतला फूँका। इस प्रदर्शन में वे लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। इस मौके पर अश्विनी उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल नवीन ज़िंदल और सीआईए की दलाली कर रहे हैं। इन घटनाओं से साफ़ ज़ाहिर है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले साल दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही आम आदमी पार्टी को राजधानी की सात लोकसभा सीटों में कितनी सीटें मिलेगी, इसका जवाब पार्टी के बड़े नेताओं के पास भी नहीं है। अखिर ऐसी कौन सी वजह है, जिसने आम आदमी पार्टी को आज हाशिए पर खड़ा कर दिया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी की यह हालत किसी विपक्षी पार्टियों ने नहीं बनाई, बल्कि स्वयं अरविंद केजरीवाल और उनके बड़बोले पार्टी प्रवक्ताओं ने बनाई। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विरोध की लहर चल रही है, शायद वही लहर जो आपातकाल के बाद हुए चुनावों में देखा गया था। पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जनता ने भरपूर समर्थन दिया। उम्मीदों से कहीं ज़्यादा सीटें उसे दिल्ली में मिलीं और अरविंद केजरीवाल अप्रत्याशित रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि इस बात की चर्चा करना व्यर्थ है कि केजरीवाल सरकार बनाने के लिए अपने किन बयानों से पलटें और किन आदर्शों की तिलांजलि दी। दिल्ली की आम जनता को इससे भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह केजरीवाल को एक मसीहा के रूप में देख रही थी, जो उसे महंगाई और बेरोज़गारी से



निजात दिला सके, लेकिन जनता की उम्मीदें महज 49 दिनों में ही टूटकर बिखर गईं, जब केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में लोकपाल क़ानून पारित न होने की वजह से अपना इस्तीफ़ा दे दिया।

अपने इस्तीफ़े को भले ही केजरीवाल या उनकी पार्टी जायज ठहरा रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि जब भी आम आदमी पार्टी के पतन की कहानी लिखी जाएगी, उस समय ज़ल्दबाज़ी में लिया गया अरविंद का यह फ़ैसला याद रखा जाएगा। भारतीय राजनीति में वैसे तो कई पार्टियों के बनने और टूटने का इतिहास दर्ज़ है, लेकिन डेढ़ साल पहले बनी किसी पार्टी का दुर्घात इस तरह होगा, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। वैसे आम आदमी पार्टी के प्रति सहानुभूति रखने वाले यह तर्क ज़रूर दे सकते हैं कि चुनाव के नतीजों से किसी पार्टी का भविष्य तय नहीं होता। बेशक, उनका तर्क अपनी जगह सही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को तर्क की इस कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। अरविंद केजरीवाल जिनका मानना है कि मौजूदा राजनीति जन विरोधी है। उनके मुताबिक, राजनीति ऐसी होनी चाहिए, जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो। केजरीवाल का यह विचार उचित है, लेकिन अफ़सोस वह और उनकी अद्वितीय राजनीति दिल्ली के दायरे से बाहर नहीं निकल सकी।

केजरीवाल भले ही अपनी राजनीति को गांधी दर्शन पर आधारित मानते हों, लेकिन दूख की बात यह है कि वह स्वयं को गांधी, जयप्रकाश और लोहिया से भी श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं, जिसे अरविंद केजरीवाल को इस खुशफ़हमी का शिकार बना दिया है। ■

arsingh@chauthiduniya.com

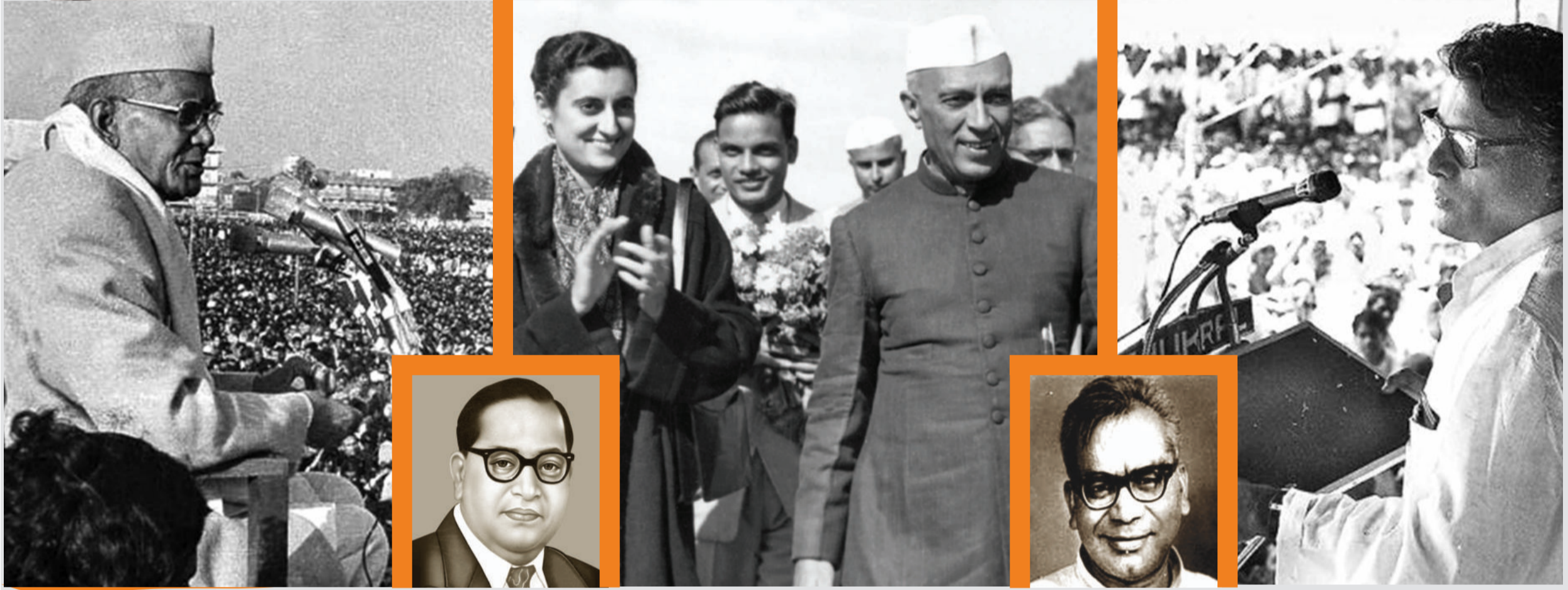


फोटो-सुनील मल्होत्रा



## लोकसभा

## 1952 से अब तक...



2 अप्रैल, 1962 को तीसरी लोकसभा का गठन हुआ. नेहरू जी फिर से प्रधानमंत्री बने. दिल का दौरा पड़ने से 27 मई, 1964 को उनका निधन हो गया, तब 2 सप्ताह के लिए गुलजारी लाल नंदा ने उनकी जगह ली. कांग्रेस द्वारा लाल बहादुर शास्त्री को नया नेता चुने जाने तक उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया. शास्त्री के देहांत के बाद कांग्रेस एक बार पुनः नेताविहीन हो गई...

## पहली लोकसभा (1952)

देश की पहली लोकसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ. पहले लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) 364 सीटों के साथ सत्ता में आई. पार्टी ने कुल पड़े वोटों का 45 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया था. पंडित जवाहर लाल नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने. स्वतंत्र भारत में चुनाव होने के पूर्व ही नेहरू के दो पूर्व कैबिनेट सहयोगियों ने कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अलग राजनीतिक दलों की स्थापना कर ली थी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक ओर जहां अक्टूबर, 1951 में जनसंघ की स्थापना की, वहीं दूसरी ओर दलित नेता बी आर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ (जिसे बाद में रिपब्लिकन पार्टी का नाम दिया गया) को पुनर्जीवित किया. अन्य दल भी उस समय सामने आए थे, जिनमें आचार्य कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा परिषद, राम मनोहर लोहिया एवं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हैं.

## दूसरी लोकसभा (1957)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली लोकसभा यानी 1952 की अपनी सफलता की कहानी 1957 में हुए दूसरे लोकसभा चुनाव में भी दोहराने में कामयाब रही. कांग्रेस के 490 उम्मीदवारों में से 371 जीतने में कामयाब रहे. पंडित जवाहर लाल नेहरू सत्ता में वापस लौटे. कांग्रेस के सदस्य फिरोज गांधी का उदय भी इस चुनाव में देखा गया. उन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नंद किशोर को 29,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया.

## तीसरी लोकसभा (1962)

2 अप्रैल, 1962 को तीसरी लोकसभा का गठन हुआ. नेहरू जी फिर से प्रधानमंत्री बने. दिल का दौरा पड़ने से 27 मई, 1964 को उनका निधन

हो गया, तब 2 सप्ताह के लिए गुलजारी लाल नंदा ने उनकी जगह ली. कांग्रेस द्वारा लाल बहादुर शास्त्री को नया नेता चुने जाने तक उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया. शास्त्री के देहांत के बाद कांग्रेस एक बार पुनः नेताविहीन हो गई. नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक बार फिर नंदा को एक महीने से कम समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया. मोरारजी देसाई के विरोध के बाद भी इंदिरा गांधी 24 जनवरी, 1966 को प्रधानमंत्री बनीं.

## महत्वपूर्ण जीत, महत्वपूर्ण हार

1957 के दूसरे आम चुनाव में पहली बार ऐसे बड़े नेता चुनाव लड़े और जीते, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे. इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लाल बहादुर शास्त्री जीते. सूरत से कांग्रेस के ही टिकट पर मोरारजी देसाई जीते थे. जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के संसदीय जीवन की शुरुआत इसी आम चुनाव से हुई थी. उन्होंने उत्तर प्रदेश की तीन सीटों से एक साथ चुनाव लड़ा था. वह बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से तो जीत गए थे, लेकिन लखनऊ और मथुरा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. मथुरा में तो उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी. लखनऊ से कांग्रेस के पुलिन बिहारी बनर्जी ने उन्हें हराया था, जबकि मथुरा से निर्दलीय उम्मीदवार राजा महेंद्र प्रताप की जीत हुई थी. 1957 में वीवी गिरि को एक निर्दलीय से हार का मुंह देखना पड़ा. उत्तर प्रदेश की चंडौली लोकसभा सीट से डॉ. लोहिया को कांग्रेस के त्रिभुवन नारायण सिंह ने हराया था. चंद्रशेखर ने भी पहला चुनाव 1957 में ही पीएसपी के टिकट पर लड़ा था, तब बलिया और गाजीपुर के कुछ हिस्से मिलाकर रसड़ा संसदीय सीट थी. चंद्रशेखर ने इसी सीट से चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे.

- चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक जिला किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) निवासी 97 वर्षीय श्याम सरन नेगी सबसे वरिष्ठ मतदाता हैं. नेगी 1952 के चुनाव में सब से पहले वोट डालने वालों में से एक थे.
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग पहली बार केरल के परूर विधान सभा क्षेत्र के 50 पोलिंग बूथों पर 1982 में हुआ था.
- अटल बिहारी वाजपेयी पहले राजनेता हैं जिन्होंने 6 अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव जीता है. बलरामपुर - 1957, 1967, बवालियर - 1971, नई दिल्ली-1977, 1980, विदिशा-1991, गांधीनगर-1996, लखनऊ-1991, 1996, 1998.
- चार राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली, से लोक सभा चुनाव जीतने वाले अटल बिहारी वाजपेई पहले राजनेता हैं.
- 7 अप्रैल से शरु होकर 16 मई तक चलने वाले और 9 चरणों में संपन्न होने वाले थे लोक सभा चुनाव भारत में अब तक सब से लम्बी अवधि तक चलने वाले आम चुनाव हैं.
- भारतीय मतदाता आम चुनाव (लोक सभा) 2014 में पहली बार नोटा (इन में से कोई नहीं) विकल्प इस्तेमाल करेंगे.

## चौथी लोकसभा (1967)

1967 में पहली बार कांग्रेस ने निचले सदन में करीब 60 सीटें खो दीं, उसे केवल 283 सीटों पर जीत हासिल हुई. कांग्रेस को एक बड़ा झटका सहना पड़ा, क्योंकि बिहार, केरल, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब एवं पश्चिम बंगाल में गैर-कांग्रेस सरकारें बनीं. इंदिरा गांधी को 13 मार्च को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई. असंतुष्ट आवाजें शांत रखने के लिए उन्होंने मोरारजी देसाई को भारत का उप-प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री नियुक्त किया.

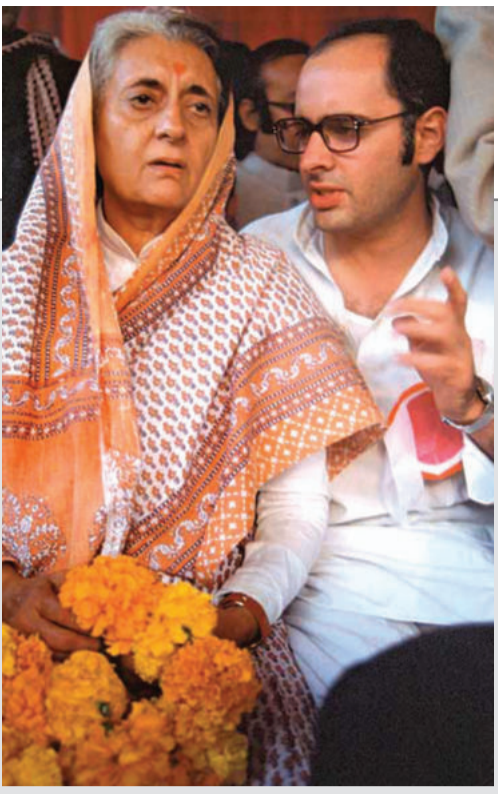
## पांचवीं लोकसभा (1971)

1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के चुनावी नारे के साथ 352 सीटों पर जीत दर्ज की. भारत-पाकिस्तान युद्ध में आई बड़ी आर्थिक लागत, दुनिया में तेल की कीमतों में वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट ने आर्थिक कठिनाइयां बढ़ा दी थीं. 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी भ्रष्टाचार के आधार पर इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध ठहरा दिया. इस्तीफे की बजाय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की और पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया.

## छठी लोकसभा (1977)

कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा 1977 के चुनाव में मुख्य मुद्दा थी. 23 जनवरी को इंदिरा गांधी ने मार्च में चुनाव कराने की घोषणा की और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया. चार विपक्षी दलों-कांग्रेस (ओ), जनसंघ, भारतीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने जनता पार्टी के रूप में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया. कांग्रेस को स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई ने 298 सीटें जीतीं. देसाई 24 मार्च को भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने. लगभग 200 सीटों पर





कांग्रेस की हार हुई. इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव हार गए.



## सातवीं लोकसभा (1980)

चरण सिंह और जगजीवन राम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से खुश नहीं थे. जनता पार्टी 1979 में विभाजित हो गई. अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी छोड़ दी और बीजेएस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया. देसाई ने संसद में विश्वास मत खोने के बाद इस्तीफा दे दिया. चरण सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में जून 1979 में शपथ ली. कांग्रेस ने समर्थन का वादा किया, लेकिन बाद में पीछे हट गई. जनवरी 1980 में चुनाव की घोषणा हुई. कांग्रेस ने लोकसभा में 351 सीटें जीतीं और जनता पार्टी या बचे हुए गठबंधन को 32 सीटें मिलीं.

## आठवीं लोकसभा (1984-89)

31 अक्टूबर, 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. नवंबर 1984 में चुनाव की घोषणा कर दी गई. कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की. उसने 409 लोकसभा सीटें और कुल मतों का 50 फीसद अपने नाम किया. तेलुगुदेशम पार्टी 30 सीटों के साथ संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई. यह भारतीय संसद के इतिहास के उन दुर्लभ रिकॉर्डों में से एक है, जिसमें कोई क्षेत्रीय पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी.

## नौवीं लोकसभा (1989)

9वीं लोकसभा का चुनाव भारतीय चुनावी राजनीति में कई मायनों में ऐतिहासिक घटना रहा. इस चुनाव ने राजनेताओं के वोट मांगने का तरीका बदल दिया. उस वक्त जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगना केंद्र बिंदु बन गया था. विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के सबसे बड़े आलोचक थे. उन्हें शीघ्र ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया. उन्होंने अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान के साथ जनमोर्चा का गठन किया. 11 अक्टूबर, 1988 को जनमोर्चा, जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस (एस) के विलय से जनता दल की स्थापना हुई. द्रमुक, तेदेपा और अगप सहित कई क्षेत्रीय दल जनता दल से मिल गए और नेशनल फ्रंट की स्थापना की गई. 525 सीटों के लिए यह चुनाव 22 नवंबर एवं 26 नवंबर, 1989 को 2 चरणों में संपन्न हुआ. नेशनल फ्रंट के लिए लोकसभा में यह आसान बहुमत हासिल हुआ, राष्ट्रीय मोर्चे के सबसे बड़े घटक जनता दल ने 143 सीटें जीतीं और उसने वाममोर्चे और भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई. विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने और दे-वीलाल उप-प्रधानमंत्री. उन्होंने 2 दिसंबर, 1989 से 10 नवंबर, 1990 तक कार्यभार संभाला. लालकृष्ण आडवाणी द्वारा राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर रथयात्रा शुरू करने और मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा बिहार में आडवाणी को गिरफ्तार किए जाने के बाद भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया. सिंह ने विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया. चंद्रशेखर 64 सांसदों के साथ जनता दल से अलग हो गए और उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी बनाई. उन्हें बाहर से कांग्रेस का समर्थन मिला और वह भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने. अखिरकार उन्होंने भी 6 मार्च, 1991 को इस्तीफा दे दिया, जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार राजीव गांधी की जासूसी करा रही है.

## दसवीं लोकसभा (1991)

10वीं लोकसभा का चुनाव मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने और राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के चलते मंडल-मंदिर चुनाव भी कहा जाता है. मतदान के पहले दौर के एक दिन बाद यानी 20 मई, 1991 को तमिल ईलम लिबरेशन

## चुनावी कहानी, आंकड़ों की जुबानी

2009 के आम चुनाव में सुरक्षाकर्मी: 12 लाख
रूस की सेना से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी चुनाव में तैनात
रूसी सेना में शामिल कुल सैनिकों की संख्या: 8.45 लाख
2009 में चुनाव आयोग के इस्तेमाल में लाई गई ट्रैनों की संख्या: 119
2009 में चुनाव आयोग के इस्तेमाल में लाए गए हेलिकॉप्टरों की संख्या: 55
सर्वाधिक वोटों वाला लोकसभा क्षेत्र: मलकाजगिरी (आंध्र प्रदेश), 29.53 लाख वोट
सबसे कम वोटों वाला लोकसभा क्षेत्र: लक्षद्वीप, 47,972 वोट
भारतीय चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या: 06
भारतीय चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त कुल प्रांतीय पार्टियों की संख्या: 45
भारतीय चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों की कुल संख्या: 702
1977 के चुनाव में सबसे कम महिला प्रत्याशी, 19 की जीत.
1952 में चुनाव का प्रति मतदाता खर्च: 0.60 पैसे
2004 में चुनाव का प्रति मतदाता खर्च: 17 रुपये
2009 में चुनाव का प्रति मतदाता खर्च: 12 रुपये

## राजीव, राजमोहन और मेनका

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पौत्र 78 वर्षीय राजमोहन गांधी पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ राजमोहन गांधी जनता दल के टिकट पर 1989 में अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन राजमोहन गांधी को 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी से करारी हार मिली थी. उस चुनाव में राजीव गांधी को 2,71,407 और राजमोहन गांधी को 69,269 मत प्राप्त हुए थे. अमेठी लोकसभा सीट से नेहरू-गांधी परिवार की ही बहु मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वह हार गई थी. ■

## नेहरू बनाम लोहिया

फूलपुर संसदीय सीट हमेशा से चर्चा में रही है. यहां 1962 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दो दोस्तों बीच कड़ी टक्कर हुई थी. वह दो दोस्त कोई और नहीं बल्कि जवाहर लाल नेहरू और डॉ. राम मनोहर लोहिया थे. लोहिया ने ही गैर-कांग्रेस वाद का सिद्धांत दिया और कांग्रेस की हर नीति का विरोध किया. लोहिया ने इसी कांग्रेस विरोध के चलते 1962 में जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. इसी कारण डॉ. लोहिया ने भारतीय जनसंघ का सहयोग लेने में भी संकोच नहीं किया. इस रणनीति के कारण 1967 के आम चुनाव के बाद उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों से कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी और डॉ. लोहिया ने राजनीति में सफलता हासिल की.



## इंदिरा बनाम राजनारायण

1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ लोकबंधु राजनारायण ने चुनाव लड़ा था. इंदिरा गांधी जीत गईं लेकिन राजनारायण ने उन पर यह आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया. इंदिरा के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज जगमोहन सिन्हा ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहरा दिया और उन्हें 6 साल तक पद से वंचित कर दिया. उसके बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश पर स्टे ले लिया. बाद में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी, जो 21 मार्च 1977 तक लागू रही और उस दौरान विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया. इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में लोकबंधु राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा और इंदिरा गांधी हार गईं. ■

टाइगरस द्वारा श्रीपेठुदूर (तमिलनाडु) में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई. इस चुनाव में महज 53 प्रतिशत मतदान हुआ. एक त्रिशंकु संसद बनी, जिसमें 232 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और 120 सीटों के साथ भाजपा दूसरे स्थान पर रही. जनता दल सिर्फ 59 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा. 21 जून को कांग्रेस के पीवी नरसिम्हाराव ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली.

## ग्यारहवीं लोकसभा (1996)

11वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव परिणामों से एक बार फिर त्रिशंकु संसद बनी और 2 वर्ष तक राजनीतिक अस्थिरता रही. इस दौरान देश के 3 प्रधानमंत्री बने. भाजपा को 161 सीटें और कांग्रेस को 140 सीटें मिलीं. अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई को प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, लेकिन 13 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया. जनता दल के नेता देवेगौड़ा ने एक जून को संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार बनाई, जो 18 महीने चली. इसके बाद

देवेगौड़ा के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अप्रैल 1997 में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला.

## बारहवीं लोकसभा (1998)

इस चुनाव ने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 265 सीटों का कार्यकारी बहुमत प्रदान किया. इस संदर्भ में 15 मार्च को राष्ट्रपति के आर नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया. 19 मार्च को वाजपेयी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली.

## तेरहवीं लोकसभा (1999)

17 अप्रैल, 1999 को वाजपेयी लोकसभा में विश्वास मत हार गए, फलस्वरूप उनकी गठबंधन सरकार ने इस्तीफा दे दिया. पिछले चुनाव 1996 और 1998 में हुए थे, इसलिए 1999 के चुनाव 40 महीने में तीसरी बार हो रहे थे. 6 अक्टूबर को आए परिणामों में राजग को 298 सीटें मिलीं और कांग्रेस एवं उसके सहयोगियों को 136 सीटों पर विजय प्राप्त

हुई. वाजपेयी ने 13 अक्टूबर को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली.

## चौदहवीं लोकसभा (2004)

20 अप्रैल से 10 मई 2004 के बीच 4 चरणों में आम चुनाव हुए. कांग्रेस अपने सहयोगियों की मदद से 335 सदस्यों (बसपा, सपा, एमडीएमके और वाममोर्चा के बाहरी समर्थन सहित) का बहुमत प्राप्त करने में सफल रही. चुनाव के बाद हुए इस गठबंधन को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) कहा गया. पूर्व वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने.

## पंद्रहवीं लोकसभा (2009)

मई 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम घोषित हुए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने लोकसभा का नेतृत्व करने का जनादेश हासिल किया. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दोबारा देश का नेतृत्व करने का अवसर मिला. ■

- चौथी दुनिया टीम





पाटलिपुत्र से जदयू के रंजन यादव के खिलाफ रामकृपाल यादव हैं। मधेपुरा में शरद यादव के खिलाफ पप्पू यादव अखाड़े में हैं। जहानाबाद में जदयू के अनिल शर्मा के खिलाफ भाजपा गठबंधन के अरुण सिंह मैदान में हैं। दोनों भूमिहार जाति से हैं।



## नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग की धार कुंद

# विरोधियों ने लोहे को लोहे से काटा

बिहार



नीतीश कुमार अभी तक जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसमें यह ध्यान रख रहे थे कि ज्यादातर सीटों पर उस जाति के उम्मीदवार उतारे जाएं, जिससे दूसरे दलों के उम्मीदवार आने की संभावना कम हो। इससे उन्हें सीधा लाभ यह मिल रहा था कि उस जाति के वोटों का धुवीकरण जदयू के पक्ष में हो रहा था...



सरोज सिंह

सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी हैं। पिछले कई चुनावों में उन्होंने अपने इस हुनर का बखूबी इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक विरोधियों को चारों खाने चित किया है, लेकिन लगता है, इस बार के चुनाव में नीतीश के विरोधियों ने उनकी सोशल इंजीनियरिंग की ताकत कम करने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए। यह उन्हीं घोड़ों की चाल का नतीजा है कि बिहार की ज्यादातर सीटों पर जदयू उम्मीदवार घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। जो जातीय ताना-बाना जदयू के लिए वोटों का इंतजाम करता था, आज जदयू उम्मीदवार उसी जातीय ताने-बाने में उलझ कर रह गए हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि विरोधियों का जातीय चकव्यूह तोड़कर दिल्ली के लिए रास्ता कैसे साफ किया जाए।

सभी दलों ने जो टिकट बांटे हैं, अगर उनकी लिस्ट गौर से देखी जाएं, तो यह समझना आसान हो जाएगा कि कैसे नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग की धार दूसरे दल के



नेताओं ने इस बार कुंद कर दी है। सासाराम सुरक्षित सीट से जदयू ने महादलित के पी रमैया को चुनाव मैदान में उतारा, तो कांग्रेस-राजद गठबंधन ने महादलित मीरा कुमार को सामने कर दिया। भाजपा ने यहां से दलित छेदी पासवान को मौका दिया। साफ है कि महादलित वोटों पर जदयू का अपना दावा है। ऐसे में दो महादलित उम्मीदवार होने से यहां इस मत का बंटवारा होना तय है। इसी तरह काराकाट से जदयू ने कुशवाहा जाति के महाबली सिंह को उतारा है, तो भाजपा गठबंधन से उषेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं यानी कुशवाहा वोटों में विभाजन तय है। नवादा से जदयू और राजद, दोनों के उम्मीदवार यादव जाति के हैं। जमुई से जदयू और राजद, दोनों के उम्मीदवार महादलित हैं।



दरअसल, नीतीश कुमार अभी तक जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसमें यह ध्यान रख रहे थे कि ज्यादातर सीटों पर उस जाति के उम्मीदवार उतारे जाएं, जिससे दूसरे दलों के उम्मीदवार आने की संभावना कम हो। इससे उन्हें सीधा लाभ यह मिल रहा था कि उस जाति के वोटों का धुवीकरण जदयू के पक्ष में हो रहा था और इसके अलावा, गठबंधन के आधार वोटों का सीधा लाभ भी जदयू उम्मीदवार को मिल रहा था, लेकिन इस बार विरोधियों ने नीतीश कुमार की चालों को अच्छी तरह समझा और यथासंभव कोशिश की है कि एकल जाति का

फ़ायदा नीतीश कुमार न उठा पाएँ। जैसे कि नालंदा में ही नीतीश कुमार के कुर्मी उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के मुकाबले में राजद गठबंधन से कुर्मी जाति के आशीष रंजन सिन्हा को उतारा गया है। मुंगेर से जदयू के भूमिहार उम्मीदवार ललन सिंह के खिलाफ लोजपा की उसी जाति की उम्मीदवार वीणा सिंह चुनाव मैदान में हैं।

पाटलिपुत्र से जदयू के रंजन यादव के खिलाफ रामकृपाल यादव हैं। मधेपुरा में शरद यादव के खिलाफ पप्पू यादव अखाड़े में हैं। जहानाबाद में जदयू के अनिल शर्मा के खिलाफ भाजपा गठबंधन के अरुण सिंह मैदान में हैं। दोनों भूमिहार जाति से हैं। इसी तरह सुपौल से जब जदयू ने अति पिछड़ा उम्मीदवार उतारा, तो भाजपा ने भी अति पिछड़े कामेश्वर चौपाल को उतार दिया। आरा में जदयू की मौजूदा सांसद मीना सिंह के खिलाफ राजपूत जाति के ही राजकुमार सिंह को भाजपा ने उतारा है। मधुबनी में जदयू के गुलाम गौस के खिलाफ राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी मुकाबले में हैं। इसी तरह खगड़िया में जदयू के दिनेश चंद्र यादव के मुकाबले राजद ने कृष्णा यादव को मैदान में उतारा है। दूसरे दलों की इसी चाल ने नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग की धार कुंद कर दी है।

बिहार की ज्यादातर सीटों पर कमोबेश यही हाल है। एक ही जाति के दो उम्मीदवार होने से वोटों का बंटवारा हो रहा है और जदयू को जो स्वाभाविक लाभ मिलता था, उससे वह वंचित हो रहा है। यही हाल जदयू के आधार वोटों का है। अब तक यह माना जा रहा है कि महादलित और अति पिछड़ा

## जाति बची, सारे मुद्दे गायब

जातीय राजनीति और चुनाव बिहार की सच्चाई रही है और आज भी यह सच्चाई इस सच्चाई से पार नहीं पा सका है। चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में चौक-चौराहों पर जातीय गुणा-भाग की कहानी आसानी से सुनी जा सकती है। फलां जाति के वोट फलां पार्टी को, तो फलां जाति के वोट फलां पार्टी को। बस इसी जोड़-घटाव से गांव की चौपाले गुलजार हैं। न स्थानीय मुद्दों की चर्चा है और न राष्ट्रीय समस्याओं की। हां, एक बात जो हर लोकसभा क्षेत्र में आम है, वह है नमो-नमो। तमाम जातीय गणित के बीच नरेंद्र मोदी चर्चा में हैं और इसे न केवल भाजपा, बल्कि उसके विरोधी दल वाले भी मान रहे हैं।

आखिर समस्याओं की बारी चुनावी चर्चा में क्यों नहीं आती? इस सवाल के जवाब में विधान पार्श्व नवल यादव कहते हैं कि जाति एक सच्चाई है, उससे कौन इंकार कर सकता है? हम जिस जातीय व्यवस्था में जीते हैं, उसे चुनाव के वक्त कैसे छोड़ सकते हैं? यादव कहते हैं कि लोगों को जाति से आगे निकल कर जमात की ओर भी देखना चाहिए और देश के सामने जो समस्याएं हैं, उन्हें देखकर भी अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस कहते हैं कि बिहार में तो वोट और बेटी अपनी ही जाति में देने का रिवाज चलता आ रहा है, लेकिन लोजपा हमेशा जमात की बात करती है। पारस कहते हैं कि चुनावी राजनीति में जाति एक अहम भूमिका निभाती है, इसलिए चुनावी मौसम में जातीय राग कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ता है, लेकिन लोजपा सभी जातियों एवं धर्मों का बराबर सम्मान करती है।

वर्ग जदयू के साथ है, लेकिन अगर टिकट बंटवारे में इन जातियों के उम्मीदवारों की संख्या पर गौर किया जाए, तो यह अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि कैसे दूसरे दलों ने नीतीश कुमार को इस बार कोई साफ संदेश देने से रोकने का काम किया है। जैसे कि जदयू ने पांच महादलितों को अपना उम्मीदवार बनाया, तो राजद गठबंधन ने पांच महादलितों को टिकट दिया, वहीं भाजपा गठबंधन ने भी दो महादलित उम्मीदवार उतारे। इसी तरह अति पिछड़ों को टिकट देने में सभी दलों ने दरियादिली दिखाई है। जदयू ने जहां तीन अति पिछड़ों को उम्मीदवार बनाया है, तो भाजपा गठबंधन ने उसे पीछे छोड़ते हुए पांच अति पिछड़ों को टिकट थमा दिए। उधर राजद गठबंधन ने भी तीन अति पिछड़ों को चुनाव मैदान में उतारा है।

कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार अब तक जिन महादलितों एवं अति पिछड़ों की बात करते थे, उन्हें उन्हीं की भाषा में भाजपा और राजद ने कारा जवाब दिया है। भाजपा नेता राकेश सिंह कहते हैं, बहुत पुरानी कहावत है कि लोहा ही लोहे को काटता है। नीतीश कुमार अब तक जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात करते आ रहे थे, हमने उन्हें उन्हीं के स्टाइल में जवाब दे दिया है। अब लोगों को तय करना है कि उनका सच्चा हितेषी कौन है। राकेश कहते हैं कि जदयू ने अब तक केवल इन जातियों के वोट लेने का काम किया है, लेकिन इनके विकास को लेकर नीतीश कुमार कभी संजीदा नहीं रहे। उन्होंने इनका केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब इन जातियों ने भी सच जान लिया है और इस चुनाव में नीतीश इनके वोट के लिए तरस जाएंगे।

feedback@chauthiduniya.com

## उत्तराखंड

# कांग्रेस-भाजपा में कांटे का मुकाबला



राजकुमार शर्मा

देवभूमि उत्तराखंड की सभी पांच संसदीय सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच घमासान होना तय है। राज्य में चुनाव मैदान में उतरने वाले विभिन्न क्षेत्रीय दल वोटकटवा की हैसियत में नज़र आ रहे हैं। पिछली बार भाजपा की अंतर्कलह और राहुल गांधी के असर के चलते सभी पांच सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। उसके ठीक बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी जनता ने भाजपा से अपना पल्ला झाड़ लिया। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस हाईकमान ने एक उद्योगपति धराने के दबाव में आकर अपने चुने गए विधायकों की

भावना को नकार कर सांसद विजय बहुगुणा को राज्य की कमान सौंप दी।

राज्य में आई भीषण दैवीय आपदा में बहुगुणा सरकार ने जिस तरह उपेक्षात्मक रवैया अपनाया, उसके चलते जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सेना के जवानों ने आपदा में फंसी जनता का हाथ मजबूती से थामा। राज्य सरकार किसी भी प्रकार की मदद के मामले में फिसड्डी साबित हुई। देश-विदेश से अरबों रुपये की आर्थिक मदद मिली, लेकिन उसे भी जनता तक पहुंचाने में बहुगुणा सरकार असफल साबित हुई। लोगों का आरोप है कि मंत्रियों, नेताओं एवं अफसरों ने सहायता राशि की बंदरबांट कर ली। सहायता राशि प्रभावित जनता तक न पहुंचने का मामला जब कांग्रेस हाईकमान

के समक्ष उठा, तो विजय बहुगुणा को हटाकर केंद्रीय मंत्री हरीश रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। चुनाव के पहले ही बहुगुणा की विदाई का जो निर्णय कांग्रेस ने लिया, वही आज उसके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। सतपाल महाराज ने इस कलह की गूंज में ही टिहरी सीट पर अपनी करारी हार का अनुमान लगाते हुए राजनाथ सिंह के माध्यम से भाजपा का दामन थाम लिया। नतीजा, कांग्रेस का पूरा दुर्ग ही दहल उठा।

भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राज्य की पांचों सीटों जीतने के लक्ष्य के साथ अपने तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनकी उम्र और छवि का ख्याल किए बिना मैदान में उतार दिया है। पैड़ी से जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, नैनीताल से भगत सिंह कोश्यारी एवं हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक को प्रत्याशी बनाया गया है। जनरल खंडूरी एवं कोश्यारी जहां अपनी बेदाग छवि के चलते जनता में हाथों हाथ लिए गए, वहीं निशंक को लोग शंका की नज़र से देख रहे हैं। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार की कालिख उड़ेलने वाली भाजपा को महाकुंभ-2010 में निशंक सरकार के घोटेले के सवाल पर बगलें झांकने के सिवाय कुछ सूझ नहीं रहा है।

टिहरी सीट पर रानी राज्यलक्ष्मी को हरा पाना साकेत के वश की बात नहीं रह गई है, क्योंकि उनके पिता की बदनामी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ रही है। गढ़वाल में सतपाल महाराज के रणछोड़ दास बनने के बाद जनरल की टक्कर का कोई प्रत्याशी कांग्रेसी खेमे में नहीं बचा था, बाद में

हाईकमान की पहल पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. हरक सिंह रावत मैदान में उतरे। गढ़वाल सीट का इतिहास काफी रोचक है। इसी सीट पर 1980 में कांग्रेस उम्मीदवार हेमवती नंदन बहुगुणा ने रिकॉर्ड 1,25,440 मतों की शानदार जीत हासिल की थी। इसी क्षेत्र से जनरल खंडूरी ने 1998, 1999 एवं 2004 में लगातार चुनाव जीतते हुए हैट्रिक कायम की थी।

देवभूमि की जनता की अपनी अलबेली पहचान है। कांग्रेस जहां अपने नेताओं की आपसी

कलह से तंग है, वहीं भाजपा के नेता भी एकजुट नहीं दिखते। विकल्प की तलाश में जनता क्या फैसला लेगी, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना सच है कि मुख्य मुकाबले में होने के बावजूद कांग्रेस की राह आसान नहीं है। यदि कांग्रेस के नेताओं ने समय रहते आपसी कलह का परित्याग न किया, तो पार्टी का हश्र वही हो सकता है, जो पिछले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में भाजपा का हुआ था।

feedback@chauthiduniya.com





एक जमाने में एक-दूसरे के पूरक रहे सूरज मंडल ने सबसे पहले शिबू सोरेन का साथ छोड़ा. अलग राज्य बनने के पूर्व जब झारखंड में जैक का गठन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष शिबू सोरेन बने और सूरज मंडल उपाध्यक्ष बनाए गए. इसके अलावा, बिहार के लालू राज में दोनों ही नेता मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खास लोगों में शामिल थे.



रूपेश कुमार

करीब एक महीने तक बार-बार टिकट बदलने और लंबे ड्रामे के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपना रायपुर का प्रत्याशी सत्य नारायण शर्मा को ही बनाया. इसी के साथ छत्तीसगढ़ में पूरी 11 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार फाइनल हो गए. अब सवाल है कि कौन कितनी सीटें जीतेगा. पिछले दो लोकसभा चुनाव से भाजपा यहां की 11 में से 10 सीटें जीतती आई है. मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा है कि इस बार सभी 11 सीटें जीतेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में मात्र 0.73 प्रतिशत वोट से सत्ता बचाने वाले रमन सिंह को मालूम है कि 10 सीटें बचाना भी आसान नहीं है. दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि कम से कम छह सीटें उनकी हैं. जानकारों के मुताबिक, भाजपा के लिए लोकल एंटी इनकम्बेंसी से बचकर फिर से 10 सीटें जीतना आसान नहीं है, वहीं गुटों में बिखरी कांग्रेस का भाजपा से ज्यादा सीटें जीतना हकीकत से दूर दिखता है.

भाजपा के दावे का आधार विधानसभा चुनाव में तीसरी बार मिली कामयाबी है. विधानसभा चुनाव में रमन सिंह ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली थी. चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाकर रमन ने 11 अशोक रोड तक यह संदेश दे दिया कि विधानसभा में मिली जीत उनकी अपनी छवि का नतीजा है. अब छत्तीसगढ़ में रमन पार्टी से बड़े हो चुके हैं. भाजपा के फैसलों में इसका साफ असर दिखता है. पार्टी में वह अपने तमाम विरोधियों को किनारे कर चुके हैं. विधानसभा चुनाव में ही उन्होंने करुणा शुक्ला को टिकट और प्रचार में जगह न



छत्तीसगढ़

## कांग्रेस और भाजपा में कांटे की जंग



भाजपा के दावे का आधार विधानसभा चुनाव में तीसरी बार मिली कामयाबी है. विधानसभा चुनाव में रमन सिंह ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली थी. चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाकर रमन ने 11 अशोक रोड तक यह संदेश दे दिया कि विधानसभा में मिली जीत उनकी अपनी छवि का नतीजा है. अब छत्तीसगढ़ में रमन पार्टी से बड़े हो चुके हैं. भाजपा के फैसलों में इसका साफ असर दिखता है. पार्टी में वह अपने तमाम विरोधियों को किनारे कर चुके हैं.

देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया. नंद कुमार साय अलग-थलग पड़े हैं. चुनाव के बाद उन्होंने नई सरकार में बृजमोहन के सभी अहम मंत्रालय छीनकर अपने चहेते राजेश मृगत को थमा दिए हैं. भाजपा में सबसे चतुर खिलाड़ी समझे जाने वाले बृजमोहन अभी किनारे लगा दिए गए हैं. बृजमोहन प्रबंधन और अनुशासन भाजपा के पक्ष में है. वह यह चुनाव मोदी के नाम और रमन के काम के सहारे लड़ रही है. जो बात भाजपा नेताओं के खिलाफ दिखती है, वह है प्रत्याशी. भाजपा ने 2 सांसदों के टिकट काटे हैं. दो सांसदों का निधन होने की वजह से पार्टी को नए प्रत्याशी उतारने पड़े हैं. बाकी 6 मौजूदा सांसद ही हैं. भाजपाई सांसदों के खाले में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, जिसे वे जनता के बीच बता सकें. ज्यादातर सांसद ऐसे हैं, जो चुनाव में ही दिखते हैं. संसद में भी कोई

जीतने वाले मधुसूदन यादव का टिकट काटकर अपने बेटे अभिषेक सिंह को दिलवा दिया. रमन को खुद पर पूरा भरोसा है. पार्टी में कोई नेता बचा नहीं है, जो अंदरखाने रमन के लिए चुनौती बन सके. इसलिए भाजपा यह चुनाव एकजुटता के साथ बिना किसी घात-प्रतिघात के लड़ने जा रही है. बेहतर प्रबंधन और अनुशासन भाजपा के पक्ष में है. वह यह चुनाव मोदी के नाम और रमन के काम के सहारे लड़ रही है. जो बात भाजपा नेताओं के खिलाफ दिखती है, वह है प्रत्याशी. भाजपा ने 2 सांसदों के टिकट काटे हैं. दो सांसदों का निधन होने की वजह से पार्टी को नए प्रत्याशी उतारने पड़े हैं. बाकी 6 मौजूदा सांसद ही हैं. भाजपाई सांसदों के खाले में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, जिसे वे जनता के बीच बता सकें. ज्यादातर सांसद ऐसे हैं, जो चुनाव में ही दिखते हैं. संसद में भी कोई

छत्तीसगढ़िया सांसद अपनी पहचान नहीं बना पाया. अभिषेक को छोड़कर जिन लोगों को मौका मिला है, उनमें कोई नामचीन नहीं है. सबसे मोदी और रमन का ही सहारा है. ऐसे हालात में भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, इसकी संभावना कम ही दिखती है.

कांग्रेस के लिहाज से देखें, तो छत्तीसगढ़ उसके उन राज्यों की सूची में है, जहां कांग्रेस बहुत हासिल करेगी. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले दो चुनावों में कांग्रेस 11 में से सिर्फ एक सीट ही जीत सकी. लिहाजा उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है. दूसरी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस चार महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में केवल छत्तीसगढ़ में ही टक्कर दे पाई थी. दो-धुवीय राजनीति के केंद्र छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महज पौन फ़ीसद वोटों और 5 सीटों के अंतर से सत्ता में आते-आते रह गई. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर बहुत हासिल की थी. एक और बड़ी वजह है कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ खूब आक्रोश था. जनता ने दोनों पार्टियों के 50 से ज्यादा विधायकों को सड़क पर ला खड़ा किया था. अगर यही ट्रेंड लोकसभा में सांसदों के खिलाफ रहा, तो कांग्रेस की बल्ले-बल्ले हो सकती है.

भाजपा ने रमेश बैस और एक हद तक विष्णुदेव साय को छोड़कर प्रदेश स्तर पर पहचान रखने वाले किसी नेता को नहीं उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं को टिकट थमा दिए हैं, जैसे कोरबा से केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत, महासमुंद से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, बिलासपुर से करुणा शुक्ला एवं रायपुर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्य नारायण शर्मा. लेकिन, इन्हीं दिग्गजों की आपसी टकराहट कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है. प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल पिछले दस सालों से जोगी की ब्लैक लिस्ट में हैं. पार्टी में भूपेश बघेल जोगी के सबसे बड़े विरोधी माने जाते रहे हैं. माना जाता है कि जोगी के अधूरे संन्यास की वजह भूपेश बघेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना था. रायपुर सीट से पहली बार सत्य नारायण शर्मा का टिकट काटा, तो शर्मा समर्थकों ने भूपेश को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस मुख्यालय में कुर्सियां तोड़ी थीं. हालांकि बाद में टिकट सत्य नारायण शर्मा को मिला. रायगढ़, जांजगीर-चाम्पा बिलासपुर और राजनांदगांव में टिकट वितरण से उपजा विरोध थमा नहीं है.

कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है. इस हालत में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें निकाल पाएगी, यह बड़ा रोचक सवाल है. इस चुनावी रण में आम आदमी पार्टी भी है, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच भी है, लेकिन जानकार उन्हें मुख्य लड़ाई का हिस्सा नहीं मानते. बस्तर से सोनी सोरी ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, लेकिन अभी उनके बारे में आकलन करना मुश्किल है. जिस राज्य में आज भी जनता नेता नहीं, बल्कि फूल छाप और हाथ पहचानती है, वहां मोदी और केजरीवाल इफेक्ट के असरदार रहने की संभावना कम है. शहरी इलाकों में इसका कुछ असर हो सकता है, लेकिन वह निर्णायक होगा, इसकी संभावना कम है. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

# अपनों के बीच बेगाने हुए शिबू

मंगलानंद मिश्र

सूबे में दिशोम गुरु के नाम से विख्यात झारखंड आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन अपनों के बीच ही बेगाने हो गए हैं. अपने मूढन्य सहयोगियों से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरे शिबू सोरेन को पूरा भरोसा है कि क्षेत्र की जनता उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी. जिस राज्य के गठन को लेकर वह अपना खून-पसीना बहाते आए हैं, वहां की जनता उनके साथ नहीं होगी, ऐसा सोरेन सोचते भी नहीं होंगे. उम्र के जिस पड़ाव पर शिबू सोरेन अपने क्षेत्र की सेवा का जज्बा लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं, उससे यह साफ है कि शिबू सोरेन अपनी राजनीतिक जमीन ताउम्र खोना नहीं चाहते. हाल के दिनों में झामुमो के मजबूत स्तंभों में से एक हेमलाल मुर्मू के पार्टी छोड़ने के बाद अब साइमन मरांडी के बगावती तेवर ने शिबू को अपनों से बिल्कुल दूर कर दिया है. 2014 के लोकसभा चुनाव के पूर्व टिकट को लेकर विवाद में हेमलाल मुर्मू ने पार्टी छोड़ दी थी. फिलहाल वह राजमहल सीट से भाजपा के टिकट पर झामुमो प्रत्याशी विजय हासंदा को चुनौती दे रहे हैं. कुछ वर्ष पूर्व संथाल में शिबू सोरेन के नज़दीकी माने जाने वाले स्टीफन मरांडी ने भी टिकट के मसले पर मतभेद के बाद झामुमो त्याग दिया था.

अब राजमहल सीट से अपने पुत्र को टिकट न मिलने से साइमन मरांडी भी खफा बताए जा

शिबू सोरेन अपने क्षेत्र की सेवा का जज्बा लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं. उससे यह साफ है कि शिबू सोरेन अपनी राजनीतिक जमीन ताउम्र खोना नहीं चाहते. हाल के दिनों में झामुमो के मजबूत स्तंभों में से एक हेमलाल मुर्मू के पार्टी छोड़ने के बाद अब साइमन मरांडी के बगावती तेवर ने शिबू को अपनों से बिल्कुल दूर कर दिया है. 2014 के लोकसभा चुनाव के पूर्व टिकट को लेकर विवाद में हेमलाल मुर्मू ने पार्टी छोड़ दी थी. फिलहाल वह राजमहल सीट से भाजपा के टिकट पर झामुमो प्रत्याशी विजय हासंदा को चुनौती दे रहे हैं.

रहे हैं. नाराज साइमन ने चुनाव प्रचार से स्वयं को अलग कर लिया है और घर पर बैठ गए हैं. उनका कहना है कि यदि झामुमो प्रत्याशी हार जाते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी मेरे मथे मढ़ी जा सकती है और यदि जीत गए, तो उसका श्रेय भी मुझे नहीं मिलने वाला. ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद साइमन अपना राजनीतिक रिश्ता किसी और दल से जोड़ सकते हैं. यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है. इससे पूर्व भी संथाल में झामुमो को कई सदमों का सामना करना पड़ा है. झामुमो प्रमुख एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन संथाल परगना में एक से बढ़कर एक झटका खाने के बाद अब अकेले दम पर अपना गढ़ बचाने में जुटे नज़र आ रहे हैं. संथाल परगना दशकों तक झामुमो का गढ़



बना रहा, लेकिन अब यह गढ़ कमजोर होता दिख रहा है, क्योंकि किसी समय शिबू सोरेन के सहयोगी रहे लोग एक के बाद एक उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं. ऐसी स्थिति में अपना गढ़ बचाए रखना उनके लिए चुनौती बन गया है.

एक जमाने में एक-दूसरे के पूरक रहे सूरज मंडल ने सबसे पहले शिबू सोरेन का साथ छोड़ा. अलग राज्य बनने के पूर्व जब झारखंड में जैक का गठन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष शिबू सोरेन बने और सूरज मंडल उपाध्यक्ष बनाए गए. इसके अलावा, बिहार के लालू राज में दोनों ही नेता मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खास लोगों में शामिल थे. बाद में शिबू सोरेन के पुत्र दुर्गा सोरेन से न पटने के कारण सूरज मंडल ने न केवल पार्टी छोड़ी, बल्कि अपनी अलग पार्टी बना ली थी. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और रणनीतिकारों की रणनीति ऐसी बन रही है कि कोई भी तीर सही निशाने पर नहीं लग पा रहा है. अब शिबू सोरेन और उनके मुख्यमंत्री पुत्र हेमंत सोरेन के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है. पूरे संथाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा आधार वाली पार्टी मानी जाती है. आने वाले दिनों में देखना यह है कि झामुमो की प्रतिष्ठा बच पाती है या नहीं? ■

feedback@chauthiduniya.com



कमल मोरारका

»»

**भाजपा मुद्रास्फ़ीति नियंत्रित करने के लिए क्या करेगी? मुद्रास्फ़ीति बहुत है, भाजपा अपने हर विज्ञापन में इसकी बात कर रही है, इसे कम करने का वादा कर रही है. अब सवाल यह है कि आप इसके लिए करेंगे क्या? क्या मांग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फ़ीति है या आपूर्ति कम होना या फिर जमाखोरी इसकी बड़ी वजह है? क्या कारण है? इसकी एक बड़ी वजह है जमाखोरी और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही लोग भाजपा का समर्थन करते हैं. तब तो भाजपा कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगी. मुद्रास्फ़ीति एक ऐसा मुद्दा है, जिसका समाधान निकालने की ज़रूरत है. भाजपा को तुरंत पांच अर्थशास्त्रियों के एक पैनल की घोषणा कनी चाहिए, जो अपना दिमाग लगाकर एक खाका दें और बताएं कि कैसे वे मुद्रास्फ़ीति नियंत्रित करना चाहते हैं.**

इसी तरह सुरक्षा की चिंता और विदेश नीति का सवाल है. भाजपा के घोषणापत्र में, जो बहुत ढेर से आया, यह नहीं बताया गया है कि वह कैसे इन मुद्दों पर कुछ अलग करेगी. आज़ादी के बाद से, देश में सरकार के बदलाव से भी विदेश नीति कभी नहीं बदली. मोरारजी सरकार में भी विदेश नीति में परिवर्तन नहीं किया गया. देवगौड़ा और गुजराल सरकार आईं, तो भी विदेश नीति में परिवर्तन नहीं किया गया. माामुली परिवर्तन हुए, लेकिन बुनियादी परिवर्तन नहीं हुए. यहाँ भाजपा कहती है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब हैं. कांग्रेस की आलोचना करते हुए यह कहती है कि हम अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन यह नहीं बता रही है कि आखिर यह इस सबके लिए करेगी क्या? मुझे लगता है कि विकल्प सीमित हैं. अब यह उसे पता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम. अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. आप इस संबंध में क्या करने जा रहे हैं? क्या आप उसके साथ व्यापार बंद करेंगे या कम कर देंगे? चीन हमारे यहाँ अपने माल की डंपिंग कर रहा है. आपकी विदेशी मुद्रा चीन जा रही है. नरेंद्र मोदी चीन के फैन हैं. तो आप क्या करने जा रहे हैं? हम साल दर साल चालू खाता घाटा देख रहे हैं. उमर आप बोल रहे हैं कि एक डॉलर पचास या चालीस रुपये तक आ जाएगा. क्या आप विदेशी मुद्रा चीन को लौक करने की अनुमति देंगे? क्या खुदरा और अन्य जगहों पर अमेरिका से विदेशी निवेश होगा? खुदरा क्षेत्र में एफ़डीआई का बेशक वे सार्वजनिक रूप से खंडन करते हैं, लेकिन एफ़डीआई के मुक्त प्रवाह को स्वीकारने की बात भी कर रहे हैं. तो, हमारी अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक अमेरिकी पैसा आएगा और अनावश्यक आयात से अधिक से अधिक नुकसान. मैं नहीं जानता कि लोग कैसे इन चीयों को देखते-समझते हैं. हम सात अरब डॉलर का आयात कर रहे हैं. करीब 48 बिलियन डॉलर का हम सिर्फ़ सेल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात कर रहे हैं. क्या हम भारत में सेल फोन नहीं बना सकते? हम डॉलर में भुगतान करते हैं. सेल फोन के लिए हमें चीन की ज़रूरत है. कोई भी इसका समाधान नहीं देता.

कांग्रेस दस सालों से सत्ता में रहते हुए इसी नीति पर चलती रही, लेकिन अगर भाजपा सत्ता में आने की बात कर रही है, तो उसे जनता को आश्चस्त करना चाहिए कि वह कैसे कांग्रेस से अलग इन मुद्दों पर काम करेगी. नरेंद्र मोदी को पहली बात यह कहनी चाहिए कि वह चीन से अनावश्यक आयात रोकने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. नरेंद्र मोदी एक साल में तीन बार चीन की यात्रा करना पसंद करते हैं, उन्हें चीन से प्यार है. इसी तरह हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी नीति क्या होने वाली है? धमकी और अंध-राष्ट्रीयता तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और भारत भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है. तो, युद्ध विकल्प की संभावना बिल्कुल नहीं नहीं है. यह बात पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से जानता है और हम भी. लेकिन, जन्म में कुछ भाषणों में, बहुत आश्चर्य की बात है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि

—अक्षय यादव, *वाणसी, उत्तर प्रदेश.*

**आधार कार्ड के बहाने धोखा**

मनीष कुमार का आलेख-आधार कार्ड एक विशिष्ट घोटाला (7-13 अप्रैल) बताया है कि आधार कार्ड के बहाने किस प्रकार झारी समाज जानकारियों सार्वजनिक की जा रही है. आधार कार्ड के जन्मदाता नंदन नीलेकणी ने सरकार के साथ मिलकर देश के लोगों के साथ धोखा किया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी है और सरकार से कहा कि लोगों की जानकारियां किसी भी हातत में साझा नहीं की जानी चाहिए. नंदन नीलेकणी इस बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं. इस घोटाले की उच्च-तरीख जांच होनी चाहिए.

—कुलदीप मौर्य, *झांसी, उत्तर प्रदेश.*

# आप इस देश को कैसे चलाएंगे?



पाकिस्तान हमारे लिए एक खतरा है. कैसे? यहां तक कि पाकिस्तान को नहीं लगता कि यह हमारे लिए एक खतरा है. भारत में भी कोई नहीं सोचता कि पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है. मोदी ने ए के एंटी.ए, एके-47, एके-49 जैसी बातें कहीं. केजरीवाल को इतना और ऐसा महत्व दिया, मानों वह राष्ट्रीय सुरक्षा के नई अर्थ हैं. चिदंबरम मुद्रास्फ़ीति और दस सालों के शासन की वजह से मुसीबत में रहे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एक वित्त मंत्री के रूप में बहुत अच्छी तरह से काम किया. मैं नहीं जानता कि श्री मोदी के वित्त मंत्री इससे बेहतर क्या कर सकते हैं?

विश्व अर्थव्यवस्था युद्ध जों में, अमेरिका में मुसीबत में है. भारत इसकी तुलना में ज़्यादा बेहतर स्थिति में है. असल समस्या कुछ और है, जिसे नरेंद्र मोदी सामने नहीं ला रहे हैं और उसका समाधान नहीं बता रहे हैं. वह है, बैंकों का बढ़ता हुआ एनपीए (बैड लोन, जो वापस नहीं होता). निर्माण उद्योग और बिजली उद्योग बैंकों से मोटा ऋण ले लेते हैं, वे अपनी परियोजनाओं को पूरा नहीं करते और इस तरह न ब्याज चुकाते हैं और न ही लोन. इनमें से ज़्यादातर भाजपा के साथ हैं. वे भाजपा का साथ देते हैं. यही लोग हैं, जिन्होंने सबसे पहले भाजपा को अपना समर्थन देने की बात कही थी. इसका अर्थ है, ये कहेंगे कि हम आपका समर्थन करते हैं और हम ऋण वापस नहीं करेंगे. मतलब यह कि एक दिन उनका ऋण खत्म कर दिया जाएगा. असल समस्या काफी अलग है और इस समस्या का जितना सामना श्री चिदंबरम ने किया, उतना ही सामना श्री मोदी के वित्त मंत्री को भी करना होगा. भरे डिसाव से, इन मुद्दों पर बात करने और इनका समाधान निकालने का वक़्त आ गया है. 16 मई को हम सब परिणाम से वाकिफ़ हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक आदमी, जो गंभीरता से प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है और इस देश को चलायाना चाहता है, उसे इस देश को चलाने के तौर-तरीके का एक ब्लूप्रिंट देश की जनता के समक्ष रखना चाहिए और यह बताना चाहिए कि उसे आखिर क्यों इस देश की जनता का जनादेश मिलना चाहिए.■

कह रहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो हम किधर जाएंगे? आरएसएस बिल्कुल अपनी शाखाओं में वृद्धि करेगा, अगर यही लक्ष्य है, तो ऐसा होगा. उनकी 57 हजार शाखाओं की संख्या बढ़कर 40 हजार तक आ गई है, इसे फिर से बढ़ाया जाएगा. मोरारजी भाई

feedback@chauthiduniya.com

घिंतनीय है. किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता हो, वह विरोधी पार्टी के नेताओं पर बार कते समय एक बार भी नहीं सोचता कि वह अखिर बोल क्या रहा है. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, आजम खान, कांग्रेस के बेनी प्रसाद वर्मा, हसपा नेता एवं मुरादाबाद से लोकसभा उम्मीदवार हाजी याक़ूब के बोल तो सारी मर्बादाएं तोड़ रहे हैं. इसी वक़्त में भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी पर मुक़दमा हुआ और कांग्रेस के एक नेता जेल जा चुके हैं. चुनाव आगे ही बाहरी ताकतों की गोद में जा बेंठे हों, तब इस देश को धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और सांप्रदायिकता से कैसे बचाया जा सकता है? तरुण गौगोई एवं मुलायम सिंह का आश्चर्य निश्चित रूप से मिंदनीय है. जो विदेशी साजिशों के हिस्से बनते दिखाई दे रहे हैं. जब देश में मुसलमान गोलबंद होते हैं, जेहाद का नारा देते हैं, किसी राजनीतिक दल को हारने का फतवा जारी करते हैं, शरीयत को संविधान के ऊपर और देश की सार्वभौम पहचान को नकारते हुए इस्लाम को सर्वोपरि बताते हैं, तो उनके इस बर्ताव का इलाज असर अन्य धर्मांतरियों पर पड़ना लासिमी हो जाता है. और, जब नैर-मुसलमान समाजबंद होकर खड़े होते हैं, तब कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक हैं, इनसे देश की गंगा-जमुनी तटनीय को ख़तरा है, ये देश तोड़ने वाले हैं, इनसे लोकतंत्र को ख़तरा है.

—अजीत सिंह, *बलिया, उत्तर प्रदेश.*

**पाठक पूरा नाम, पता व फ़ोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :**

**चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301**

**नेताओं के घटिया बोल**

देश में राजनीति की दिशा जिस तरफ़ जा रही है, वह बेवद

# संपादकीय



संतोष भारतीय

दस अप्रैल को दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए. 6 सीटों पर विहार में भी वोट पड़े. कुल मिलाकर लगभग 91 सीटों पर वोट पड़े. मतदान का प्रतिशत शानदार रहा. इसकी जड़ में चुनाव आयोग का प्रचार, उसकी कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, तो धी ही और पिछले कुछ चुनावों से नौजवान मतदाताओं में वोट डालने का ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है. 18 से 24 साल के युवा अचानक चुनाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने लगे हैं. पहले चुनावों में कार्यकर्ता हुआ करते थे. उसके बाद पिछले 10-15 सालों में कार्यकर्ता की जगह दैनिक ख़र्चों पर काम करने वाले नौजवान चुनावों में इस्तेमाल होने लगे, पर दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव के बाद सारे देश में नए सिरे से नौजवान कार्यकर्ता पार्टियों को मिलने लगे. लोकसभा के इस चुनाव में तो नौजवान कार्यकर्ताओं ने भी अपने-अपने दलों में, चुनाव में हिस्सा लिया. मतदाताओं की युवा हिस्सेदारी ने बड़-बड़कर अपनी

# जीतने वालों से देश की अपेक्षा

भूमिका अदा की. अब यह नौजवानों का वोट, जो कि बड़ी संख्या में दे रहे हैं, जिसने मतदान का प्रतिशत 65 से 70 और 70 से 73 कर दिया, यह किमके पक्ष में जाएगा, अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह प्रतिशत नरेंद्र मोदी की प्रचार टीम अपने पक्ष में आया हुआ बता रही है. 11 अप्रैल की सुबह लगभग सभी महत्वपूर्ण पत्रकारों के पास यह जाकारी पहुंचाई जा चुकी थी कि दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद रूप से जीत रही है और सभी लोगों में नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान किया है. तो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है कि ऐसा हुआ हो. क्योंकि तो हुआ, यह तो 16 मई को इंडीएय में कैद आंकड़े सामने आने के बाद पता चलना. महत्वपूर्ण यह है कि 10 तारीख की शा 6 बजे मतदान समाप्त हुआ और 11 तारीख की सुबह 9 बजे तक विभिन्न स्रोतों से सारे पत्रकारों, महत्वपूर्ण



feedback@chauthiduniya.com

»»

**नई कहानी यह है कि मनमोहन सिंह की उपा-सीतना को नरेंद्र मोदी भुना रहे हैं. वह पार्टी के लिए एक परेशानी की तरह हैं, जो देश भर में फैल गए हैं. वहीं मोदी को भाजपा का मजबूत पक्ष माना जा रहा है. मोदी क्या करेंगे, यह कोई बहुत महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है, लेकिन उनका वक्तवा होना और सक्रिय होना, उन्हें मनमोहन सिंह के शांत रहने वाले तरीके से आगे ले जाता है. यहां पर कोई भी यह सवाल पूछ सकता है कि क्या मनमोहन सिंह को उनकी चुप्पी के लिए लगातार उनके कांग्रेसी साथियों द्वारा नहीं धकेला गया? उन्हें इसी कारण चुना ही जा सकता था, क्योंकि एक एक शांत व्यक्तिवर्ग के मालिक होने के साथ-साथ परिवार विशेष से कोई भी श्रेय जुटाया नहीं जा सकता है. उन्हें प्रधानमंत्री बनाया ही इसलिए गया था, क्योंकि वह उदासीन थे.**

2004 की परिस्थितियों के मुताबिक पार्टी के लिए वह सबसे ज़्यादा मुक्ति व्यक्तिव थे. पार्टी में अच्छे वक़्ताओं और नेताओं की की कमी नहीं थी, जिन्हें चुना जा सकता है. प्रणव कुमार और अर्जुन सिंह, दोनों ही नेता उस वक़्त मौजूद थे. अगर उस समय की प्रसंगिकताओं को परेशानी बन गई है, तो इसका मुख्य कारण परिवार है. परिवार ने ही उनका नाम प्रस्तावित किया था और परिवार ही उन्हें दुःखद रूप से



राजनेताओं और राव बनाने वालों के पास यह जानकारी किसी न किसी तरह पहुंचाई जा चुकी थी कि वह दौर नरेंद्र मोदी का है और तीसरे दौर की सीटें नरेंद्र मोदी के पक्ष में 95 प्रतिशत से ज़्यादा जा रही हैं.

यही सफलता है. नरेंद्र मोदी ने 10 हजार करोड़ रुपये प्रचार में खर्च किए या नहीं खर्च किए, यह बहस का विषय है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अगर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए, तो वे दिमाग के साथ खर्च हुए. जबकि दूसरी तरफ़ अगर हजार करोड़ रुपये भी खर्च हुए, तो वेबकूफ़ी से खर्च हुए, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में कोई प्रचार हुआ दिखाई ही नहीं दिया. कांग्रेस ने पिछले 10 साल में अच्छे काम किए, हालांकि उनके नतीजे अच्छे नहीं दिखाई दिए. एक सूचना के अधिवार को छोड़ दे, तो बाकी सारे कानून भ्रष्टाचार के पक्ष में बदर करते दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी युद्ध को जिना लड़े ही छोड़ दिया और चुनाव के बीच में अपने सिपहसालारों को यह कहने दिया कि कांग्रेस तो धारणा के त्तर पर चुनाव हार गई है. जयराम रमेश, पी चिदंबरम और ए के एंटी.ए से लोगों में प्रमुख हैं, जिन्होंने कांग्रेस की संभावनाओं को समाप्त करने का उद्योग किया और कांग्रेस ने उन्हें कोई सजा नहीं दी. ये तीनों लोग कांग्रेस की विधिन कमेटियों के सदस्य हैं और अभी भी पी चिदंबरम एवं ए के एंटी.ए सोनिया गांधी की और जयराम रमेश राहुल गांधी की ताक के बाल बचे हुए हैं. ऐसे लगता है कि जैसे कांग्रेस के भीतर न राजनीतिक सोच बची है और न युद्ध लड़ने की जिजीविषा. कांग्रेस ने जिस जापानी कंपनी को प्रचार अभियान का ठेका सौंपा, ऐसा लगता है कि उसमें से 50 प्रतिशत धनराशि कमीशन के तौर पर वापस ले ली गई. यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन कंपनी ने जिन भारतीय सहयोगियों को अपने साथ रखा, उन्हें यह समझ में ही नहीं आया कि इलेक्शन कैंपन कैसे आगेगाइज करते हैं. शायद दूसरा कारण यह भी रहा हो कि राहुल गांधी ने किसी आदमी को यह ज़िम्मा नहीं सौंपा कि कैंपन की बुनियादी शक्ल क्या हो. यह सिर्फ़ और सिर्फ़ नरेंद्र मोदी की बातों का भौंडा जवाब देने की कोशिश करते दिखाई दिए.

कांग्रेस ने क्यों हथियार डाले, इसके कई कारण हो सकते हैं. पहला कारण है कि जब सोनिया गांधी ने यह तय किया कि राहुल गांधी कांग्रेस के भावी नेता होंगे, तब सोनिया गांधी की टीम ने काम करना बंद कर दिया और राहुल गांधी की टीम ने काम कैसे करें, यही सोचने में अपना सारा समय बर्बाद कर दिया. वे काम कर ही नहीं पाए. सत्ता हस्तांतरण की भी एक प्रक्रिया होती है, पर यह मानना कि राहुल गांधी में इतनी भी समझ नहीं है कि मिली हुई ताकत का इस्तेमाल कैसे करें, इस पर विश्वास नहीं होता. राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास सारे विकल्प खुले हैं. कांग्रेस के लोगों में उसाह भरने का विकल्प था, पार्टी को मजबूत करने का विकल्प था, अपने प्रमुख लोगों को चुनाव लड़ लगाने का विकल्प था जो चुनाव अभियान संयोजित करते, उन्हें राज्सभा का वादा देकर पार्टी के काम में लगाने का विकल्प था, लेकिन कोई इलेक्शन होती दिखाई नहीं दी.

दूसरी तरफ़ नरेंद्र मोदी पिछले तीन साल से चुनाव लड़ रहे हैं. तीन साल का मतलब, जबसे उन्होंने गुजरात टूरिज्म का ब्रांड अंबेसडर अभिताम बच्चन को बनाया, जिन्होंने गुजरात-गुजरात-गुजरात-गुजरात और फिर नरेंद्र मोदी का गुजरात जैसे क्रमशः प्रचार अभियान की तीयता बढ़ाई. नरेंद्र मोदी ने अपने प्रथम श्रेणी के आईएएस अफसरों को पूरे चुनाव की देखरेख का ज़िम्न नियुक्त किया. नरेंद्र मोदी ने कहीं भी अपने सार्वनीयक कार्यकर्ताओं पर सरोसा नहीं किया. सिर्फ़ एक अरबाद अमित शाह हैं, जिन्हें उन्होंने महीनों पहले उत्तर प्रदेश में भेज दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की गुटबंदी है और जिस तरह से पार्टी के भीतर अंतर्विरोध हैं, उसका मुकाबला वह उत्तर प्रदेश के ही किसी

editor@chauthiduniya.com

# आरोपों का खेल

इतिहाम के कूड़ेदान में डाल रहा है. यही बताया है कि मोदी की सफलता का राज क्या है? वर्तमान समय के अनुवात कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को छोड़कर उस बात की सहमति कईयों में है कि मोदी एक चमत्कारिक कार्यकर्ता हैं. चूंकि सिर्फ़ मनमोहन सिंह को मुद्रास्फ़ीति और आर्थिक विकास घटने के लिए आरोपित किया जाता है, इसलिए मोदी से यह आगा है कि वह तेजी से आर्थिक विकास करने की बात है, तो हमें उनके विजन और योजनाओं के बारे में विस्तार में जानना होगा, जिसकी हर आदमी उससे अपेक्षा कर रहा है. आगामी 17 मई को जब भाजपा नीत एनडीए सरकार बनाने की

»»

**पी चिदंबरम ने लोकसभा में जो पेश किया था, वह चुनावी बजट था. जो बात हम पहले से जानते हैं, वह यह है कि 2013-14 के घाटे का परिणाम 4.6 प्रतिशत से ज़्यादा है. आने वाले वर्ष वित्सयकारी होंगे, क्योंकि अनियोजित खर्च ज़्यादा है और आय भी कम है. हम इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2014-15 का बजट घाटा अप्रत्याशित रूप से कम होगा. हालांकि, अभी हम यह नहीं जानते हैं कि आगामी वित्त मंत्री कौन होगा? कुछ नामों की चर्चा तो है, जैसे अरुण जेठली और मनोहर पारिहार. चाहे जो भी वित्त मंत्री हों, लेकिन अभी बजट से पहले उसके पास आर्थिक विकास के कम ही रास्ते होंगे. जो भी वित्त मंत्री बने, उसके लिए यह सबसे बढ़िया सनाह है कि वह**

feedback@chauthiduniya.com

»»

**कांग्रेस ने क्यों हथियार डाले, इसके कई कारण हो सकते हैं. पहला कारण है कि जब सोनिया गांधी ने यह तय किया कि राहुल गांधी कांग्रेस के भावी नेता होंगे, तब सोनिया गांधी की टीम ने काम करना बंद कर दिया और राहुल गांधी की टीम ने काम कैसे करें, यही सोचने में अपना सारा समय बर्बाद कर दिया. वे काम कर ही नहीं पाए. सत्ता हस्तांतरण की भी एक प्रक्रिया होती है, पर यह मानना कि राहुल गांधी में इतनी भी समझ नहीं है कि मिली हुई ताकत का इस्तेमाल कैसे करें, इस पर विश्वास नहीं होता. राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास सारे विकल्प खुले थे. कांग्रेस के लोगों में उसाह भरने का विकल्प था, पार्टी को मजबूत करने का विकल्प था, अपने प्रमुख लोगों को चुनाव लड़ लगाने का विकल्प था जो चुनाव अभियान संयोजित करते, उन्हें राज्सभा का वादा देकर पार्टी के काम में लगाने का विकल्प था, लेकिन कोई इलेक्शन होती दिखाई नहीं दी.**

दूसरी तरफ़ नरेंद्र मोदी पिछले तीन साल से चुनाव लड़ रहे हैं. तीन साल का मतलब, जबसे उन्होंने गुजरात टूरिज्म का ब्रांड अंबेसडर अभिताम बच्चन को बनाया, जिन्होंने गुजरात-गुजरात-गुजरात-गुजरात और फिर नरेंद्र मोदी का गुजरात जैसे क्रमशः प्रचार अभियान की तीयता बढ़ाई. नरेंद्र मोदी ने अपने प्रथम श्रेणी के आईएएस अफसरों को पूरे चुनाव की देखरेख का ज़िम्न नियुक्त किया. नरेंद्र मोदी ने कहीं भी अपने सार्वनीयक कार्यकर्ताओं पर सरोसा नहीं किया. सिर्फ़ एक अरबाद अमित शाह हैं, जिन्हें उन्होंने महीनों पहले उत्तर प्रदेश में भेज दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की गुटबंदी है और जिस तरह से पार्टी के भीतर अंतर्विरोध हैं, उसका मुकाबला वह उत्तर प्रदेश के ही किसी

नेता के जरिये नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र अमित शाह को भेजा. नरेंद्र मोदी की रणनीति खासी सफल रही. कम से कम नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान कहीं पर भी कमजोरी से नहीं चला और उसने सारे देश में भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के तौर पर इतलेवेए (अप्रसंगिक) कर दिया. पार्टी का कोई भी बड़ा नेता देश में चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है. सारे लोग अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में घुरे हुए हैं. सिर्फ़ एक शख्स सारे देश में प्रचार कर रहा है और कह रहा है कि तुम मुझे खंडन दो, मैं तुम्हें बदलाव दूंगा, सुशासन दूंगा, स्वराज्य दूंगा और वह शख्स नरेंद्र मोदी हैं. नरेंद्र मोदी ने ऐसा खर्च करने में भी कौताही नहीं बली. उन्होंने उन सारे वार्गों, जो हिंदू समाज के साथ नहीं आते हैं, को अपने साथ खड़ा करने के लिए साम, दाम, दंड, भेरे की नीति अपनाई और सफलतापूर्वक मुसलमानों में भी यह संदेश भेज दिया कि अगर वे नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, तो ज़्यादा सुखी रहेंगे और कांग्रेस के साथ रहेंगे, तो दुःखी होंगे. मुसलमानों में भी कम्यूनन बड़ा है, लेकिन यह कम्यूनन कांग्रेस को काँड़ फ़ायदा नहीं दे रहा है, बल्कि अलग-अलग वार्गों पर अलग-अलग फ़ायदे दे रहा है. उत्तर प्रदेश में यह समाजवादी पार्टी की बदर कर रहा है और बिहार में अब यह लालू चंदब एवं नीतीश कुमार के साथ आया. कांग्रेस के साथ कम से कम इन दो प्रदेशों में पैसा होना नहीं दिख रहा है.

अतः कांग्रेस ने जहाँ जिना लड़े चुनावी युद्ध की कमान छोड़ दी है, वहाँ अब वह जनता के विवेक पर है कि वह वादों की असंभव पघचान कर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होती है या वादों को इंगनदारी से न बोलने वाली कांग्रेस के साथ या फिर श्रेणीय दलों के साथ जाती है. चारे जो जीते, लेकिन देश जीतना, यह मानना चाहिए और जो जीते, उसे देश के लिए काम करना चाहिए. इतनी छोटी सी अपेक्षा तो हमें जीतने वालों से कनी ही चाहिए.■

# पाठकों की दुनिया



**सबके निशाने पर मोदी**

राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए, तो हर तरफ़ मोदी की चर्चा सुनाई देती है. एनडीए में शामिल पार्टियों में उसाह देखते ही बनता है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के पक्ष में चल रही यह हवा वोटों में परिवर्तित हो पाएगी? यदि ऐसा हुआ, तो नरेंद्र मोदी की अनुयायियों में चुनाव लड़ रही भाजपा को पिछनी बार से अधिक सीटें मिल सकती हैं. नरेंद्र मोदी विरोधी पार्टियों के निशाने पर हैं और मोदी के खिलाफ़ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. छै. 16 मई को मानगानार के बाद स्वको पता चल पारगा कि कौन बाजी मारता है, मोदी या कोई और?

—अक्षय यादव, *वाणसी, उत्तर प्रदेश.*

**झूठ का पुलिंदा**

आलेख-वादे हैं वादों का क्या (7-13 अप्रैल) पढ़ा. शशि शेखर ने सच कहा कि चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणापत्र जारी तो करती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करतीं. कांग्रेस ने भी यही किया. उसने 2004 के आम चुनाव से पहले जो वादे जनता से किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया. कांग्रेस की अनुवाई वाली केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में केवल घोटालों का रिकार्ड बनाया है. जनता को अब सदा नहीं, काम चाहिए. जो काम करेगा, वहीं चुनाव भी जीतेगा.

नेहा सिंह, *स्वातिनगर, मध्य प्रदेश.*

**तीसरा मोर्चा एक दिखावा**

आलेख-तीसरे मोर्चे की सरकार की संभावना बहुत कम (7-13 अप्रैल) में ए वू आसिफ़ ने सही कहा है कि तीसरे मोर्चे में जो पार्टियां शामिल हैं, उनकी स्थिति अपने-अपने दलों में ही खराब है. वाममोर्चा की स्थिति परिवर्ण बंगाल, केरल एवं पूर्वोत्तर में अच्छी नहीं है, जदयू की हालत बिहार में अच्छी नहीं है, समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है. सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे मोर्चे में पीएम पद के कई दावेदार हैं.

तीसरा मोर्चा अगर चुनाव में कोई कामयाबी हासिल करता है, तब भी उसकी सरकार बनना मुश्किल नजर आता है.

—दीपक कुमार, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*





संजय सक्सेना

फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता एवं विदेश मंत्री सलमान खुरशीद के मुकाबले के लिए भाजपा ने कल्याण के क्रीबी मुकेश राजपूत पर दांव लगाया है. मुकेश राजपूत को टिकट देने का विरोध भी हुआ था, इसलिए कल्याण को यहां अपनी साख बचानी होगी.



ब्रज की 12 सीटों पर मुकाबला 24 को

# सपा, हेमा, अमर और जयंत की किस्मत दांव पर

उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की सियासी जंग की पटकथा ब्रजभूमि में लिखी जाएगी. तीसरे चरण में 24 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान होगा. राजनीतिक धुरंधरों, उनकी बहू-बेटी, एक सिने-तारिका के अलावा कभी समाजवादी पार्टी के लिए अमर कथा लिखने वाले एक नेता जी की भी अग्निपरीक्षा होगी. भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां सपा ने 12 में से चार, कांग्रेस ने तीन, राष्ट्रीय लोकदल ने दो और भाजपा-बसपा ने एक-एक सीट पर फतह हासिल की थी. 24 अप्रैल को आगरा (सुरक्षित), फतेहपुर सीकरी, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, हाथरस (सुरक्षित), एटा, हरदोई (सुरक्षित), फर्रुखाबाद, इटावा (सुरक्षित), कन्नौज और अकबरपुर में मतदान होगा. फ़िरोज़ाबाद एवं हाथरस ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं, जिनके मौजूदा सांसद इस बार मैदान बदल कर ताल ठोक रहे हैं. फ़िरोज़ाबाद के सांसद एवं गुजरे जमाने के फिल्म स्टार राज बब्बर इस बार गाज़ियाबाद और हाथरस की मौजूदा रालोद सांसद सारिका सिंह बघेल सपा के टिकट पर आगरा से चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं एटा के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपनी जगह बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है. इन 12 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने वाले प्रमुख चेहरों में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव मैनपुरी, उनकी बहू एवं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज, सपा महासचिव एवं मुलायम के चचेरे भाई रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव फ़िरोज़ाबाद से, अमर सिंह रालोद के टिकट पर फतेहपुर सीकरी, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमामालिनी भाजपा के टिकट पर मथुरा, अजित सिंह के पुत्र जयंत चौधरी, कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुरशीद फर्रुखाबाद, बसपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य मैनपुरी आदि शामिल हैं. यहां आम आदमी पार्टी ने पूर्व नौकरशाह बाबा हरदेव को सपा प्रमुख को



आगरा की सीट पर इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद रामशंकर कठेरिया, बसपा के श्रीनारायण सिंह, कांग्रेस के उपेंद्र जाटव, सपा के महाराज सिंह और आप के रवींद्र के बीच है. आगरा की सीट पर भाजपा का खासा प्रभाव है, तो बसपा का वोट बैंक भी यहां कम नहीं है. फ़िरोज़ाबाद में सपा के थिंक टैंक प्रो. रामगोपाल के पुत्र अक्षय यादव मैदान में हैं, जिनसे मुकाबले के लिए भाजपा ने बसपा के कद्दावर नेता एवं राज्यसभा सदस्य एसपी सिंह बघेल को पार्टी में शामिल कर मैदान में उतारा है. बघेल सपा और बसपा होते हुए भाजपा में आए हैं और सपा-बसपा से सांसद रह चुके हैं. बसपा और सपा की काट क्या है, यह बघेल अच्छी तरह जानते हैं. कांग्रेस ने उद्योगपति अतुल चतुर्वेदी और बसपा ने ठाकुर ब्रजराज सिंह के पुत्र डॉ. विश्वदीप सिंह को मैदान में उतारा है, जिनकी नज़र ठाकुर वोट बैंक पर है.

चुनौती देने के लिए उतारा है. फतेहपुर सीकरी में बसपा नेता रामवीर उपाध्याय की पत्नी एवं मौजूदा सांसद सीमा उपाध्याय की टक्कर रालोद के अमर सिंह से बताई जा रही है. सपा प्रमुख मुलायम सिंह के प्रधानमंत्री बनने का सपना कितनी दूर तक जा सकता है, यह मैनपुरी और उसके आसपास की 12 सीटों के संकेत से काफी कुछ तय हो जाएगा.

ब्रज क्षेत्र की सियासी गणित काफी उलझी

हुई है. जाट बाहुल्य इस इलाके में राष्ट्रीय लोकदल भी एक फैक्टर की तरह मौजूद है. आम आदमी पार्टी को लोग तरजीह तो दे रहे हैं, लेकिन वोटकुटा से अधिक नहीं. वैसे उसने यहां कई अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं. समीकरणों को समझना आसान न होगा. पिछले दो सालों में सियासी चक्रवात रुख बदल रहे हैं. मथुरा सीट से पिछली बार भाजपा के गठबंधन से जीते रालोद नेता एवं चौधरी अजित सिंह के पुत्र जयंत चौधरी के रास्ते में इस बार भाजपा ने ही सिल्वर स्क्रीन की बाधा खड़ी कर दी है. जयंत के समर्थक हेमा का विरोध बाहरी बताते हुए कर रहे हैं, लेकिन रालोद की चुनौती कम नहीं हो रही है. जयंत को मोदी की हवा और हेमा के कद ने परेशान कर रखा है. मथुरा में क्या होगा, यह चौक-चौराहों और पान की दुकानों पर चर्चा का विषय बना हुआ है. कांग्रेस गठबंधन के साथ मैदान में उतरी रालोद ने कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए जाट आरक्षण को मुद्दा बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने उसकी हवा निकाल दी. बसपा के योगेश द्विवेदी, सपा के चंदन सिंह और आप के अनुज मथुरा की लड़ाई अपने हिसाब से रोचक बनाए हुए हैं.

देश भर के लोग आगरा के फतेहपुर सीकरी में इबादत करने आते हैं. यहां श्रेष्ठ सलीम चिश्ती की विश्व प्रसिद्ध दरगाह पर मत्था टेकने वालों का हुजूम लगा रहता है. रालोद नेता अमर सिंह ने भी यहां आकर मत्था टेककर जीत की दुआ ज़रूर मांगी होगी. अमर सिंह यहां से बसपा की मौजूदा सांसद सीमा उपाध्याय को परास्त करके मायावती और सपा की रानी पक्षालिका सिंह को हराकर मुलायम से अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं. अमर सिंह भले ही रालोद के टिकट से मैदान में हों, लेकिन आज भी उनकी पहचान यही है कि कभी उनके इशारे पर सपा सरकार चलती थी. इस बार अमर सिंह के सारथी बने हैं रालोद के अजित सिंह, जिनके गुणगान करते वह थक नहीं रहे हैं. रालोद के जाट वोट बैंक की अच्छी मौजूदगी और ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण अमर सिंह को अपनी राह में कोई रुकावट नहीं नज़र आ रही है. सपा ने भदावर राजघराने की रानी एवं प्रदेश के मंत्री अरिंदमन सिंह की पत्नी पक्षालिका सिंह को उतार कर मुकाबला रोचक बना दिया. बसपा प्रत्याशी एवं वर्तमान सांसद सीमा उपाध्याय का अपना गणित है. वह अपने हिसाब से जाति का

गुणा-भाग कर रही हैं. रालोद प्रत्याशी के लिए जाट वोट बैंक की मुश्किल खड़ी की है भाजपा के चौधरी बाबूलाल ने और मोदी लहर उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है.

आगरा की सीट पर इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद रामशंकर कठेरिया, बसपा के श्रीनारायण सिंह, कांग्रेस के उपेंद्र जाटव, सपा के महाराज सिंह और आप के रवींद्र के बीच है. आगरा की सीट पर भाजपा का खासा प्रभाव है, तो बसपा का वोट बैंक भी यहां कम नहीं है. फ़िरोज़ाबाद में सपा के थिंक टैंक प्रो. रामगोपाल के पुत्र अक्षय यादव मैदान में हैं, जिनसे मुकाबले के लिए भाजपा ने बसपा के कद्दावर नेता एवं राज्यसभा सदस्य एसपी सिंह बघेल को पार्टी में शामिल कर मैदान में उतारा है. बघेल सपा और बसपा होते हुए भाजपा में आए हैं और सपा-बसपा से सांसद रह चुके हैं. बसपा और सपा की काट क्या है, यह बघेल अच्छी तरह जानते हैं. कांग्रेस ने उद्योगपति अतुल चतुर्वेदी और बसपा ने ठाकुर ब्रजराज सिंह के पुत्र डॉ. विश्वदीप सिंह को मैदान में उतारा है, जिनकी नज़र ठाकुर वोट बैंक पर है.

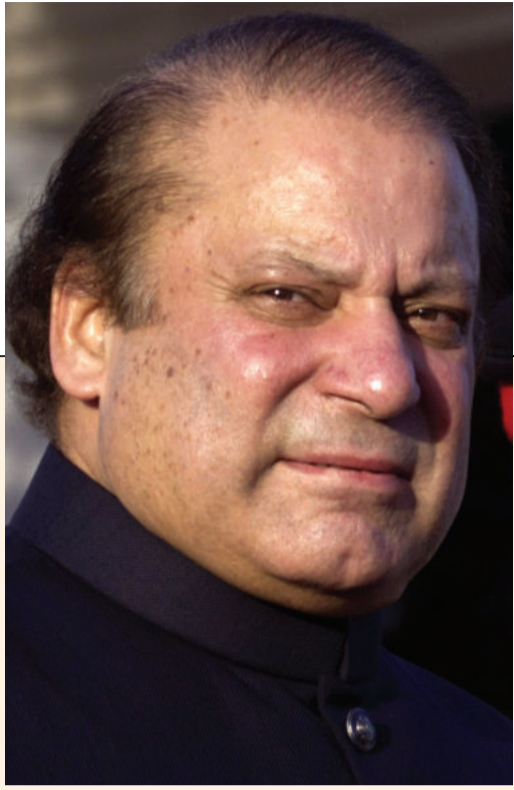
एटा से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र राजवीर सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन साख कल्याण सिंह की दांव पर लगी है. यहां राजवीर की राह रोकने के लिए सपा ने पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव और बसपा ने नूर मोहम्मद को उतारा है. यह कुर्मी बाहुल्य इलाका कल्याण सिंह का गढ़ माना जाता है. यहां कांग्रेस का कोई नामलेवा नहीं है और गठबंधन में पार्टी ने यह सीट अपने सहयोगी दल के लिए छोड़ दी है. यहां का सारा ताना-बाना कल्याण के इर्द-गिर्द घूम रहा है. कल्याण को इस क्षेत्र से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भाजपा के लिए जीतकर यह साबित करना होगा कि वह मुलायम का चक्रव्यूह तोड़ने में सक्षम हैं. फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता एवं विदेश मंत्री सलमान खुरशीद के मुकाबले के लिए भाजपा ने कल्याण के क्रीबी मुकेश राजपूत पर दांव लगाया है. मुकेश को टिकट देने का विरोध भी हुआ था, इसलिए कल्याण को यहां अपनी साख बचानी होगी. मुकेश और राजवीर पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, जिससे भाजपाई जीत को लेकर आशंकित नज़र आते हैं. यहां से बसपा के जयवीर सिंह भी मैदान में हैं. सपा ने भाजपा की राह रोकने के लिए अपनी पहली

प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री रहे नरेंद्र सिंह यादव के बेटे को टिकट दिया था, लेकिन बाद में एटा ज़िले की अलीगंज सीट से सपा विधायक रामेश्वर यादव को टिकट थमा दिया गया. देश में चल रही कांग्रेस विरोधी लहर से सलमान के माथे पर बल पड़े हैं, वहीं बसपा राजनीतिक गणित बैठाने में लगी है.

हाथरस में बसपा से मनोज सोनी, भाजपा से राजेश दिवाकर, सपा से रामजीलाल सुमन, रालोद से निरंजन सिंह धनगर मैदान में हैं. हाथरस की मौजूदा सांसद सारिका आगरा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. मैनपुरी में अब कोई चमत्कार न हुआ, तो मुलायम की जीत पक्की है. मुलायम को चुनौती देने के लिए भाजपा ने एसएस चौहान को उतारा है, लेकिन उनके नाम पर पार्टी बंटी हुई नज़र आ रही है. बसपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री डॉ. संघमित्रा मौर्य के जरिये मुलायम को चुनौती दी है. लेकिन संघमित्रा के लिए राह आसान नहीं है. आप ने रालोद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरदेव सिंह को मैदान में उतारा है. इटावा सुरक्षित सीट सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव एवं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए नाक का सवाल है. यहां सपा से वर्तमान सांसद प्रेमदास कठेरिया ही प्रत्याशी हैं, जिनसे जनता नाराज़ चल रही है, लेकिन मुलायम और अखिलेश अपना वास्ता देकर मतदाताओं से सपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं. भाजपा ने यहां अशोक दोहरे को प्रत्याशी बनाया है, जो हाल में बसपा छोड़कर आए हैं. पार्टी की हसंभव कोशिश है कि सुखदा मिश्रा के बाद वह मुलायम के गढ़ में एक बार फिर कमल खिलाए, लेकिन मुलायम के धोबी पाट दांव से भाजपाई सहमे हुए हैं. कन्नौज में विकास खूब हुआ है. यहां से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में हैं. उनकी जीत में शायद ही कोई प्रत्याशी बाधा बन पाएगा. हरदोई में सपा ने मौजूदा सांसद ऊषा वर्मा को मैदान में उतारा है. इस बार भाजपा और बसपा दोनों उनका खेल बिगाड़ने में लगे हैं. अकबरपुर सीट इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में दिख रही है. कांग्रेस के मौजूदा सांसद राजाराम पाल को कांग्रेस विरोधी लहर के चलते भाजपा के देवेंद्र सिंह भोले और सपा-बसपा प्रत्याशियों से पार पाना आसान नहीं लग रहा है. ■



अमर सिंह यहां से बसपा की मौजूदा सांसद सीमा उपाध्याय को परास्त करके मायावती और सपा की रानी पक्षालिका सिंह को हराकर मुलायम से अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं. अमर सिंह भले ही रालोद के टिकट से मैदान में हों, लेकिन आज भी उनकी पहचान यही है कि कभी उनके इशारे पर सपा सरकार चलती थी. इस बार अमर सिंह के सारथी बने हैं रालोद के अजित सिंह, जिनके गुणगान करते वह थक नहीं रहे हैं.



चंद्रबाबु नायडू

नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कई बयान भी दिए। भारत की बात करें, तो पिछले 10 वर्षों से यहां कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार है। अगली सरकार के चुनाव के लिए मतदान का दौर शुरू हो चुका है और 16 मई को यह साफ़ हो जाएगा कि देश की सत्ता किसके पास जाने वाली है।



## आम चुनाव

# मोदी और पाकिस्तान

चुनावी सभाओं के दौरान नरेंद्र मोदी ने भी कई बार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े स्वरों का इस्तेमाल किया। लेकिन, यह गौर करने वाली बात है कि दोनों देशों के चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए एक-दूसरे के खिलाफ इस तरह के सख्त कदम उठाने की बात कही जाती रही है। इससे यह मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पाकिस्तान के प्रति उनका रवैया एक दुश्मन मुल्क के रूप में रहेगा।

में इस बात की चर्चा थी कि अगर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पाकिस्तान के साथ संबंधों में खटास का दौर शुरू हो सकता है। हालांकि, भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। पाकिस्तानी मीडिया में यह बात संभवतः नरेंद्र मोदी की छवि को देखते हुए कही गई। चुनावी सभाओं के दौरान नरेंद्र मोदी ने भी कई बार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े स्वरों का इस्तेमाल किया। लेकिन, यह गौर करने वाली बात है कि दोनों देशों के चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए एक-दूसरे के खिलाफ इस तरह के सख्त कदम उठाने की बात कही जाती रही है। इससे यह मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पाकिस्तान के प्रति उनका रवैया एक दुश्मन मुल्क के रूप में रहेगा।

भारत-पाकिस्तान के आपसी संबंधों को विस्तार से देखने की कोशिश करें, तो जनवरी 2013 में अमेरिकी थिंक टैंक ने दोनों देशों के 30 विशेषज्ञों की बैठक दुबई में बुलाई थी। इस बैठक का मकसद था, आपस में विचारों को साझा करना, आपसी मुद्दों एवं चुनौतियों को जानना, किन मुद्दों पर सहमति हो सकती है उनकी पहचान करना और यह भी कि नीति, रणनीति एवं शोध आदि के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यह बैठक दोनों देशों के साथ संबंधों को लेकर फिर वार्ता शुरू करने की दिशा में काफी अहम मानी जा रही थी। इसी बैठक के पांच महीने बाद मई में जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी बयान दिया था कि वह भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना चाहते हैं और भारत के साथ-साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वह रिश्तों की उस डोर को पकड़ेंगे, जिसे 1999 में हमने छोड़ दिया था।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में किसी भी नागरिक सरकार ने भारत के प्रति स्वतंत्र नीति बनाने की टोस पहल नहीं की। उसमें सेना का हस्तक्षेप हमेशा से रहा है। अगस्त 1999 में नवाज शरीफ ने दिल्ली से लाहौर के लिए बस चलाने की अनुमति के जरिये एक शुरुआत करने की कोशिश की थी। ऐसा लगा था कि दोनों देशों के संबंधों में एक नए युग की शुरुआत हो रही है, लेकिन चंद महीने के भीतर ही जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाक सेना ने उसका गला घोट दिया। करगिल की घटना हुई। अब एक बार फिर शरीफ ने भारत के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की पहल की है। हालांकि, पाक की तरफ से इस तरह के बयान कई बार दिए जा चुके हैं। भारत का कहना था कि पाकिस्तान को वार्ता करने से पहले आतंकवाद जैसे मुद्दों पर टोस आदि करके एक भरोसा पैदा करने की आवश्यकता है। बहरहाल, अगर पाकिस्तान की तरफ से यह बयान आता है कि आम चुनाव के बाद भारत में किसी भी पार्टी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनें या कोई और, वह साथ काम करने को तैयार है, तो इसे सकारात्मक कदम ही माना जाना चाहिए।

feedback@chauthiduniya.com



भारत-पाकिस्तान के आपसी संबंधों को विस्तार से देखने की कोशिश करें, तो जनवरी 2013 में अमेरिकी थिंक टैंक ने दोनों देशों के 30 विशेषज्ञों की बैठक दुबई में बुलाई थी। इस बैठक का मकसद था, आपस में विचारों को साझा करना, आपसी मुद्दों एवं चुनौतियों को जानना, किन मुद्दों पर सहमति हो सकती है उनकी पहचान करना और यह भी कि नीति, रणनीति एवं शोध आदि के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यह बैठक दोनों देशों के साथ संबंधों को लेकर फिर वार्ता शुरू करने की दिशा में काफी अहम मानी जा रही थी।

वर्ष 1947 भारतीय इतिहास के पन्नों में अगर स्वर्णाक्षरों से अंकित है, तो इसी इतिहास का एक स्याह पन्ना भी इस पर दर्ज है। भारत की आज़ादी के साथ-साथ यह वर्ष बंटवारे का दर्द भी लेकर आया था। भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश अस्तित्व में आए थे। लेकिन, अपने जन्म के साथ ही इन दोनों पड़ोसी देशों का आपसी रिश्ता कभी भी सामान्य नहीं रहा। आलम यह है कि अभी तक दोनों देशों के बीच तीन लड़ाइयां हो चुकी हैं और छह जंग तो अक्सर चलती रहती है। कश्मीर युद्ध से लेकर शुरू हुआ यह विवाद आज आतंकवाद तक पहुंच चुका है। दोनों के रिश्ते इस क़दर ख़राब हैं कि 66 वर्षों से बातचीत होने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। पिछले कुछ वर्षों में संबंधों को पटरी पर लाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन हर बार कोई ऐसी घटना घट जाती, जिससे वार्ता स्थगित करनी पड़ती। कई बार आतंकी घटनाओं की वजह से वार्ता स्थगित करनी पड़ी। बाद में इस बात की आलोचना भी होने लगी कि यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो फिर उसके साथ वार्ता क्यों की जाए?

साल 2003 में इसी संदर्भ में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। यह सच भी है। हालांकि, अब मसला इससे भी आगे निकल चुका है। उसके बाद से पाकिस्तान कई प्रधानमंत्रियों को देख चुका है। पाकिस्तान में पहली बार किसी चुनी हुई सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिलहाल नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की



दिशा में कई बयान भी दिए। भारत की बात करें, तो पिछले 10 वर्षों से यहां कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार है। अगली सरकार के चुनाव के लिए मतदान का दौर शुरू हो चुका है और 16 मई को यह साफ़ हो जाएगा कि देश की सत्ता किसके पास जाने वाली है। अगर हालिया रुझानों और मीडिया रिपोर्टों को देखें, तो देश में भाजपा के नरेंद्र मोदी की लहर बताई जा रही है।

इसी संदर्भ में पाकिस्तान का हालिया बयान आया कि भारत में आम चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए वह तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तसनीम असलम की तरफ से कहा गया कि भारत की जनता नए नेता का चुनाव करेगी। नई दिल्ली में किसी की भी सरकार बने, पाकिस्तान को उससे किसी तरह की समस्या नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से यह बयान काफी महत्व रखता है, क्योंकि पिछले दिनों वहां के मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में भारत ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की है, चाहे वह सॉफ्टवेयर दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा भारतीय मूल के सत्या नडेला को सीईओ पद पर नियुक्त करना हो या फिर पिछले साल ओबामा प्रशासन द्वारा भारतीय मूल के दर्जन भर से अधिक लोगों की व्हाइट हाउस में नियुक्ति का मामला। इन सभी घटनाक्रमों ने भारत के पड़ोसी देश चीन की चिंता बढ़ा दी है। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में एक नई राजनीति को जन्म दिया। यह वही दौर था, जब भारत में आर्थिक उदारीकरण के बीज पड़ने शुरू हो गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। 1991 के पहले यानी



शीतयुद्ध काल में दुनिया के तमाम मुल्क मुख्य तौर पर दो धड़ों में बंटे थे। एक गुट सोवियत संघ की अगुवाई वाला कम्युनिस्ट देशों का था, तो दूसरी ओर पूंजीवाद का झंडाबंदरदार अमेरिका नेतृत्व की भूमिका में था। हालांकि, एक ओर खेमा था, जो किसी भी गुट में नहीं था। यह कहलाया गुटनिरपेक्ष देशों का समूह। भारत, मिस्र, श्रीलंका एवं इंडोनेशिया जैसे देश इसके सदस्य थे।

1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति काफी तेजी से बदली। सोवियत संघ का अस्तित्व खत्म हो गया और उससे 15 नए

## अमेरिका में भारत की मौजूदगी चीन की चिंता बड़ी



बीच काफी टकराहट देखने को मिली थी, लेकिन उन तमाम विवादों से आगे बढ़ते हुए चीन ने अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चीन ने अमेरिका में निवेश किया और लगातार वहां पैर पसार रहा है। लेकिन, हाल में अमेरिका में भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चीन की पेशानी पर बल आने शुरू हो गए हैं। अमेरिकी कंपनियों में भारतीय मूल के प्रमुखों की बढ़ती संख्या चीन की बेचैनी का सबब बनती जा रही है। हाल में सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सीईओ पद पर सत्या नडेला को नियुक्त किया। नडेला के अलावा पेप्सीको की इंद्रा नूड, ड्यूरा बैंक के अंशु जैन और मास्टर कार्ड बैंक के अजय बंगा पहले से ही पश्चिमी देशों में अपनी सफलता का झंडा बुलंद कर चुके हैं।

हालिया रिपोर्ट, चीन क्यों नहीं दे पा रहा विश्वस्तरीय सीईओ-में कहा गया है कि चीन के मुकाबले भारतीय पश्चिमी देशों में आने के लिए अधिक इच्छुक हैं। वहीं, चीनी लोगों को घरेलू स्तर पर रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध हैं। नतीजतन, चीनी नागरिक अपना मुल्क को छोड़ना अच्छा नहीं समझते। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में प्रबंधन स्तर पर लोगों को लगभग एक लाख 31 हजार डॉलर तक सालाना मिलते हैं। भारत की तुलना में यह चार गुना अधिक है। भारत में यही वेतन औसतन 35 हजार डॉलर के करीब है। चीनी नागरिकों के देश न छोड़ने की एक वजह यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों में वहां का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। वहां हर तरफ अवसर हैं। चीन खुद शीर्ष स्तर पर योग्य

देशों का जन्म हुआ। इसके बाद अमेरिका दुनिया का एकमात्र सुपर पावर रह गया। चूंकि अन्य देशों की अर्थव्यवस्था भी चरमराने लगी थी, ऐसे में गुटनिरपेक्ष समूह के सदस्यों का भी रुझान अमेरिका की ओर बढ़ने लगा। यहीं पहली बार भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक सुधारों का सहारा लिया और अपने बाज़ार दुनिया के लिए खोल दिए। सोवियत संघ और गुटनिरपेक्षता से बदल कर उसका झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ने लगा। आज स्थिति यह है कि भारत-अमेरिका के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच कर 63.7 अरब

डॉलर से भी अधिक का हो गया है। भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में प्रगाढ़ता से पड़ोसी देश चीन में बेचैनी का आलम देखा जा रहा है। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में तेजी से सामरिक और आर्थिक स्तर चीन के उभार को देखते हुए यह हवा बनने लगी थी कि चीन के रूप में एक नए सुपर पावर का अस्तित्व दुनिया में आ रहा है। चीन ने भी इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन ने आर्थिक तौर पर अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने की पहल भी की है। डॉलर और चीनी मुद्रा युआन को लेकर दोनों देशों के

सोवियत संघ और गुटनिरपेक्षता से बदल कर भारत का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ने लगा। आज स्थिति यह है कि भारत-अमेरिका के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच कर 63.7 अरब डॉलर से भी अधिक का हो गया है। भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में प्रगाढ़ता से पड़ोसी देश चीन में बेचैनी का आलम देखा जा रहा है।

अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में चीनी नागरिकों का बाहर जाना बेहद अव्यवहारिक लगता है। चीन के बनिस्बत भारत में स्थिति विपरीत है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक विकास दर काफी प्रभावित हुई है। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो वह भी पटरी से उतरी हुई थी, लेकिन अचानक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के दुरुस्त होने के बाद भारत के साथ उसके संबंधों में एक नई ऊंचाई देखने को मिली है। यह बात भी चीन को चुभ रही है। अमेरिका में भारत के प्रभाव पर चीन की चिंता की एकमात्र वजह यही नहीं है। दरअसल, साल 2013 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 12 से अधिक भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों को व्हाइट हाउस में अहम पदों पर नियुक्त किया। अगर जानकारों की मानें, तो ओबामा प्रशासन में काम करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों की संख्या 50 से भी अधिक है। ये सभी किसी देश के लिए अमेरिका की नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा राजनयिक बांबी जिंदल एवं डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी कमला हैरिस जैसी महत्वपूर्ण शक्तियंत अमेरिका में भारत की उपस्थिति को मजबूती से पेश कर रही हैं। ऐसे में चीन की चिंता लाजिमी है और चीन भी अपनी इस चिंता को बखूबी जानता-समझता है।

चंद्रबाबु नायडू

feedback@chauthiduniya.com

साई



साई की दृष्टि मात्र से ही हमारे कर्म-बंधन दूर हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है. गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गंगा भी संतों के आगमन की सदैव उत्सुकतापूर्वक राह देखा करती है.

रूपकंड:



# भक्तों के पालनहार

चौथी दुनिया ब्यूरो

हमें साई बाबा का सदा प्रेमपूर्वक स्मरण करना चाहिए. साई बाबा सदैव अपने भक्तों के कल्याण के लिए तत्पर तथा आत्मलीन रहते थे. उनका स्मरण करने से जीवन और मृत्यु की पहली सुलझ जाती है. ईश्वर के अवतार का ध्येय साधुजनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना है, लेकिन संतों का कार्य तो सर्वथा भिन्न है. संतों के लिए साधु और दुष्ट प्रायः एक समान हैं. संतों को प्रथम चिंता दुष्टों की होती है और वे उन्हें सही पथ पर लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं. साई भक्तों के कष्ट दूर करते

साई के ग्यारह वचन

- 1- जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
- 2- चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
- 3- न्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
- 4- मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
- 5- मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
- 6- मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
- 7- जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
- 8- भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
- 9- आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
- 10- मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
- 11- धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.



साई बाबा सभी प्राणियों से समान प्रेम करते थे. उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा एवं भिक्षुक सब एक समान थे. भक्तों के लिए उन्होंने अपने दिव्य चमत्कार का प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे. उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच भी नहीं सकता था. यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हैं, तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और न उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंच सकीं. तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था. बहुत सारे लोगों को साई बाबा के दर्शन की अभिलाषा थी, लेकिन उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक दर्शन का कोई मौका प्राप्त न हो सका.

चमत्कार का प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे. उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच भी नहीं सकता था. यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हैं, तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और न उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंच सकीं. तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था. बहुत सारे लोगों को साई बाबा के दर्शन की अभिलाषा थी, लेकिन उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक दर्शन का कोई मौका प्राप्त न हो सका. बाबा के दर्शन से वंचित रहने वाले

भक्त यदि उनकी लीलाओं का श्रवण करें, तो दर्शन की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है. साई बाबा की लीला अपरंपार थी. वह जिसे चाहते थे, वही उनके पास अधिक दिनों तक ठहर सकता था. अगर किसी की इच्छा होती भी थी, तो उसे बाबा किसी न किसी बहाने वहां से वापस भेज देते थे. साई बाबा धन्य हैं. उनके दर्शन मात्र से भक्तों की अज्ञानता दूर हो जाती है और वह संसार के उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जिससे वह वंचित रहता है. उनका क्षण मात्र भी अवलोकन करने से भक्तों के पूर्व जन्मों के समस्त पापों का नाश हो

जाता है और उसे सुखों की प्राप्ति होती है. साई की दृष्टि मात्र से ही हमारे कर्म-बंधन दूर हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है. गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गंगा भी संतों के आगमन की सदैव उत्सुकतापूर्वक राह देखा करती है. शिरडी में भी साई बाबा अपने भक्तों की राह देखते हैं कि वे उनके दर्शनों के लिए कब आते हैं. शिरडी के साई बाबा के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया  
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा  
(जाँतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश,  
पिन-201301  
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

सप्तम ज्योतिर्लिंग नागेश्वर

# शिव की महिमा अपरंपार

धर्मेन्द्र सिंह

नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक विश्वविख्यात प्रसिद्ध मंदिर है. यहां भगवान शिव का सातवां ज्योतिर्लिंग स्थापित है. यह मंदिर गुजरात राज्य में द्वारकापुरी से 17 किमी की दूरी पर स्थित है. हिंदू धर्म के अनुसार, नागेश्वर को नागों का ईश्वर कहा जाता है. रुद्र संहिता में नागेश्वर को दारुकावने नागेश कहा गया है. पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन की महिमा का बखान है. मान्यता है कि जो भी श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति और माहात्म्य की कथा सुनेगा, उसे उसके सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी और अंत में समस्त सुखों का भोग करते हुए उसे भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी.

नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में मान्यता है कि सुप्रिय नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और शिव का अनन्य भक्त था. वह निरंतर शिव की आराधना, पूजन और ध्यान में लीन रहता था. अपने सारे कार्य वह भगवान शिव का नाम लेकर करता था. मन, वचन, धर्म, कर्म से वह पूर्णतः शिव में लीन रहता था. उसकी इस शिव भक्ति को देखकर एक दारुक नामक राक्षस उससे बहुत द्वेष रखता था. राक्षस को भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार से अच्छी नहीं लगती थी. वह निरंतर इस प्रयत्न में लगा रहता था कि सुप्रिय की पूजा-अर्चना में किसी भी तरह विघ्न पहुंचाया जाए. एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी उस दुष्ट राक्षस दारुक ने अवसर का लाभ उठाते हुए नौका पर आक्रमण कर दिया. उसने नौका पर सवार सभी यात्रियों को पकड़ कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया. सुप्रिय कारागार में भी अपने नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने लगा और अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिवभक्ति की प्रेरणा देने लगा. दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर कारागार में आ पहुंचा. सुप्रिय भगवान शिव के चरणों में दोनों आंखें बंद किए हुए ध्यान लगाए बैठा था. उस राक्षस ने उसकी मुद्रा देखकर अत्यंत क्रोधित होकर तेज आवाज में उससे कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहां कौन से उपद्रव और षडयंत्र करने की बातें सोच रहा है? उसके इतना क्रोध करने के बाद भी धर्मात्मा शिवभक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई. अब तो वह राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा. उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय



एवं अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया. सुप्रिय उसके इस आदेश से तनिक भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ. वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा. उसे यह पूर्ण विश्वास था कि उसके आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से उसे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे. उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान भोले नाथ उसी क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर एक चमकते हुए सिंहासन पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए. उन्होंने सुप्रिय को दर्शन देने के साथ-साथ उसे अपना अस्त्र भी दिया, जिससे वह राक्षस दारुक और उसकी सेना का वध करके शिवधाम चला गया. भगवान शिव के आदेश से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा.

कैसे जाएं:- अगर आप नागेश्वर जाना चाहते हैं, तो सड़क, रेल, हवाई मार्ग से जा सकते हैं. नागेश्वर जाने के लिए अहमदाबाद और जामनगर से सीधे बसें मिलती हैं. रेल मार्ग से जाने के लिए आप देश के किसी प्रमुख स्टेशन से ट्रेन द्वारा द्वारका जाएं. वहां से टैक्सी, बस अथवा ऑटो से

feedback@chauthiduniya.com

रूपकंड

## एक रहस्यमयी झील



विनीता यशस्वी

रूपकंड उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक झील है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5029 मीटर है. रूपकंड उच्च हिमालयी क्षेत्र में हिमालय की त्रिशूल और नंदाघुंटी पर्वत शृंखलाओं की गोद में बसा है. रूपकंड विश्वविख्यात पर्यटन स्थल होने के साथ ही उत्तराखंडवासियों के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल भी है, जहां हर वर्ष सितंबर माह में नंदा देवी यात्रा का आयोजन होता है और प्रत्येक बारह वर्षों में नंदा राजजात यात्रा का आयोजन किया जाता है. यह झील साल के ज्यादातर महीनों में जमी ही रहती है. रूपकंड अपने चारों ओर बिखरे हुए मानव कंकालों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इस झील को रहस्यमयी बनाते हैं. 1960 में वैज्ञानिकों द्वारा इन कंकालों की कराए गए कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये मानव कंकाल 12वीं सदी से 15वीं सदी के हैं. यहां मानव शरीर, कपड़े, जूते, बर्तन आदि कई तरह के अवशेष मिलते हैं. इन कंकालों की लंबाई 10 फीट तक नापी गई है. हालांकि मानव कंकालों की संख्या निश्चित नहीं है, फिर भी एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 500 के आसपास है, जो अचानक हुई ओलावृष्टि के शिकार हो गए थे.

इन कंकालों के विषय में कुछ लोक कथाएं भी प्रचलित हैं. उनमें से एक लोककथा के अनुसार, ये अवशेष कन्नौज के राजा यशोधवल, उनकी पत्नी, बच्चों, परिवार के अन्य सदस्यों एवं उनके साथ आए दूसरे यात्रियों के हैं. कहा जाता है कि उन्होंने यहां आने पर राजजात के नियमों एवं मर्यादा का पालन नहीं किया, जिसके चलते उन्हें देवी के गुस्से का शिकार होना पड़ा था. दूसरी लोककथा के अनुसार, ये अवशेष कन्नौज के राजा जसधवल के हैं, जो यहां नंदा राजजात के दौरान आया था और साथ में नर्तकियों को भी लाया था. जब नर्तकियों ने नृत्य शुरू किया, तो देवी ने उन्हें पत्थर बना दिया, जिस कारण इस जगह को पाथर नचनियां कहा जाता है. राजजात में राजा की पत्नी को प्रसव भी हुआ, जिस कारण देवी नाराज हो गईं और दंड स्वरूप उन्होंने एक बर्फीले तूफान द्वारा राजा की पूरी सेना नष्ट कर दी, वही अवशेष यहां पड़े हैं. आज भी वैज्ञानिक इस अनुसंधान रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं. रूपकंड जाने वाला रास्ता बेहद खूबसूरत है, जिसे रास्ते में पड़ने वाले बड़े-बड़े बुग्याल और भी खूबसूरत बना देते हैं. जुलाई से सितंबर के बीच यहां ब्रह्म-कमल के फूल भी दिखाई देते हैं. इसके अलावा, यह क्षेत्र कई किस्म की जड़ी-बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है. ■

feedback@chauthiduniya.com



## सोनी की एक्स एवी-712 बीटी

**का**

र चलाने में आसानी हो, इसके लिए सोनी ने इन-कार एवी सेंटर हेड यूनिट एक्सएवी-712 बीटी लॉन्च किया है। यह चालक को ड्राइविंग के दौरान म्यूजिक, नेविगेशन और एंड्रॉयड स्मार्ट फोन ऐप्स की सुविधा देती है। इसमें डबल-डिन मल्टीमीडिया सेंटर है, जो आसानी से स्मार्ट फोन से कनेक्ट हो सकता है। इसमें मिरर लिंक टेक्नोलॉजी है, जिससे एवी सेंटर हेड यूनिट के साथ स्मार्ट फोन की स्क्रीन दोनों ओर से कनेक्ट की जा सकती है। इसमें ऐप रिमोट वर्जन 2.0 का सपोर्ट है। इससे ड्राइविंग के दौरान इनकॉमिंग टेक्स्ट मैसेजिंग, ट्वीट्स और कैलेंडर रिमाइंडर भी आसानी से पढ़े जा सकते हैं। एमएचएल या एचडीएमएल टेक्नोलॉजी होने से यूजर हेड यूनिट डिस्प्ले के जरिये ऑडियो और वीडियो कंटेंट को एंजॉय कर सकता है। इसकी कीमत 27,995 रुपये है।



## सैमसंग की नई गैलेक्सी टैब सीरीज



**ये टैबलेट्स 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वाडकोर प्रोसेसर, 1.5 जीबी रैम और 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ हैं। 7 इंच गैलेक्सी टैब-4 में 8 जीबी वैरिएंट मॉडल का भी विकल्प मिलेगा।**

गैलेक्सी टैब-4 7.0 की बैटरी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। फोटोग्राफी के लिए 3 मेगा पिक्सल का मुख्य कैमरा और 1.3 मेगा पिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है।

**सै**मसंग ने गैलेक्सी टैब-4 सीरीज के तीन नए टैब पेश किए हैं, गैलेक्सी टैब-4 7.0, गैलेक्सी टैब-4 8.0, गैलेक्सी टैब-4 10.1। इन टैबलेट्स की स्क्रीन को छोड़ दें तो अन्य फीचर्स में कोई खास अंतर नहीं है। अलग-अलग स्क्रीन साइज के उक्त टैबलेट्स डब्ल्यूएक्सजीए (1280 गुणा 800 पिक्सल) डिस्प्ले रेजोल्यूशन पर काम करते हैं। ये टैबलेट्स 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वाडकोर प्रोसेसर, 1.5 जीबी रैम और 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ हैं। 7 इंच गैलेक्सी टैब-4 में 8 जीबी वैरिएंट मॉडल का भी विकल्प मिलेगा। माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए एक्सटर्नल मेमोरी को 64 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। सैमसंग के ये तीनों टैबलेट्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग 4.4 किटकेट आधारित हैं। पावर बैकअप के लिए गैलेक्सी टैब-4 10.1 में 6800 एमएच, गैलेक्सी टैब-4 8.0 में 4450 एमएच की बैटरी है। गैलेक्सी टैब-4 7.0 की बैटरी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। फोटोग्राफी के लिए 3 मेगा पिक्सल का मुख्य कैमरा और 1.3 मेगा पिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है। कनेक्टिविटी के लिए 3जी, एलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ की सुविधा है।



## बाजार में आया इलेक्ट्रिक स्कूटर

**इ**

लेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली जापानी कंपनी टैरा मोटर्स भारत सहित एशियन मार्केट में अपना नया स्टाइलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर ए-4000 आई लॉन्च करने वाली है। इस स्कूटर की खास बात यह है कि इसमें आईफोन इनबिल्ट किया गया है।

स्कूटर में आईफोन लगाने का मकसद उसे स्टेटस और नेविगेशन तकनीक के तौर पर इस्तेमाल करना है। ए-4000 आई अपनी तरह का ऐसा पहला स्कूटर होगा, जिसमें स्मार्ट फोन इनबिल्ट है।

उम्मीद है कि आईफोन के अलावा इसमें दूसरे स्मार्ट फोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनबिल्ट स्मार्ट फोन आपको

बैटरी स्टेटस, माइलेज और एवरेज स्पीड की जानकारी देगा।

कंपनी ने अपने इस स्कूटर में टैरा लिथियम इंडोन् बैटरी का इस्तेमाल किया है, जो इसे 50 हजार किमी तक चलने में मदद करती है। एक बार फुल चार्ज होने के बाद स्कूटर 65 किमी तक चलता है। स्कूटर की बैटरी 4.5 घंटे में फुल चार्ज की जा सकती है।

**भा**

रत की जानी-मानी स्मार्ट फोन कंपनी लावा ने क्यूपैड ई-704 नाम से टैबलेट लॉन्च किया है, इस टैबलेट की कीमत मात्र 9,999 रुपये है। लावा क्यूपैड ई-704 डुअल सिम वाला 3 जी टैबलेट है। इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वाडकोर ब्रॉडकोम प्रोसेसर है। इसमें खास तौर पर ग्राफिक्स इंजन आधारित वीडियोकार मल्टीमीडिया तकनीक का उपयोग किया गया है, जिस पर गेम, वेब ब्राउजिंग एवं इंटरटेनमेंट का लाभ उठाया जा सकता है। टैबलेट में 1024 गुणा 600 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 7.0 इंच का मल्टीटच आईपीएस स्क्रीन डिस्प्ले है। यह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग 4.2.2 जेलीबीन आधारित है।

इसमें 1 जीबी रैम, 4 जीबी इंटरनल मेमोरी के अलावा 32 जीबी तक एक्सपेंडेबल मेमोरी की भी सुविधा है। कनेक्टिविटी ऑप्शन के तौर पर टैबलेट में वाई-फाई, ब्लूटूथ, 2जी, 3जी एवं एज शामिल हैं। पावर बैकअप के लिए क्यूपैड ई-704 टैबलेट में 3,500 एमएच की बैटरी है। कंपनी के अनुसार, इसकी बैटरी 300 घंटे का स्टैंडबाई टाइम और 10 घंटे का टॉकटाइम देने में सक्षम है। फोटोग्राफी के लिए 3.2 मेगा पिक्सल रियर कैमरा एवं वीडियो कॉलिंग के लिए 0.3 मेगा पिक्सल कैमरा है। युवाओं में लोकप्रिय कुछ एप्लिकेशन एवं गेम भी इसमें प्री-लोडेड हैं, जैसे वीचैट, वाइबर, अस्पफाल्ट-7 एचडी आदि।

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

## लावा का सस्ता टैबलेट



## हाई स्पीड इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क



**इं**

टरनेट की स्पीड को लेकर परेशान नेट यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। जानी-मानी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल अब मोबाइल नेटवर्क के क्षेत्र में आ सकती है। दुनिया को सबसे सफल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और सच इंजन गूगल ने अब मोबाइल नेटवर्क के क्षेत्र में उतरने का फैसला लिया है। कंपनी अब खुद का वायरलेस नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रही है, जो यूजर को फोन करने, मैसेज भेजने और इंटरनेट के इस्तेमाल तक की सुविधा देगा। गूगल अमेरिका में पहले से ही सबसे तेज ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा मुहैया करा रही है। योजना के तहत गूगल मौजूदा मोबाइल नेटवर्क कंपनियों से ही 3 जी और 4 जी नेटवर्क खरीद कर उसे कम कीमत में यूजर तक पहुंचाएगी। ऐसे में गूगल एक वचुअल मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर (एमवीएनओ) की भूमिका में होगा। एक ऐसा नेटवर्क ऑपरेटर, जो मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों तक अपने सर्विस प्लान पहुंचाता है।

## महिंद्रा एक्सयूवी का नया मॉडल

**क**

ई कंपनियों के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपनी अपडेटेड बोलेरो का स्पेशल एडिशन बाजार में उतारा है। महिंद्रा स्कापियों और बोलेरो एक्सयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें हैं। महिंद्रा बोलेरो के इस स्पेशल एडिशन की सिर्फ 500 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी। नई अपडेटेड बोलेरो स्पेशल एडिशन के फीचर्स की बात करें, तो इसमें एबीएस, पल व्हाइट, स्पोर्ट्स बोडी लुक, यूरोपियन लेदर इंटीरियर, ब्लू विजन हेडलाइट्स, यूरोपियन लेदर सीट्स, ब्लूटूथ-यूएसबी कनेक्टिविटी, म्यूजिक सिस्टम आदि शामिल हैं। कंपनी ने इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है। यह 2.5 लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन, 62 एचपी पावर, 195 एनएम के टॉर्क एवं 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ काम करता है।

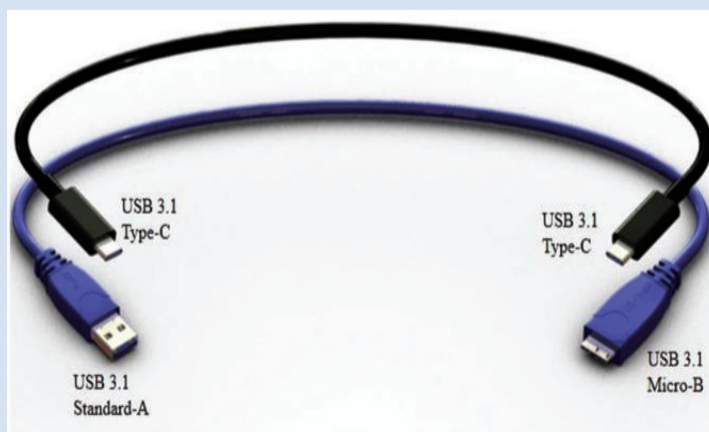


## दोतरफ़ा यूएसबी

इस यूएसबी को लागू करने वाले फोरम ने आशा व्यक्त की है कि नया डिजाइन जुलाई तक आएगा। मोबाइल फोन और कैमरा चार्ज करने के लिए प्रयोग में आने वाले टाइप-सी मानक का यह नया यूएसबी केबल आकार में मौजूदा माइक्रो-यूएसबी कनेक्टर जितना होगा।

**यू**

एसबी को गलत साइड से लगाने वाले लोगों को प्रतिदिन अड़चनों का सामना करना पड़ता है। इससे निजात दिलाने के लिए यूएसबी केबल का एक नया डिजाइन आया है। यूएसबी 3.1 टाइप-सी अपनी तरह का पहला ऐसा केबल होगा, जो



सीधे-उल्टे, दोनों तरफ से कनेक्ट किया जा सकेगा। इस यूएसबी को लागू करने वाले फोरम ने आशा व्यक्त की है कि नया डिजाइन जुलाई तक आएगा। मोबाइल फोन और कैमरा चार्ज करने के लिए प्रयोग में आने वाले टाइप-सी मानक का यह नया यूएसबी केबल आकार में मौजूदा माइक्रो-यूएसबी कनेक्टर जितना होगा। अब तक यह डाटा कनेक्शन के लिए कंप्यूटर या दूसरे उपकरणों में केवल एक ओर से लगाया जाता रहा है। नया यूएसबी केबल 100 वाट तक की ऊर्जा का ट्रांसफर कर सकेगा। इसके अलावा, यूएसबी 3.1 में 10 गीगाबाइट्स की गति से डाटा ट्रांसफर होगा।

## ट्रांसैंड ड्राइव प्रो-200

इसे फुल एचडी 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन और नाइट शूटिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।



**ड्रा**

इविंग करते समय हर स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए आप इस कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कार में लगे विंडशील्ड से जोड़कर फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। यही नहीं, इसे फुल एचडी 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन और नाइट शूटिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 2.4 इंच कलर्ड एलसीडी स्क्रीन, 160 डिग्री वाइड एंगल ग्लास लेंस, बिल्ट-इन माइक्रोफोन एवं स्पीकर, डॉट मूव फाइल फॉर्मेट में वीडियो रिकॉर्डिंग और 16 जीबी माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड जैसे फीचर्स हैं। यह 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है।

## शूमाकर की सेहत में सुधार



गत वर्ष दिसंबर में फ्रैंच आल्प्स में एक स्कीइंग दुर्घटना में जर्मन के फॉर्मूला वन चैंपियन शूमाकर (47) के सिर में गंभीर चोट लग गई थी, जिससे वह कोमा में चले गए थे और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। उनके प्रतिनिधि सेबाइन केम के अनुसार, शूमाकर की हालत में सुधार हो रहा है, डॉक्टरों की टीम उन्हें कोमा से बाहर लाने के लिए प्रयासरत है। केम ने कहा कि ग्रेनोबल में अस्पताल की टीम के साथ उनके इस लंबे और कठिन संघर्ष के दौरान हम सब साथ हैं। हम अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन उनसे यह समझने की उम्मीद भी करते हैं कि हम शूमाकर की हालत के बारे में बहुत विस्तार से कुछ नहीं बता सकते। पिछले महीने शूमाकर के परिवारियों ने कहा था कि उनकी स्थिति में मामूली, लेकिन आशाजनक सुधार के संकेत दिखाई दिए हैं। हादसे की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना का शिकार होने से पहले शूमाकर की गति अच्छे स्कीअर की रही होगी, फिर वह गिर गए और पत्थर से टकरा गए। विशेषज्ञों ने शूमाकर के स्कीइंग उपकरण और हेलमेट में लगे कैमरे की फुटेज के आधार पर दुर्घटना का दृश्य पुनर्निर्मित किया, ताकि कारणों का पता चल सके। फॉर्मूला वन रेसिंग में 19 साल के करियर के बाद शूमाकर 2012 में रिटायर हो गए थे। ■

## कैफ को सचिन-सहवाग से उम्मीद

कैफ को विश्वास है कि उनके उक्त वरिष्ठ सहयोगी चुनाव में उनकी मदद करेंगे, कैफ कहते हैं कि क्रिकेट ने मुझे देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने का मौका दिया, मैंने जब भी महाराष्ट्र या दक्षिणी राज्यों की यात्रा की, मुझे विकास के लिहाज से वे उत्तर प्रदेश से बेहतर नज़र आए।



कैफ की दुनिया से राजनीति में आए और कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मोहम्मद कैफ को सचिन तेंदुलकर, सीरव गांगुली एवं वीरेंद्र सहवाग जैसे प्रसिद्ध क्रिकेटर्स ने अपनी शुभकामनाओं से नवाजा है। कैफ को विश्वास है कि उनके उक्त वरिष्ठ सहयोगी चुनाव में उनकी मदद करेंगे। कैफ कहते हैं कि क्रिकेट ने मुझे देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने का मौका दिया, मैंने जब भी महाराष्ट्र या दक्षिणी राज्यों की यात्रा की, मुझे विकास के लिहाज से वे उत्तर प्रदेश से बेहतर नज़र आए। हमारे यहां खेलों के लिए आधारभूत ढांचे का अभाव है। कैफ कहते हैं कि वह अपने गृहराज्य और खास तौर से गृहनगर इलाहाबाद के लिए कुछ करना चाहता था, जहां खेलों की अनगढ़ प्रतिभाओं का खजाना है, जो प्रशिक्षण एवं कोचिंग की अच्छी सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अभी तक वह खुद को असहाय पाते थे और समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या करें, लेकिन अब लगता है कि उनके पास एक मंच है, जहां से वह अपने लोगों की सेवा कर सकते हैं। कैफ कहते हैं कि वह अपनी बल्लेबाजी की तरह राजनीति में भी काम करेंगे। भले ही बहुत सारे चौके-छक्के न लगा पाएं, लेकिन एक-दो रन बनाकर स्कोर बोर्ड गतिमान बनाए रखेंगे। ■



## मुझसे शादी कर लो!

रतीय क्रिकेटर्स के अभिनेत्रियों के साथ अफेयर के चर्चे हमेशा से रहे हैं। हाल में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की लव स्टोरी भी खूब चर्चा में रही है। अब इंग्लैंड की क्रिकेटर डानिएल वेट ने विराट कोहली को शादी का प्रस्ताव भेजा है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर डानिएल ने ट्वीट के जरिए कहा कि विराट कोहली, मुझसे शादी कर लो! हालांकि डानिएल के ट्वीट में कोहली के नाम की स्पेलिंग थोड़ी अलग थी। उनके ट्वीट के बाद जब कोहली के प्रशंसकों ने उन्हें बताया कि ऐसी चर्चा है कि कोहली बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को डेट कर रहे हैं, तो डानिएल ने जवाब में कहा कि नहीं, वह नहीं कर रहे। डानिएल के इस ट्वीट पर उनकी साथी क्रिकेटर कैथरीन ब्रंट ने भी चुटकी ली। ब्रंट ने ट्वीट किया, तुमने देर कर दी डानिएल, विराट ने मुझे पिछले हफ्ते ही प्रस्ताव भेजा है। शायद डानिएल को यह नहीं पता है कि अनुष्का शर्मा कौन हैं, लेकिन उनके ट्वीट ने सोशल मीडिया की दुनिया में हलचल ज़रूर मचा दी है। डानिएल की उम्र 22 साल है। वह ऑफ स्पिनर हैं और 32 एक दिवसीय और 50 ट्वेंटी-20 मैचों में इंग्लैंड की तरफ से खेल चुकी हैं। हालांकि वह अभी इंग्लैंड की महिला ट्वेंटी-20 टीम की सदस्य नहीं हैं। ■



संदीप सिंह को एचआईएल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रीय शिविर में भाग लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब टीम चुनने का समय आया, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पिछले साल भी उनके साथ यही बर्ताव किया गया था।

## सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए जगह नहीं



संदीप सिंह को एचआईएल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रीय शिविर में भाग लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब टीम चुनने का समय आया, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पिछले साल भी उनके साथ यही बर्ताव किया गया था। वह एचआईएल के पहले संस्करण के भी सर्वश्रेष्ठ स्कोरर थे। संदीप सिंह लंदन ओलंपिक में आखिरी स्थान पर रही भारतीय टीम में शामिल थे। खास बात यह है कि मुख्य कोच टैरी वालश ने एचआईएल के दूसरे सत्र में दिल्ली वेवराइडर्स की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले गुरबाज को टीम में शामिल किया है। ऐसे में चयन प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजिमी है। जब गुरबाज का चयन हो गया, तो उससे अच्छा खेलने वाले संदीप सिंह की उपेक्षा क्यों? ■

कि सी भी खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को महत्व दिया जाता है, वहीं भारतीय हॉकी टीम में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को जगह नहीं मिलती। हॉकी इंडिया लीग के दोनों संस्करणों में सबसे अधिक स्कोर बनाने वाले एक खिलाड़ी को बाहर रखने की वजह से कई सवाल उठने लगे हैं। बीते 23 जनवरी से 23 फरवरी तक हुए एचआईएल के दूसरे संस्करण में सबसे ज्यादा गोल करने वाले पंजाब वॉरियर्स टीम के हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह की चयनकर्ताओं ने एक बार फिर उपेक्षा की है। नीदरलैंड में 31 मई से होने जा रहे एचआईएल विश्वकप से पहले यूरोपीय दौर के लिए भारतीय हॉकी टीम में उनका चयन नहीं किया गया। खास बात यह है कि संदीप सिंह को एचआईएल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रीय शिविर में भाग लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब टीम चुनने का समय आया, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पिछले साल भी उनके साथ यही बर्ताव किया गया था। वह एचआईएल के पहले संस्करण के भी सर्वश्रेष्ठ स्कोरर थे। संदीप सिंह लंदन ओलंपिक में आखिरी स्थान पर रही भारतीय टीम में शामिल थे। खास बात यह है कि मुख्य कोच टैरी वालश ने एचआईएल के दूसरे सत्र में दिल्ली वेवराइडर्स की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले गुरबाज को टीम में शामिल किया है। ऐसे में चयन प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजिमी है। जब गुरबाज का चयन हो गया, तो उससे अच्छा खेलने वाले संदीप सिंह की उपेक्षा क्यों? ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

## कैंसर का मरीज बना फुटबॉल खिलाड़ी

कैंसर से पीड़ित एक युवक को चेचन्या की प्रमुख फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। रूस के एक राजनेता ने युवक के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, उसके बाद क्लब ने यह निर्णय लिया। तैरेक प्रोजनी फुटबॉल क्लब के मानद अध्यक्ष एवं चेचन्या के प्रसिद्ध क्षेत्रीय नेता रमजान कादरोव ने कहा कि वह गिगोरी सिमोनयान के बारे में जानकर बहुत दुःखी हुए। अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर 18 वर्षीय सिमोनयान की फोटो लगाकर कादरोव ने लिखा कि उन्होंने फुटबॉल क्लब को सिमोनयान के इलाज का खर्च उठाने को भी कहा है। कादरोव का इंस्टाग्राम एकाउंट बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने लिखा कि पूरी तरह ठीक होने पर गिगोरी क्लब के लिए खेल सकेगा। ठीक होने में भगवान उसकी मदद करें। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद सिमोनयान का इलाज जर्मनी में किया जाएगा। सिमोनयान को पिछले साल सितंबर में अपनी बीमारी के बारे में पता चला। उसके तुरंत बाद उनका एक ऑपरेशन भी हुआ। ■



## 7 फुटबॉलर गिरफ्तार



रत क्रिकेट में फिक्सिंग को लेकर परेशान है और इसके चलते काफी किरकिरी भी हो चुकी है, लेकिन इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी भी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों से पीछे नहीं हैं। इंग्लैंड के उत्तरी-पश्चिमी फुटबॉल लीग के सात खिलाड़ियों को कथित रूप से स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) के अनुसार, इन सभी फुटबॉलर्स की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है। इनमें से 6 को पिछले साल दिसंबर में भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए थे। अभी तक कुल 13 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और स्पॉट फिक्सिंग व मनी लांड्रिंग में उनकी संलिप्तता को लेकर पूछताछ की जा रही है। बावजूद इसके इंग्लैंड फुटबॉल में फिक्सिंग रुक नहीं रही है। ■



भारतीय दर्शकों के दिलों पर राज कर रहीं अभिनेत्री कटरीना कैफ लोकसभा चुनाव के लिए मतदान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। दरअसल, वह हांगकांग में पैदा हुईं, जबकि उनके पास नागरिकता है इंग्लैंड की और उन्हें कामयाबी मिली भारत में। कटरीना की मां ब्रिटिश मूल की हैं और पिता भारतीय कश्मीरी।

## बॉलीवुड के सितारे, जो नहीं दे पाएंगे वोट

प्रियंका प्रियम तिवारी

feedback@chauthiduniya.com

**बॉ** लीवुड सितारों और भारत की राजनीति के बीच गहरे संबंध हैं। ये सितारे कभी चुनाव में किसी पार्टी विशेष का प्रचार, तो कभी जनता को मतदान के लिए जागरूक करते नज़र आते हैं और तो कभी खुद किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते नज़र आते हैं। बॉलीवुड सितारों की लोकप्रियता मतदान को प्रभावित करती है। जनता कई बार अपने लोकप्रिय सितारे को जिताने के लिए पार्टी को भी नज़रअंदाज़ कर देती है। वह वोट देने समय सिर्फ अपने पसंदीदा कलाकार को देखती है। लेकिन, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके कई पसंदीदा कलाकार मतदान नहीं कर पाएंगे। बॉलीवुड के कई सितारे, जिन्हें दर्शकों ने तहेदिल से स्वीकार किया, जिन्हें दौलत-शोहरत सब कुछ दिया, लेकिन वे लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। क्यों? पढ़िए चौथी दुनिया की यह रिपोर्ट...

### कटरीना कैफ

कटरीना कैफ बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं। ऐश्वर्या के बाद दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद किया। अपनी सभी समकालीन अभिनेत्रियों को कटरीना ने पीछे छोड़ दिया। यह जानकर हैरानी होगी कि आपकी चहेती स्टार कटरीना मतदान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। वह हांगकांग में पैदा हुईं, जबकि उनके पास नागरिकता है इंग्लैंड की और उन्हें कामयाबी मिली भारत में। कटरीना की मां ब्रिटिश मूल की हैं और पिता भारतीय कश्मीरी। उनकी मां एक वैरिटेबल संस्था में काम करती थीं, ऐसे में उन्हें दुनिया भर में घूमना पड़ता था। हर दो साल बाद कटरीना का परिवार किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाता था। भारतीय नागरिकता के मुद्दे पर एक इंटरव्यू में उन्होंने विवादास्पद बयान देते हुए राहुल गांधी को भी लपेट लिया था। उन्होंने कहा था, मैं जो हूँ, उसमें बहुत खुश हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को इससे समस्या क्या है? मैंने कभी यह बात नहीं छिपाई कि मेरी मां ब्रिटिश मूल की हैं। क्या मुझे इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि मैं आधी एशियन हूँ और आधी यूरोपियन? राहुल गांधी भी आधे भारतीय और आधे इटैलियन हैं, उसी तरह मैं आधी भारतीय हूँ, तो इसमें गलत क्या है? ■



### नरगिस फाकरी

अमेरिका की टॉप मॉडल नरगिस फाकरी ने इमिग्रेशन अली की फिल्म रॉकस्टार से बॉलीवुड में एंट्री की। पहली ही फिल्म में वह मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में थीं और उनके अपोजिट थे बॉलीवुड के रणबीर कपूर। नरगिस ने काफी मेहनत की और अब तो वह हिंदी सीखने के लिए भी काफी मेहनत कर रही हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड ने अब उन्हें अपना लिया है, पर वह भी लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पिता पाकिस्तानी एवं उनकी मां चेक गणराज्य की हैं और नरगिस का जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में। ■

### आलिया भट्ट

महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी आलिया भट्ट इन दिनों बॉलीवुड में एक के बाद एक फिल्मों में कर रही हैं, लेकिन आलिया वोट नहीं दे पाएंगी, क्योंकि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। दरअसल, उनकी मां सोनी राजदान ब्रिटिश मूल की हैं और आलिया भी ब्रिटेन में ही पैदा हुई थीं। वह चाहती हैं कि उन्हें भारत की नागरिकता भी मिल जाए, जिससे वह अगली बार मतदान जरूर कर सकें, लेकिन आलिया को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत में अभी तक दोहरी नागरिकता की मान्यता नहीं है।

## पूरब को ट्रेवलिंग पसंद है

पूरब कोहली ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2003 में फिल्म यूं ही से की थी। वो लम्हे और रॉक ऑन समेत दर्जनों फिल्मों में काम किया, लेकिन वे उनके करियर के लिए खास साबित नहीं हुईं। हालिया रिलीज फिल्म जल में वह मुख्य भूमिका में नज़र आए। इसमें पानी की विकराल समस्या को दिखाया गया है। कच्छ के दो गांव, जहां दूर-दूर तक पानी का नामोनिशान नहीं है, वहां पानी के लिए मारपीट तक हो जाती है। फिल्म में बक्का बने पूरब कोहली पानी के देवता माने जाते हैं, क्योंकि वह ज़मीन में कान लगाकर सुनते हैं और बता देते हैं कि किस जगह खुदाई करने से पानी निकलेगा। उनकी अधिकतर भविष्यवाणी सही साबित होती है। पूरब इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। पूरब को घुमना काफी पसंद है। वह कहते हैं कि अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग लोगों से मिलकर उन्होंने ज़िंदगी की असल किताब पढ़ी है। पूरब ने अपने ट्रेवल शो के दौरान पूरा देश घूमा। वह कहते हैं कि यही वह चीज है, जो ज़िंदगी को समझने का मौका देती है। पूरब अभी तक मणिपुर, त्रिपुरा एवं मिजोरम नहीं गए हैं, पर अगले पांच सालों में उनकी वहां भी जाने की योजना है। वह मानते हैं कि घूमने के लिए कच्छ सबसे बढ़िया जगह है। वहां के लोग, वहां का कल्चर, रहन-सहन, ऐसा लगता है, मानो भगवान ने एक बहुत बड़ा सेट डिजाइन किया हो। अपनी फिल्म जल के बारे में वह कहते हैं कि जल की कहानी जितनी प्रभावी है, उतना ही दमदार उनका किरदार भी है। बक्का सीधा-सादा है, लेकिन एक इंसान के तौर पर उसमें भी कुछ कमियां हैं। वह भी गलतियां करता है। पूरब का सपना था कि वह पायलट बनें, लेकिन यह आसान नहीं था। वे सोचते कि अगर उन्हें जांब नहीं मिली तो? वजह, 1995-96 के दौर में एयरलाइंस ज्यादा नहीं थीं, इसलिए यह सपना उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। पढ़ाई में उनका मन ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन हार्डवर्क से वह नहीं घबरते। और



तो और, वह 11वीं कक्षा में एक बार फेल भी हो चुके हैं, पर वह निराश नहीं हुए। उन्होंने फिर मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास हुए। ■

### फिल्म प्रीत्यु

#### रिवाँल्वर रानी

फिल्म क्वीन में एक सीधी-सादी लड़की की भूमिका में अपने अभिनय का लोहा मनवाने के बाद कंगना अब फिल्म रिवाँल्वर रानी में नज़र आएंगी। यह एक कॉमेडी फिल्म है। इसके लेखक और डायरेक्टर साई कबीर हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं कंगना रानावत और वीर दास, जबकि सह-कलाकार हैं पीयूष मिश्रा, जाकिर हुसैन और पंकज सारस्वत। चंबल का नाम आते ही उन डाकुओं की याद आती है, जो जमींदारों एवं साहूकारों को लूटते थे। उन डाकुओं को अंग्रेज बागी कहते थे, क्योंकि उनमें भी देशभक्ति का जज्बा कूट-कूट का भरा था। वे क्रांतिकारियों की मदद करते थे। वे

डायरेक्टर : साई कबीर श्रीवास्तव  
प्रोड्यूसर : राजू चड्ढा, नितिन तेज आहूजा एवं राहुल मिश्रा  
कलाकार : कंगना रानावत, पीयूष मिश्रा, वीर दास, जाकिर हुसैन  
भाषा : हिंदी  
रिलीज : 25 अप्रैल, 2014



उन्हें असलमे, गोला-बारूद ही मुहैया नहीं कराते थे, बल्कि मौका पड़ने पर शरण भी देते थे। वे राजनीति में भी खासे सक्रिय थे। उसी चंबल की डाकु है अलका गुर्जर, जिसे लोग रिवाँल्वर रानी कहते हैं। रिवाँल्वर रानी ग्वालियर की राजनीति में सक्रिय है और उसके अपोजिट है तोमर पार्टी। रिवाँल्वर रानी का एक डबॉयफ्रेंड भी है, जो बॉलीवुड का हीरो बनने की ख्वाहिश रखता है। फैशनबल रिवाँल्वर रानी के कपड़े इटली से आते हैं। वह कहती भी है, हम हैं अलका सिंह, आई लव फैशन, फन एंड गन। इस फिल्म के लिए कंगना ने काफी मेहनत की है। उन्होंने भाषा से लेकर बंदूक चलाने तक का अभ्यास किया। फिल्म में कंगना बुंदेली मिश्रित हिंदी बोलती हैं। फिल्म की शूटिंग चंबल में की गई है। ■

### जैकलिन फर्नांडीज

मिस श्रीलंका जैकलिन फर्नांडीज ने भी बॉलीवुड को अपना घर मान लिया है। कई फिल्मों में अभिनय और आइटम डांस करके तारीफ बटोर चुकी जैकलिन अब जल्द ही अपना घर बसाने वाली हैं फिल्म निर्माता साजिद खान के साथ। साजिद जानी-मानी कोरियोग्राफर एवं फिल्म निर्माता फ़राह खान के भाई हैं। भारत जैकलिन की कर्मभूमि है और शायद उनका भविष्य भी, पर वह मतदान नहीं कर पाएंगी। दरअसल, उनके पिता श्रीलंका के हैं, जबकि मां केनेडियन एवं मलेशियन। जैकलिन जन्मी और पली-बड़ी बहरीन में हैं। हालांकि जैकलिन पूरी तरह खुद को श्रीलंका मूल की मानती हैं। ■



### इमरान खान

एक तरफ अभिनेता आमिर खान देश में जागरूकता लाने के लिए कई प्रयासों से जुड़े हैं। वह देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके भांजे इमरान खान 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमरान के पास अमेरिका की नागरिकता है। इमरान कहते हैं कि अगर वह अमेरिका की नागरिकता वापस करके भारत की नागरिकता लेते हैं, तो उन्हें एडवांस में दस साल का टैक्स चुकाना होगा। ■



### शकीरा नहीं करेंगी पुरुषों के साथ काम

कोलंबियन पॉप सुपरस्टार शकीरा अब किसी म्यूजिक वीडियो में किसी गैर-मर्द के साथ धरकती नज़र नहीं आएंगी यानी अपनी अदाएं नहीं दिखाएंगी। उन पर यह प्रतिबंध लगाया है उनके पार्टनर जेराई पीके ने। शकीरा ने हाल में बताया कि पीके को उनके किसी पुरुष के साथ म्यूजिक वीडियो में काम करने पर आपत्ति है। 37 वर्षीय शकीरा ने हाल में गाविका रिहाना के साथ एक नया म्यूजिक वीडियो शूट किया है। इस वीडियो में शकीरा और रिहाना अपने सेक्सि अवतार में नज़र आ रही हैं और इसमें दोनों के काफी इंटिमेड सींस हैं। जब उनसे पूछा गया कि अपने इस वीडियो में उन्होंने एक महिला के साथ काम क्यों किया? तो शकीरा ने बताया कि दरअसल, उनके पति पीके को उनका किसी पुरुष के साथ काम करना पसंद नहीं है। न्यूज वेबसाइट डिजिटल स्पॉट के मुताबिक, शकीरा ने कहा कि दरअसल, पीके थोड़े ईश्यालु स्वभाव के हैं और इसीलिए उन्होंने उन्हें दूसरे पुरुषों के साथ शूटिंग करने की इजाजत नहीं दी। रिहाना के साथ शूटिंग के लिए भी उन्होंने पीके से बात की और उनके हां कहने पर ही रिहाना के साथ काम किया। वह कहती हैं कि पीके उनसे बेहद प्यार करते हैं और उन्हें लेकर थोड़े पजेसिव एवं जेलस भी हैं। हालांकि पीके ने यह बात कभी खुलकर नहीं कही, लेकिन वह उनके जज्बातों को समझती हैं। शकीरा और पीके 2011 से साथ हैं और दोनों का 15 महीने का एक बेटा भी है। पीके स्पेन और एफसी बार्सिलोना की फुटबॉल टीम से खेलते हैं। ■



# पौथी दनिया

21 अप्रैल-27 अप्रैल 2014

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

## बिहार-झारखंड

**प्राइम गोल्ड**  
Fe-500+  
टी.एम.टी. हुआ पुराना!  
टी.एम.टी. 500+ का अब आया जगाना!  
सिर्फ स्टील नहीं, प्योर स्टील  
MFG: CITY ROLLING MILLS PVT. LTD. PATNA  
हिंदी क्वॉटरलिफ़ एवं डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें: 0612-2216770, 2216771, 8405800214



# दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा

**सू** बे की छह सीटों पर वोटों ने अपना फैसला सुना दिया है. लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने यह साबित कर दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी कितनी आस्था है. मतदान केंद्रों पर उमड़ी भारी भीड़ यह एहसास करा गई कि लोकतंत्र की जड़ यहां कितनी गहरी है. तमाम अगर-मगर के बीच लोगों ने जमकर वोट डाले और अपना फैसला इंडीएएम में केंद्र कर दिया. मीरा कुमार, निखिल सिंह, उषेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जैसी हस्तियों की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया. अब अगले चरणों में भी डेर सारी हस्तियों की किस्मत का फैसला होना है.

छह विधानसभा वाले हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में सात मई को चुनाव होना है. यह सीट सुरक्षित है. देश भर के पर्यवेक्षकों की नजर इस सीट पर है. लोजपा सुप्रिमो व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यहां से प्रत्याशी हैं. वहीं जदयू ने इस बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास को मैदान में उतारा है और कांग्रेस की तरफ से संजीव टोनी यहां से उम्मीदवार हैं. फिलहाल दास ही यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. 1977 में यह सीट सुरक्षित घोषित हुई और रामविलास पासवान पहली बार यहां से सर्वाधिक मतों के अंतर से जीते. पहली बार पासवान ने कांग्रेस के बालेश्वर राम को चार लाख से अधिक मतों से हराया था. रामसुंदर दास और पासवान लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे हैं. पासवान यहां का सात बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं वहीं दास दो बार यहां से निर्वाचित हो चुके हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से सात बार जीते रामविलास पासवान को रामसुंदर दास ने लगभग सैंतिस हजार मतों के अंतर से हराया था. नीतीश ने एकबार फिर दास पर ही दांव खेला है. बताया जाता है कि यह सीट खुद नीतीश के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई है लेकिन इसबार दास का रास्ता आसान नहीं है. भाजपा से अलगाव के बाद से जिस जनाधार का नुकसान जदयू को हुआ है उसका खामियाजा दास को इसबार भुगतना पड़ेगा वहीं पासवान भाजपा के साथ हैं और इसबार उन्हें अपनी छवि के साथ साथ नमो की लहर का भरोसा है. यहां के वोट मान रहे हैं कि इस बार रामविलास पासवान का केंद्र में मंत्री बनना तय है इसलिए उन्हें ही अपना सांसद बनाया जाए ताकि हाजीपुर का विकास फिर से पटरी पर आ सके और यह संसदीय क्षेत्र देश दुनिया के पटल पर चमक सके. कांग्रेस के संजीव टोनी को राजद के आधार वोट पर भरोसा है. टोनी को यादव वोटों का आसरा है.

सारण लोकसभा सीट पर सात मई को चुनाव होना है. देश भर की निगाहें इस सीट पर इसलिए है कि हर कोई देखना चाह रहा है कि आखिर लालू के बाद कौन? लालू पहली बार 1977 में यहां से चुने गए और 2013 में चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी. राजद की तरफ से लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी यहां से उम्मीदवार हैं वहीं भाजपा ने एक बार फिर राजसभा सदस्य व पार्टी के महासचिव राजीव प्रताप रूडी को उम्मीदवार बनाया है. जदयू ने यहां से सलीम परवेज को मैदान में उतारा है. राजीव पिछले दो लोकसभा



का मत नहीं मिलने की आशंका है. वहीं वैशाली लोकसभा क्षेत्र भी हाई प्रफाईल सीट माना जा रही है. यहां से केंद्रीय मंत्री रह चुके रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के उम्मीदवार हैं. जदयू ने यहां से विजय सहनी को उतारा है वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से लोजपा ने यहां से रामा सिंह को मैदान में उतारा है. 1996 से रघुवंश प्रसाद सिंह यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और अब तक उन्होंने ही यहां का प्रतिनिधित्व किया है. बीते लोकसभा चुनावों को अगर देखें तो हर बार यहां सीधा मुकाबला हुआ करता था बावजूद इसके रघुवंश जीतते रहे हैं. पिछले लोकसभा में उनका मुकाबला जदयू उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला से हुआ था और उस समय उन्हें कड़ी टक्कर मिली थी. रामा सिंह विधायक रह चुके हैं. उन्हें भाजपा के आधार वोट और राजपूत वोट पर आस है. उन्हें इम्मीद है कि इस बार भूमिहार और राजपूत मिलकर उन्हें वोट देंगे. लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है. इस संसदीय क्षेत्र का इतिहास रहा है कि राजपूत और भूमिहार हमेशा एक-दूसरे के विरोध में ही वोट करते रहे हैं. जानकारों की माने तो ऐसा पहली बार 94 में हुआ था जब लवली आनंद चुनाव लड़ी थीं. मतों के लिहाज से देखें तो यहां राजपूत, भूमिहार, अतिपिछड़ा और कुर्मी मतदाताओं की संख्या अधिक है. जदयू के उम्मीदवार विजय सहनी को अतिपिछड़े और कुर्मी मतदाता का ही भरोसा है और इसी समीकरण ध्यान में रखकर वृषिण पटेल भी यहां से टिकट मांग रहे थे. पटेल यहां से दो बार चुनाव लड़ चुके हैं. जदयू के उम्मीदवार के लिए बुरी खबर यह है कि इस बार यहां से अनु शुक्ला भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं. यह नुकसान जदयू को ही होने वाला है. भागलपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव 24 अप्रैल को होना है. भाजपा की तरफ से शाहनवाज हुसैन यहां से उम्मीदवार है. वहीं राजद ने बूलो मंडल और जदयू ने राजद से आए अबू कैसर को उम्मीदवार बनाया है. वर्तमान में शाहनवाज ही यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. नए परिसीमन की वजह से विपूर और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र इस संसदीय क्षेत्र में जुड़ा है और दोनों विधानसभा क्षेत्र भूमिहार बहुल है साथ ही यह माना जाता है कि यहां के भूमिहार भाजपा समर्थित हैं. वहीं इस संसदीय क्षेत्र शहरी और आसपास के इलाके में वैश्य मतों की संख्या भी अच्छी है. वहीं मुस्लिम मतों की संख्या भी अच्छी है. भाजपा को शाहनवाज की व्यक्तिगत छवि की वजह से थोड़ा बहुत मुस्लिम मत भी मिलता रहा है. शाहनवाज के साथ पेशानी यह है कि इस बार इसे जदयू का आधार मत नहीं मिलेगा. जदयू ने अबू कैसर को अपना उम्मीदवार बनाया है. कैसर को मुसलमान मतों के साथ साथ जदयू के आधार वोट का सहारा है और जदयू के आधार वोटों की संख्या अच्छी मानी जाती है. अबू कैसर दंगा पीड़ितों के बीच काफी सक्रिय भी रहे हैं जिसका उन्हें फायदा मिल सकता है लेकिन राजद ने यहां से बूलो मंडल को उम्मीदवार बनाकर जदयू को पेशानी में डाल दिया है. मंडल अति पिछड़ी समुदाय के गंगोता जति से आते हैं. इस जाति से पहली बार किसी को उम्मीदवार बनाया गया है. साथ ही मंडल को राजद के आधार मतों का भरोसा है. फिलहाल यहां की लड़ाई त्रिकोणीय ही दिख रही है. कटिहार बिहार के इन जिलों में से है जहां मुसलमानों की आबादी चालीस फीसदी से ज्यादा है लेकिन पिछले

**भागलपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव 24 अप्रैल को होना है. भाजपा की तरफ से शाहनवाज हुसैन यहां से उम्मीदवार हैं. वहीं राजद ने बूलो मंडल और जदयू ने राजद से आए अबू कैसर को उम्मीदवार बनाया है. वर्तमान में शाहनवाज ही यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. नए परिसीमन की वजह से विपूर और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र इस संसदीय क्षेत्र में जुड़े हैं.**

तमाम अगर-मगर के बीच लोगों ने जमकर वोट डाले और अपना फैसला इंडीएएम में केंद्र कर दिया. मीरा कुमार, निखिल सिंह, उषेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जैसी हस्तियों की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया. अब अगले चरणों में भी डेर सारी हस्तियों की किस्मत का फैसला होना है.

तीन चुनाव से भाजपा के निखिल कुमार चौधरी का इस सीट पर कब्जा है. भाजपा की तरफ से इस बार भी चौधरी ही यहां से उम्मीदवार हैं. केंद्र में मंत्री और रांकपा के तारिक अनवर के आ जाने से इस सीट पर पूरे देश की नजर है. तारिक को पिछले तीन लोकसभा चुनाव से यहां से हार का सामना करना पड़ रहा है. तारिक 1980, 84, 96 और 98 में यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं. यूपीए गठबंधन के तहत मात्र एक सीट कटिहार ही रांकपा के हिस्से में आई है. वर्तमान सांसद को अपनी छवि के साथ साथ भाजपा के वोट बैंक और नमो की लहर का भरोसा है. पिछले चुनाव में निखिल ने तारिक को 14 हजार से ज्यादा मतों से हराया था वहीं लोजपा के अशफाक करीम को 45 हजार मत मिले थे. निखिल को जहां जदयू के आधार मतों के खोने का खतरा है वहीं लोजपा का मत इनके पाले में आने की संभावना है. तारिक महाराष्ट्र के कोटे से राज्यसभा सदस्य हैं और केंद्र में मंत्री हैं. उन्हें भरोसा है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने कटिहार के विकास के लिए जो कार्य किया है उसका फायदा मिलेगा. वहीं जदयू ने यहां से पूर्व विधायक प्रो. रामप्रकाश महतो को मैदान में उतारा है. महतो कटिहार सदर से विधायक और राजद सरकार में मंत्री रह चुके हैं. महतो को अपनी छवि के साथ साथ नीतीश के विकास पुरुष वाली छवि और जदयू के कैडर का भरोसा है. लेकिन यहां समस्या है कि मनियारी के पूर्व विधायक मुबारक हुसैन के बेटे हमिद मुबारक भी जदयू से टिकट चाह रहे थे लेकिन इन्हें निराशा हाथ लगी. इसका खामियाजा महतो को इठाना पड़ सकता है. तारिक को भरोसा है कि इन्हें राजद के आधार वोट के साथ साथ यहां मुसलमान मतों की संख्या अच्छी है और मुसलमान समुदाय से अकेले उम्मीदवार हैं

**नया खून है, खौलेगा !**  
**अब इन्डिया ग्लो करेगा !**  
**आप स्वस्थ, इन्डिया स्वस्थ !**  
**आज की नारी शक्ति का प्रतीक**  
**आईरोफॉल्विन**  
सिप  
**पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक**  
• रक्त बढ़ाए • शक्ति दे • सौंदर्य निखारे

Helpline No. : 09431021238, 09430285525, 08544128054 सभी मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध [www.shrinivaslabs.co.in](http://www.shrinivaslabs.co.in)

**क्योरफास्ट क्रीम**  
फोड़े, फुन्सी, दाद, खाज एवं खुजली के स्थान में कीटाणुओं को नष्ट कर आराम पहुँचाता है।

Helpline No. : 09431021238, 09430285525, 08544128054 सभी मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध [www.shrinivaslabs.co.in](http://www.shrinivaslabs.co.in)







# चौथी दुनिया

21 अप्रैल-27 अप्रैल 2014

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

## उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड



# दिग्गजों की लड़ाई



फोटो : प्रभात पाण्डेय

कांग्रेस-भाजपा-सपा-बसपा आदि दलों ने लोकसभा चुनाव की विसात पर कई मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों को उतारा है, वहीं ऐसे नेताओं पर भी दांव लगाया गया है, जो पिछला लोकसभा/विधानसभा चुनाव जीत नहीं सके थे. देश की दो प्रमुख पार्टियों कांग्रेस-भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रमशः सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह के अलावा, राहुल गांधी, रीता बहुगुणा जोशी, वरुण गांधी, जगदंबिका पाल, पीएल पुनिया, बेनी प्रसाद वर्मा, स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास, बाहुबली ब्रज भूषणशरण सिंह, अतीक अहमद, रिजवान जहीर, पुराने और कांग्रेसी नेता जफर अली नकवी और जावेद जाफरी जैसे सितारे भी इसी क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं.



अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की सियासी विसात पर अवध का डंका अलग बजता है. भौगोलिक रूप से अवध की जो परिभाषा तय की जाती है, उसके अनुसार अवध में 17 जिले (अंबेडकर नगर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, इलाहाबाद, कौशांबी, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव) आते हैं. अगर यह कहा जाए कि यूपी और उसमें भी खासकर अवध क्षेत्र ने देश को आजादी के बाद हिन्दुस्तान की सियासत को कई आंदोलन और तमाम प्रधानमंत्री दिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. अवध की जमीं से जीत कर पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी ने देश-दुनिया में भारत का नाम खूब रोशन किया. आजादी के बाद सबसे अधिक समय देश पर राज करने वाले नेताओं की सूची में उक्त नेताओं के नाम अग्रणी हैं. सियासत से अलग अवध भगवान राम की जन्मस्थली है, तो आदिकाल की लक्ष्मण नगरी (आज का लखनऊ), जिसे कालांतर में नवाबों के शहर के नाम से भी पहचाना गया. अवध क्षेत्र ने अपने जीवन में कई सियासी और सामाजिक उतार-चढ़ाव देखे.

आजादी के बाद देश की सियासत और जातिगत तानाबाना हिला कर रख देने वाला राम मंदिर और नौकरियों में आरक्षण आंदोलन यहीं की उपज था, जिसे मंडल-कमंडल के नाम से खूब सुर्खियां मिली थी. कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में अयोध्या मंदिर का ताला खुलने के बाद अस्सी के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिन्दूवादी संगठनों ने राम मंदिर आंदोलन की अलख जगाई, तो भाजपा के हिन्दुत्व के वेग को रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के लिए सामाजिक समरसता को दांव पर लगा दिया. मंडल की आग में पूरा देश झुलस गया. आरक्षण समर्थकों और विरोधियों के बीच सड़क पर तांडव होने लगा. युवा सड़कों पर आत्मदाह करने लगे. भाजपा को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने से राजनैतिक नुकसान होते दिखने, तो इस समय के भाजपा के लौहपुरुष लालकृष्ण आडवाणी इसकी काट के लिए सोमनाथ से रामरथ लेकर चल पड़े. 'राम लला हम आएं और मंदिर वहीं बनाएं' के उद्घोष ने आग पर पानी डालने का काम किया. भाजपा की राजनीति इसके बाद उबाल पर आई और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि विवादित दांचा नेस्तेनाबूद नहीं कर दिया गया.

अवध में इस बार भी कई नामचीन नेता, प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार, सिने स्टार आदि दिग्गज भाग्य आजमा रहे हैं. अवध के 17 जिलों की सभी लोकसभा सीटों पर विभिन्न दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है. कांग्रेस-भाजपा-सपा-बसपा आदि दलों ने लोकसभा चुनाव की विसात पर कई मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों को उतारा है, वहीं ऐसे नेताओं पर भी दांव लगाया गया है, जो पिछला लोकसभा/विधानसभा चुनाव जीत नहीं सके थे. देश की दो प्रमुख पार्टियों कांग्रेस-भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रमशः सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह के अलावा, राहुल गांधी, रीता बहुगुणा जोशी, वरुण गांधी, जगदंबिका पाल, पीएल पुनिया, बेनी प्रसाद वर्मा, स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास, बाहुबली ब्रज भूषणशरण सिंह, अतीक अहमद,

रिजवान जहीर, पुराने और कांग्रेसी नेता जफर अली नकवी और जावेद जाफरी जैसे सितारे भी इसी क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं.

समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर नगर सीट से राममूर्ति वर्मा को प्रत्याशी बनाया है. राममूर्ति वर्मा इसी जिले की अकबरपुर सीट से विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. गोंडा सीट से नंदिता शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है, जो इसी जिले की गुजेहना सीट से विधायक हैं. मित्रसेन यादव फैजाबाद संसदीय सीट से सपा प्रत्याशी हैं और जिले की ही बीकापुर सीट से विधायक हैं. ऐसे ही अभिषेक मिश्र लखनऊ सीट से राजनाथ के मुकाबले सपा के उम्मीदवार हैं. जबकि वह लखनऊ उत्तर सीट से विधायक व प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री हैं. कैसरगंज लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित भी गोंडा सदर सीट से विधायक हैं.



अमेठी में अभिनय से राजनीति में आई स्मृति ईरानी और लखनऊ में फिल्मी कलाकार जावेद जाफरी के मैदान में कूदने से अवध इलाके की दोनों सीटों (अमेठी और लखनऊ लोकसभा सीट) पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है. भाजपा ने स्मृति ईरानी को अमेठी में राहुल गांधी के मुकाबले उतार दिया है, वहीं आम आदमी पार्टी कवि से नेता बने कुमार विश्वास के सहारे राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं. अमेठी में कुमार विश्वास घर लेकर परिवार के साथ रहने भी लगे हैं, ताकि उन पर बाहरी होने का दाग नहीं लगे. उत्तर प्रदेश में मोदी की लहर चल रही है. इससे अवध भी अछूता नहीं है. मोदी के चलते भाजपा को अवध में बड़ी कामयाबी की उम्मीद है. ■

भाजपा ने भी अवध इलाके के अपने दो विधायकों कलराज मिश्र व सावित्रीबाई फुले को मैदान में उतारा है. कलराज मिश्र लखनऊ पूर्व सीट से विधायक हैं. इन्हें देवरिया सीट से पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया है. वहीं सावित्रीबाई फुले को बहराइच सुरक्षित लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार है. वह जिले की बलहा सुरक्षित सीट से विधायक हैं. कांग्रेस ने भी अवध क्षेत्र के अपने दो विधायकों को मैदान में उतारा है. रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट सीट से विधायक हैं. बहराइच जिले की प्रयागपुर सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव को पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है.

भाजपा, बसपा और कांग्रेस ने ऐसे नेताओं पर भी दांव लगाया है, जो बीते विधानसभा के चुनाव में ही पराजित हो गए थे. बसपा के कद्दावर नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे लालजी वर्मा को पार्टी ने श्रावस्ती लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है. पिछला विधानसभा चुनाव वह अपने गृह जनपद अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से हार चुके हैं. नकुल दुबे को लखनऊ लोकसभा सीट से बसपा ने प्रत्याशी बनाया है. वह भी पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे. इनको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और सपा के अभिषेक मिश्रा तथा आम आदमी पार्टी के अभिनेता प्रत्याशी जावेद जाफरी से कड़ी टक्कर मिल रही है. कांग्रेस की प्रदेश

अध्यक्ष रहीं रीता बहुगुणा जोशी के घर पर आगजनी के आरोपी जितेंद्र सिंह बबलू को बसपा ने फैजाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है. यहां मित्रसेन यादव सपा के टिकट से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री को टक्कर देने के लिए भाजपा ने लखू सिंह को प्रत्याशी बनाया है. वह पिछला विधानसभा चुनाव अयोध्या विधानसभा सीट से हार गए थे. श्रावस्ती लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दहन मिश्रा भी पिछला चुनाव श्रावस्ती जिले की भिनगा विधानसभा सीट से हार गये थे.

कैसरगंज से भाजपा ने बाहुबली ब्रज भूषण शरण सिंह को मैदान में उतारा है. इनका मुकाबला अखिलेश सरकार के मंत्री विनोद उर्फ पंडित सिंह से है. कांग्रेस के लिए अबकी से सुल्तानपुर लोकसभा सीट आसान नहीं रह गई है. कांग्रेस प्रत्याशी अमीता सिंह अमेठी विधानसभा सीट से पिछला

इलाके का चुनाव दिलचस्प हो गया है. सोनिया गांधी रायबरेली से और राहुल बगल की अमेठी सीट से पहले से ही चुनाव लड़ते रहे हैं. नई इंड्री के रूप में सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सोनिया गांधी के भतीजे वरुण गांधी भाजपा प्रत्याशी हैं. इनका मुकाबला यहां के निवर्तमान सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह से है.

अनीता सिंह कांग्रेस के टिकट से मैदान में हैं. अमेठी में अभिनय से राजनीति में आई स्मृति ईरानी और लखनऊ में फिल्म कलाकार जावेद जाफरी के मैदान में कूदने से अवध इलाके की दोनों सीटों (अमेठी और लखनऊ लोकसभा सीट) पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है. भाजपा ने स्मृति ईरानी को अमेठी में राहुल गांधी के मुकाबले उतार दिया है, वहीं आम आदमी पार्टी कवि से नेता बने कुमार विश्वास के सहारे राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं. अमेठी में कुमार विश्वास घर लेकर परिवार के साथ रहने भी लगे हैं, ताकि उन पर बाहरी होने का दाग नहीं लगे. उत्तर प्रदेश में मोदी की लहर चल रही है. इससे अवध भी अछूता नहीं है. मोदी के चलते भाजपा को अवध में बड़ी कामयाबी की उम्मीद है. ■

feedback@chauthiduniya.com

## चौथी दुनिया

आवश्यकता है  
संवाददाता, विज्ञापन  
प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com  
ajaiup@chauthiduniya.com  
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा  
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301,  
PH : 120-6450888, 6451999



